खण्ड–500, अंक–8
गुरुवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1939
(13 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–8
प्रश्नोत्तर	9–40
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	40–41
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में समाना पंछी विहार की भूमि अधिग्रहण की अवशेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम–आनन्दपुर, मउरा हुलासखेड़ा से कनकहा तक खड़न्जा पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आनन्द स्वरूप वार्ड–59, सिविल लाइन्स में रख–रखाव व सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ग्राम–समरी व किशनपुर के मध्य नाले पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
जनपद मेरठ के लौटी (सफियाबाद) के पास काली नदी पर पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड ईसानगर के ऐरा शुगर मील के श्रमिकों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद आगरा की पेयजल की समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	43–44
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपिया को 100 शैय्या का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बा में परिवहन डिपो न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	44–45
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अकबरपुर अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के पूरब टन्ना–मन्ना गांव के पास शारदा सहाय नहर पर बनी पैदल पुलिया के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में	45

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर स्थित अमराहट कैनाल योजना का द्वितीय चरण चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत बरही बम्बा से शहीदनगर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं एवं रामपुर रोडवेज बसों का बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	46–47
पूर्व मा0 सदस्य विधान सभा एवं अधिकारियों के नाम से आवंटित गैराज किराये पर धोबियों, नाईयों, वस्त्र विक्रेताओं आदि को अधिपत्य प्रदान किये जाने से व गैराज में सरकारी बिजली, पानी एवं आवास के रूप में प्रयोग किये जाने दूसरे मा0 सदस्यों को कथित गैराज आवंटित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति में औचित्य का प्रश्न	47–48
विधान सभा की ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली के अन्तर्गत मा0 सदस्यों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पूछने की सुविधा सप्ताह के सातों दिन चौबीस घण्टे उपलब्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	48–49
आय–व्ययक पर साधारण चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	49–50
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	50–51
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	51–63
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	64–114
सदन की कार्यवाही कम से कम 6 बजे तक चलाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	114–115
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा ...	115–127
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	127–129
जनपद उन्नाव सदर में नगर निगम का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर	129–130

विषय	पृष्ठ–संख्या
नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय लालगंज अझारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत 50 बेड के मैटरनिटी विंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	130–131
जनपद अम्बेडकर नगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	131–132
जनपद सीतापुर में राशन कार्ड बनाने में हुई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	132
जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद उटवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	132–135
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं सुश्री अदिति सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	135–136
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाई व मुफ्त इलाज न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	136–137
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	137–138
जनपद पीलीभीत में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के	1
अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	38–139
जनपद बदायूं के ग्राम नाधा दफतोरी और बिनावर को ब्लाक बनाये	139–140

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जाने के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–376

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'', कुंवर गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमतीबहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा,श्रीकानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्रीमहाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
31. अवतार सिंह भडाना, श्रीमुजफ्फरनगर
32. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
35. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
36. असलम अली, श्री हापुड़
37. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
38. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
39. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
40. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई

43. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
44. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
46. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उज्जवल रमण सिंह, श्रीइलाहाबाद
50. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
53. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
54. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
58. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
59. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
60. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
61. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
62. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
63. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
64. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
65. काली प्रसाद, श्री देवरिया
66. किशन लाल राजपूत, श्रीपीलीभीत
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केसर सिंह, श्री बरेली
72. कैलाश नाथ शुक्ल, श्रीबलरामपुर
73. कैलाश नाथ सोनकर, श्रीवाराणसी
74. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
75. गंगा, श्री कुशीनगर
76. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
77. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
78. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गौरी शंकर, श्री जालौन
81. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
82. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
83. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
84. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
85. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जयमंगल, श्री महाराजगंज
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
94. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
95. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
96. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
97. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
98. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
99. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर

100. तेजपाल सिंह नागर,श्री गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
104. दल बहादुर, श्री रायबरेली
105. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
106. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
107. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
108. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
112. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
116. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
119. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
120. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
121. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्रीरायबरेली
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
123. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
124. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'श्री इलाहाबाद
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्रीफर्रुखाबाद
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलम करवरिया, श्रीमतीइलाहाबाद
137. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
141. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
142. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
147. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
148. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
149. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
150. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
151. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
152. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
153. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
154. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद

155. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
156. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
157. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
158. फागू चौहान, श्री मऊ
159. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
160. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
161. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
162. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
163. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
164. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
165. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
166. बिमला सिंह सोलंकी,श्रीमती बुलन्दशहर
167. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
168. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
169. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
170. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
171. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
172. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
173. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
174. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
175. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
176. भगवती प्रसाद सागर,श्री कानपुर नगर
177. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
178. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
181. मनोज कुमार पाण्डेय, श्रीरायबरेली
182. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
183. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
184. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
185. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
186. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्रीरायबरेली
187. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
188. महबूब अली, श्री अमरोहा
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
191. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
192. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
193. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
194. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
195. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
196. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
197. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
198. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
199. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
200. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
201. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
202. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्रीइलाहाबाद
203. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
204. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
205. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
206. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
207. यासर शाह, श्री बहराइच
208. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
209. योगेश धामा, श्री बागपत
210. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
211. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ

धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
214. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
215. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
216. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
217. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
218. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
219. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
220. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
221. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
222. रवि शर्मा, श्री झांसी
223. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
224. राकेश कुमार गोस्वामी, श्रीमहोबा
225. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
227. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
228. राकेश सिंह बघेल,श्री सन्तकबीर नगर
229. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
230. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
231. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
232. राजबाला, श्रीमती रामपुर
233. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
234. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
235. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
236. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायू
237. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
238. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
239. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
241. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
242. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
243. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
244. राम अचल राजभर,श्री अम्बेडकर नगर
245. रामकुमार वर्मा, (पटेल), श्री खीरी
246. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
247. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
248. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
249. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
250. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
251. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
252. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
253. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
254. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
255. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
256. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
257. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
258. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
259. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
260. रितेश कुमार गुप्ता, श्रीमुरादाबाद
261. रितेश पाण्डेय, श्रीअम्बेडकर नगर
262. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0लखनऊ
263. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
264. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
265. लाखन सिंह, श्री औरैया
266. लाल जी वर्मा, श्रीअम्बेडकर नगर
267. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी

268. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
269. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
270. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
271. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
272. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
273. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
274. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
275. विजय कुमार कश्यप,श्री मुजफ्फरनगर
276. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
277. विजय मिश्र, श्री भदोही
278. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
279. विनय शंकर तिवारी, श्रीगोरखपुर
280. विनय शाक्य, श्री औरैया
281. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
282. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
283. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
284. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
285. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
286. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
287. वीर विक्रम सिंह, प्रिंसशाहजहांपुर
288. वीरेन्द्र, श्री एटा
289. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
290. शरद कुमार अवस्थी, श्रीबाराबंकी
291. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
292. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
293. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
294. शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
295. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
296. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
297. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
298. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
299. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
300. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
301. शोभा सिंह चौहान, श्रीमतीफैजाबाद
302. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
303. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
304. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
305. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
306. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
307. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
308. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
309. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
310. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
311. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
312. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
313. संजय, श्री बुलन्दशहर
314. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
315. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
316. संजय प्रताप जायसवाल, श्रीबस्ती
317. संजय यादव, श्री बलिया
318. संजय सिंह गंगवार, श्रीपीलीभीत
319. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
320. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
321. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
322. संजू देवी, श्रीमतीअम्बेडकर नगर
323. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
324. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
325. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
326. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
327. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर

328. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
329. सत्यपाल सिंह राठौर, श्रीकासगंज
330. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
331. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
332. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
333. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
334. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
335. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
336. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
337. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
338. सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
339. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
340. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
341. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
342. सुनील कुमार शर्मा, श्रीगाजियाबाद
343. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
344. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
345. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट,श्री बहराइच
346. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
347. सुरेन्द्र, श्री बलिया
348. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्रीवाराणसी
349. सुरेश कुमार, श्री शामली
350. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्रीशाहजहांपुर
352. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीलखनऊ
353. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
354. सुरेश राही, श्री सीतापुर
355. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
356. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
357. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
358. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
359. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
360. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
361. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
362. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
363. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
364. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
365. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
366. सौरभ सिंह, श्री खीरी
367. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
368. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
369. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
370. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
371. हरीराम, श्री सोनभद्र
372. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
373. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
374. हाकिम लाल बिन्द, श्रीइलाहाबाद
375. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
376. हृदय नारायण दीक्षित, श्रीउन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज

एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, मुलिस्म वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

¤11.00, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0–01

श्री अध्यक्ष–

(मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर) अब अगला प्रश्न

प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना

''**1–श्री पारसनाथ यादव (अनुपस्थित)–**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं उद्यान (श्री दारा सिंह चौहान)–

जी हां।

प्रदेश में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं इसके अन्तर्गत प्रख्यापित विभिन्न नियम प्रभावी हैं जिनके प्राविधानों का अनुपालन कराये जाने हेतु नियमानुसार नियमित रूप से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रदूषण का मुख्य स्रोत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट का असुरक्षित निस्तारण किया जाना आदि है।

औद्योगिक जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समस्त औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इनका नियमित अनुश्रवण किया जाता है। आसवनी इकाइयों, एग्रो आधारित पेपर इकाइयों में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण के प्राविधान प्रभावी हैं। घरेलू जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रदेश में कुल 68 सीवेज उपचार संयंत्र संचालित हैं।

वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण, बायोमास जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण आदि हैं। वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रदेश के कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, फिरोजाबाद शहरों में वाहनों में प्रयोग हेतु स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति की जा रही है। औद्योगिक वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रदेश में स्थापित प्रमुख वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में नियमानुसार आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें एवं चिमनियों की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इन इकाइयों का नियमित अनुश्रवण करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। निर्माण कार्यों से जनित डस्ट प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्माण कार्य के दौरान यथावश्यक जल छिड़काव किये जाने के निर्देश भवन निर्माण परियोजनाओं को दिये जाते हैं। प्रदेश में बायोमास बर्निंग पर्यावरण विभाग के शासनादेश दिनांक 28–10–2015 द्वारा प्रतिबन्धित की गयी है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रदेश में 03 सामूहिक निस्तारण सुविधायें स्थापित एवं संचालित हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाली इकाइयों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रदेश में 20 सामूहिक निस्तारण सुविधायें स्थापित हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले संस्थानों के अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है।

प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, वरूणा, काली, रामगंगा, सई, हिण्डन, गोमती, सरयू, यमुना, घाघरा, राप्ती आदि की जल गुणता का अनुश्रवण 53 चिन्हित स्थलों पर किया जाता है जिसमें नदी जल में घुलित आक्सीजन, बी0ओ0डी0, टोटल कोलीफार्म आदि प्रचालकों का मापन कराया जाता है।

प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रदेश के 21 शहरों में 62 चिन्हित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है जिसके अन्तर्गत पार्टिकुलेट मैटर–10, सल्फर–डाई–आक्साइड एवं नाइट्रोजल–डाई–आक्साइड की मात्रा का मापन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद एवं नोएडा नगरों में सतत् परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय ध्वनि गुणता के अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रदेश के 15 शहरों में परिवेशीय ध्वनि गुणता के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त लखनऊ नगर की परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण कार्य हेतु 10 स्थलों पर सतत् ध्वनि गुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ख)

तांराकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दूना करने के संबंध में रोडमैप

'1–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज एवं आमदनी को बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय आगामी 05 वर्षों में दोगुना किये जाने हेतु 08 बिन्दुओं पर रोडमैप तैयार किया गया है, जो निम्नवत् है –

1–प्रदेश के रेन फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार।

2–मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शत–प्रतिशत किसानों में वितरण।

3–पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों पर प्रभावी नियंत्रण।

4–खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) हेतु प्रोत्साहन।

5–किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाना।

6–फसल बीमा।

7–खेती के साथ मत्स्य एवं पशुपालन आदि व्यवसाय अपनाने पर जोर।

8–कृषि विविधीकरण।

इस संबंध में कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

(1) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश की सभी मण्डियों में ई–नेम व्यवस्था मण्डी समितियों में हो रहे क्रय विक्रय को कैशलेस करना, किसानों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

(2) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग–फल, शाकभाजी, पुष्प एवं मसाला फसलों के क्षेत्रफल आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु पाली हाउस/शेडनेट हाउस तकनीक आधारित हाई वैल्यू सब्जियों/फूलों की खेती, औषधीय एवं सगंध फसलों की खेती, मौसम आधारित बीमा योजना में अधिक औद्योगिक फसलों का अच्छादन, विकास खण्ड स्तर पर शीतग्रहों की व्यवस्था, फल पट्टियों का विकास, उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाना तथा फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम सम्मिलित है।

(3) खाद्य एवं रसद विभाग–शासन द्वारा निर्धारित क्रय एजेन्सियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीद तथा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों को भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय शाही साहब बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य भी हैं और शायद ही सरकार के मंत्रियों में कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो अपनी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आज इस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं तो हम लोगों ने उम्मीद यह की थी क्योंकि सरकार बार–बार यह बयान देती है कि हमने अपने संकल्प पत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही है। 5 साल में हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। तमाम वादे किसानों से चुनाव से पहले किए गए लेकिन आज स्थिति कुछ दूसरी है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिए।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, उसी पर आ रहा हूं। आज स्थिति कुछ दूसरी है। आज जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज चाहे किसी भी वर्ग का किसान क्यों न हो, आज किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, दर–दर भटकने को मजबूर है।

(विरोध स्वरूप सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा शोर की स्थिति उत्पन्न)
(शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास भारत सरकार की एक सूची है।

श्री अध्यक्ष–

आपसे चूक यह हो रही है कि आप सूचनाएं दे रहे हैं, आप प्रश्न करिए।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मेरे पास भारत सरकार की एक सूची है जिसमें समर्थन मूल्य दिया है, 2017–18 का भी समर्थन मूल्य है और 2016–17 का भी समर्थन मूल्य है। उसमें अगर पैडी धान की फसल में आपने केवल 5.4 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी की, ज्वार में केवल 4.6 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई, बाजरा में केवल 7.1 प्रतिशत की हुई, मक्का में 4.3 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। अगर इस अनुपात में आप बढोत्तरी कर रहे हैं और हर साल किसान की लागत बढ़ रही है चाहे वह खाद हो, चाहे बीज हो, सिंचाई के साधन आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी ने पिछले सत्र में जवाब दिया था कि हमारे पास हर खेत में पानी पहुंचाने का कोई साधन नहीं है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, आ रहा हूं मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। सरकार यह बता दे कि यदि इसी प्रतिशत में सरकार समर्थन मूल्य को बढ़ाएगी...

श्री अध्यक्ष–

आप अपने आधार पर कुछ जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अभी एक भी प्रश्न नहीं किया है। तीन मिनट हो गया है और आपने पूछा कुछ नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। माननीय कृषि मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि इस अनुपात में यदि बढ़ेगा तो किसान की आमदनी दुगुनी होनी नहीं है। हर साल जो किसान की लागत बढ़ रही है उसके संबंध में क्या आप यह घोषणा सदन में कर सकते हैं या करेंगे कि जो खाद, बीज, सिंचाई और बिजली आदि पर किसान की लागत आती है, क्या उन सब पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने की सरकार घोषणा करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इन्होंने जो कल्पना की है। कल्पनातीत यह सवाल है। सबसे पहले तो मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा था प्रदेश का इस साल का उसमें सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र के ऊपर 67682 करोड़ रूपये का प्राविधान पहली बार किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) विगत सरकार का यदि अंतर लिया जाए 37790 करोड़ रुपये का ज्यादा प्राविधान किया गया है। यह प्राविधान इस बात का संकेत करता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों के उन्नयन और उनके विकास की दृष्टि से बहुत बड़े कदम उठाये जाने वाले हैं और 36000 करोड़ रूपये की जो हम लोगों ने उनकी ऋण माफी की जो उनके ऊपर आर्थिक दबाव था और आर्थिक बोझ की वजह से वह जो पूंजी–निवेश नहीं कर पा रहे थे आज उनको अपने कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश करने की एक बेहतर सुविधा प्राप्त हुई। इनको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक की रिकार्ड गेहूं की खरीद हमारी सरकार ने की है। (मेजों की थपथपाहट) 36 लाख 999 हजार क्विंटल का और 6000 करोड़ रूपये से ऊपर का हम लोग भुगतान कर चुके हैं। यह पहली बार हुआ है। यह पूरे प्रदेश में खरीदारी हुई बिना किसी अनियमितता और बिना किसी शिकायत के और इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न खरीदा गया उनको तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो अभी उन्होंने चर्चा की है विगत 5 वर्षों में जब प्रदेश के भीतर आपकी सरकार रही है तो किसानों की सलाना आमदनी 16300 से लेकर 16600 वार्षिक के भीतर रही है आज हम उसको गति देने का संकल्प लेकर के आए हैं और जिसके लिए विविधीकरण की जो विभिन्न परियोजनाएं आपके सामने हमने रखी हैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी में अगले वर्षो के भीतर इजाफा होने वाला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लाल जी वर्मा आप पूछें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, अभी मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आ गया, आ गया, बड़ा विस्तृत जवाब आया है।

श्री नितिन अग्रवाल–

नहीं, नहीं जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब बिन्दुवार आ गया है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं माननीय अध्यक्ष जी। एक बार प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जवाब बिन्दुवार आ गया है। माननीय लाल जी वर्मा आप बोलें। आपके एक–एक प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय लाल जी वर्मा पहले पूछ लें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, उसके बाद मुझे एक बार मौका दे दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाना तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रति क्विंटल गेहूं, धान या किसानों के उत्पादन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मूल्य है, हमारे जो 3–4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उनमें गेहूं, धान का लागत मूल्य के आधार पर जो निर्धारित किया गया है क्या उसके सापेक्ष है ? लागत मूल्य पर लाभकारी मूल्य देने का जो वायदा सरकार ने किया था क्या लागत मूल्य जो हमारे कृषि विश्वविद्यालयों का, मैं एक ही फसल का पूछ लेता हूं कि गेहूं का जो लागत मूल्य है वह हमारे तीन–चारों विश्वविद्यालयों में क्या आता है, क्या उसमें 25 का दूना 50 प्रतिशत का लाभकारी मूल्य जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो लागत है वह लगभग 14 सौ से साढ़े 14 सौ रुपये प्रति कुंतल बैठती है। उस पर वृद्धि करके भारत सरकार तय करती है। पूरे देशभर की लागत का औसत आधार मान करके, कहीं पर लागत कम है और कहीं पर लागत ज्यादा है उसके आधार पर एक औसत न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत सरकार ने जो गेहूं की कीमत 1625 रुपये कुंतल तय की उसके अनुसार हम लोगों ने खरीदारी की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी आमदनी को दूना करना है उसमें लागत में कमी किया जाना एक उसका दूसरा हिस्सा है और प्रदेश सरकार इसके लिए विभिन्न जींसों पर सब्सिडी दे करके और हम बीज पर लागत घटाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्वायल हेल्थ कार्ड का परीक्षण करके उनकी भूमि का स्वायल टेस्टिंग करा करके जो उसमें आवश्यकता अनुरूप फर्टिलाइजर पड़े, जो पहले केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा जाता था उसमें कमी आए उसकी लागत को भी घटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में एक विस्तृत कार्य योजना जो हम लोगों ने बनायी है वह आपके सामने रखा है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लागत को घटा करके उत्पादन को बढ़ा करके, साथ–साथ में अच्छे तरीके से मार्केटिंग की व्यवस्था करके कृषि का विविधीकरण करके उद्यान, साग–भाजी की खेती व फलों–फूलों की खेती को बढ़ा करके वह आमदनी दूनी की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, अब तो उत्तर आ गया।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, तीनों कृषि विश्वविद्यालयों में केवल गेहूं का लागत मूल्य माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मूल प्रश्न आप देखें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दे दिया चूंकि माननीय मंत्री जी ने उस संबंध में उत्तर दिया है तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में मेरा यह प्रश्न बनता है अगर उत्तर नहीं दिया होता तो नहीं बनता था।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर तो दे दिया। नितिन जी, आप प्रश्न करिए।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप किसान की लागत घटाने की बात कर रहे हैं मेंथा के किसानों पर पहले 4 प्रतिशत वैट लगता था लेकिन जब से जी0एस0टी0 आया तब से 12 प्रतिशत की जी0एस0टी0 लगा दी। आपने टैक्स तो बढ़ा दिया किसान के ऊपर लाभ की बातें कर रहे हैं, चलिए यही बता दीजिए इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ?

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न यही किया है कि जी0एस0टी0 जो किसानों पर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर टैक्स 12 प्रतिशत कर दिया है क्या उस टैक्स में कमी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जी0एस0टी0 का कृषि मंत्रालय से कोई विशेष संबंध नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है जी0एस0टी0 का विषय वहां पर नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, आपने लागत की बात की कि आप लागत को कम करना चाहते हैं मैंने उसी पर पूछा कि क्या आप टैक्स को कम करके लागत को कम करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

कृषि मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का उत्तर आ गया। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की कार्य योजना

'02–श्री संजय गर्ग–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग बदहाली व बन्दी के कगार पर पहुंच चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में बुनकरों को बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें–

1–राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजनान्तर्गत व्यापक हथकरघा विकास योजना।

2–महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना।

3–पावरलूम कामगारों के लिये समूह बीमा योजना।

4–मेला एवं प्रदर्शनी।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें–

1–उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के अन्तर्गत मेगा परियोजना।

2–उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना।

3–जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना।

4–बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतन्त्र फीडर की व्यवस्था योजना।

5–हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना।

6–धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना।

7–हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों को सहायता।

8–पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति।

प्रस्तावित संशोधन वाली योजनायें–

1–राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के नाम परिवर्तन एवं योजना के प्राविधान में आंशिक संशोधन कर पं0 दीन दयाल राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना।

2–पावरलूम उद्योग विकास योजना के नाम में परिवर्तन एवं योजना के प्राविधान में आंशिक संशोधन कर मुख्य मंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना।

वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार बुनकरों को बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वस्त्रोद्योग, हथकरघा एवं रेशम उद्योग नीति 2017 भी प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग बन्दी और बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है परन्तु माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी नहीं जब कि अभी कुछ दिन पहले ही हथकरघा के तमाम व्यापारी माननीय मंत्री जी से मिले थे जीएसटी लागू होने के बाद तमाम व्यापारियों में बहुत ज्यादा असन्तोष हथकरघा उद्योग में लगे लोगों में हैं और वह इस बात का मुकाबला करने के लिए अपने आपको सक्षम नहीं पा रहे हैं और जितनी भी योजनायें माननीय मंत्री जी ने गिनाई वह तमाम योजनायें पुरानी सरकार की माननीय अखिलेश यादव सरकार की योजनायें हैं। केवल नई बोतल में पुरानी शराब परोसने की कोशिश करने का काम नाम परिवर्तित कर कर दिया गया और उसके आधार पर स्वयं माननीय मंत्री जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014, उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान, जनेश्वर मिश्र पावरलूम का विकास योजना के अन्तर्गत जितनी योजनायें थीं हथकरघा बुनकरों को।

श्री अध्यक्ष–

आप जानना क्या चाहते हैं माननीय मंत्री जी उत्तर के लिए तैयार हैं।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल इतना कहना है कि समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना.

श्री अध्यक्ष–

कहना नहीं, पूछना है आपको । यह प्रश्नकाल है आपकी सूचनायें महत्वपूर्ण हो सकती हैं लेकिन यह प्रश्नकाल है आपको केवल पूछना है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि क्या मौजूदा सरकार हथकरघा उद्योग में लगे हुए उन तमाम बुनकरों के उत्थान के लिए साफ नीयत से अपनी ओर से कोई नई नीति लागू करने आई है इनका कोई मकसद उसके उत्थान से नहीं है और जी0एस0टी0 लागू करके इन्होंने उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। मेरा एक केवल एक प्रश्न है कि क्या सरकार जी0एस0टी0 कौंसिल में बुनकरों पर लगने वाले और हैण्डलूम पर लगने वाले जी0एस0टी0 को खत्म करने का प्रस्ताव देगी और दूसरे नम्बर पर इनके उत्थान के लिए इनकी क्या योजनायें हैं।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, जो जी0एस0टी0 का प्रश्न पूछ रहे हैं यह विषय से संबंधित नहीं है। यह आपके प्रश्न में उल्लेख नहीं है इसलिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। जो आपने उल्लेख किया है मैंने उस विषय का पूर्णतः से उल्लेख किया है और माननीय अध्यक्ष जी, आज हथकरघा उद्योग जिस स्थिति में पहुंचा है तो इसके जिम्मेदार ये लोग है 14 वर्ष में इन लोगों ने इस उद्योग को धराशायी कर दिया ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नीतियां बनाई आप उन्हीं पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हमीं जिम्मेदार हैं आपने कौन सी नई नीतियां बनाई मेरा इस बात का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

सरकार एक सतत् प्रवाही कार्यवाही है तो आपको जिस योजना पर एतराज हो कि न ले तो वह बता दीजिए।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं इसलिए आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ पूरे प्रदेश के बुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बदहाली को रोकर गये हैं और वहां सांत्वना देने के साथ यह हाउस में आश्वासन क्यों नहीं दिया जाता कि क्या बुनकरों के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हुये जी0एस0टी0 कौन्सिल में प्रदेश सरकार जी0एस0टी0 को खत्म करने का प्रस्ताव रखेगी ?

श्री अध्यक्ष–

बुनकरों के हितों के प्रति आप प्रतिबद्व हैं, इसका उत्तर आप दे दीजिये।

श्री सत्यदेव पचौरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बुनकर रोकर गये हैं, यह 15 साल के हालात के ऊपर रोकर गये हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि बुनकरों के प्रोत्साहन के लिये जो हमारी योजनायें चल रही हैं, उनमें बुनकरों का संरक्षण होगा और उनका संवर्धन होगा ।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा लम्बा चौड़ा कुछ भाषण नहीं देंगे, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिये आपने तमाम योजनाओं का उल्लेख किया। मैं पूछना चाहता हूं कि बुनकरों द्वारा उत्पादित कपड़ा व धागा द्वारा पावरलूम या हैन्डलूम में अच्छे कपड़े तो जरूर दिख रहे हैं लेकिन उनके द्वारा उत्पादित कपड़े व धागे की बिक्री की बड़ी समस्या है क्या इनके उत्पादित कपड़ों को सरकार स्वंय लेकर इनके उचित विक्रय करने की व्यवस्था करेगी।

श्री सत्यदेव पचौरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यू0पी0 हैन्डलूम और यूपिका बुनकरों से कपड़ा खरीदकर सरकार को सप्लाई कर रही है और 2019 तक इसके लिये संरक्षण नीति बनाई गयी है।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब तो इस पर बहुत स्पष्ट उत्तर आ गया । अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में किसानों को प्रत्येक वर्ष सब्सिडी दिये जाने की कार्य योजना

'03–श्री पंकज सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को बीज पर एक वर्ष सब्सिडी मिलती है, फिर एक या दो वर्ष का गैप रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें किसानों को हर वर्ष बीज पर सब्सिडी दी जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

जी नहीं।

प्रमाणित बीज को एक कृषक द्वारा 03 वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसके दृष्टिगत जिन कृषकों को एक वर्ष अनुदान की सुविधा दी जा चुकी है उन्हें 02 वर्ष पश्चात अनुदान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री पंकज सिंह–

मैं इससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

'04श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ख्1 ले सोमवार के ता0प्र0सं0–12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, इसे पहले सोमवार तक के लिये आगे बढ़ा दिया गया है।

प्रदेश में कृषि उपज कृषि उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देने की नीति

'05 डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उपज और कृषि पर आधारित उद्योग, व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

प्रदेश की कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा कृषि नीति 2013 निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

प्राकृतिक संसाधन का इष्टतम उपयोग एवं पर्यावरण प्रबन्धन।

निवेश प्रबन्धन।

प्रसार एवं कृषि परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन।

फसलोत्तर प्रबन्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास।

कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन।

कृषकों के आर्थिक स्तर में उत्थान हेतु कृषि प्रोत्साहन।

कृषि में जोखिम प्रबन्धन।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा।

ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

कृषि शिक्षा, शोध एवं मानव संसाधन विकास।

कृषि पर आधारित उद्योग एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु अन्य विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

अ–उद्योग–

(1) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग–खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, कोल्ड चेन, प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना तथा रिफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन आदि के क्रय हेतु मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजनान्तर्गत ब्याज उपादान वित्तीय सहायता/रियायतें प्रदान की जाती है।

ब–व्यवसाय–

(1) खाद्य एवं रसद विभाग–शासन द्वारा निर्धारित क्रय एजेन्सियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीद तथा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों को भुगतान की व्यवस्था की गयी है। आधुनिक चावल मिलों को धान की कस्टम हलिंग हेतु सम्बद्ध करने में वरीयता दी जाती है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उक्तवत् चावल उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है।

(2) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–मण्डी अधिनियम और मण्डी नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को या इसके पश्चात् स्थापित नई कृषि प्रसंस्करण इकाई जिनकी संयंत्र एवं मशीनरी की लागत 05 करोड़ या उससे अधिक हो, अधिकतम 05 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से सहमत हूं सिर्फ प्रश्न के दूसरे खण्ड से छोटी सी जानकारी चाहिये जो कृषि उपज आधारित उद्योग से सम्बन्धित है। मा0 मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजनान्तर्गत योजना में वित्तीय सहायता क्या है और उस पर सब्सिडी है या नहीं सिर्फ इतना सा जवाब चाहिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुन्देलखण्ड पूर्वांचल में 100 एकड़ पर और मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों के लिये तथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ भूमि विकसित एग्रो पार्क के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन, भूमि क्रय पर 7 वर्ष के लिये वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत तक अधिकतम और 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष सब्सिडी दी जायेगी। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्ष के लिये वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक अधिकतम 10 करोड़ प्रतिवर्ष और 50 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी। कोल्ड स्टोरज डाउन गोडाउन ई0पी0टी0, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आदि उद्योगों को लगाना होगा।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने लिखित में जवाब दिया है कि कृषि में जोखिम प्रबन्धन। मान्यवर, इसी के अन्तर्गत किसान बीमा दुर्घटना योजना का लाभ किसानों की दुर्घटना होने पर दिया जाता है। मान्यवर, किसान उसे माना जाता है जिसके नाम जमीन है। मान्यवर, अगर वह 90 साल का है और उसका बेटा वास्तविक कृषक है और उसकी दुर्घटना होने पर उसको कोई लाभ नहीं मिलता है तो क्या मा0 कृषि मंत्री जी किसान दुर्घटना बीमा में जो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं और उनके बेटे जो वास्तविक किसानी कर रहे हैं क्या उनको भी किसान दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी, यह इस प्रश्न से आच्छादित नहीं है। मा0 मंत्री जी को यदि कुछ कहना हो तो कह दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह आच्छादित नहीं है वैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बहुत मामूली प्रीमियम देने पर सबका कवरेज हो जाता है।

उ0प्र0 में उन्नतिशील बीजों को समय से पूर्व ही ब्लाकों पर पहुंचाने की योजना

'06 श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उन्नतिशील बीजों को बुवाई से पूर्व ही ब्लाकों पर पहुंचाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार काला नमक चावल जो गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन मण्डलों में पैदा होता है, को संरक्षित–संवर्धित, शोध, विकास के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा काला नमक धान को संरक्षित करने एवं इसके संवर्धन शोध एवं विकास करने पर कार्य किया जा रहा है। काला नमक धान की दो नयी प्रजातियां–के0एन0–3 एवं बौना काला नमक–101 विकसित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी आपकी कृपा है कि आज आपने दूसरी बार मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

यह तीसरी बार है।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का यकीन है कि आपका संरक्षण एक निर्दलीय विधायक को भी है।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि आप निर्दलीय नहीं, ब0स0पा0 के सदस्य हैं)

मान्यवर, मैं इंडिपेन्डेंट एम0एल0ए0 हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप मा0 सदस्य से बात न करिये।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

आदरणीय माननीय मंत्री जी चूंकि आप भी गोरखपुर जिले के ही हैं, हमारे चचा है। (हंसी) हमारे पास उनका संरक्षण है, गोरखपुर मण्डल के तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष–

तो आप फिर सवाल नहीं करेंगे, अपने चचा से सवाल नहीं कर रहे हैं ?

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

मेरा सवाल यह है कि देवी पाटन मण्डल, गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल अगर आज जिन्दा है तो इसलिए जिन्दा है कि काला नमक पैदा करता है जब किसान, तब पूरे घर का खर्चा चलता है।

श्री अध्यक्ष–

आप जो सूचनायें दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन आप सवाल करिये, यह प्रश्न काल है।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

मैं इतनी ही बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग बासमती की तरह काला नमक का उत्पादन करके, इक्कट्ठा करके पूरे प्रदेश में उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते जो पूर्वान्चल के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पूरे पूर्वान्चल के लिए काला नमक चावल

जिसकी दो प्रजातियों का नाम लिया गया, एक का नाम है के0 एन0–3, दूसरे का नाम है काला नमक–101। तो क्या हम लोग काला नमक–101 और के0एन0–3 को इण्डिया गेट बासमती चावल के बराबर खड़ा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य बैठिये, आपके दो सवाल हो गये, अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मूल प्रश्न काला नमक के बारे में है, बासमती के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने बासमती इसलिए जोड़ दिया कि आप इनके चाचा हैं। (हंसी)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, सरकार उस चिंता से अवगत है और इसलिए इस साल हमने सेण्टर आफ एक्सीलेंसी के रूप में धान की फसलों के लिए फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय को अधिकृत किया है और अभी जो बजट आया है उसमें उस पर 02 करोड़ रुपये का प्राविधान करके ऐसे फसलों को संरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

नेता, विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उनकी मंशा यह थी कि जैसे केन्द्र सरकार बासमती चावल को निर्यात करके किसानों को लाभकारी मूल्य देने की व्यवस्था करती है तो काला नमक चावल के भी निर्यात करने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी, यह मा0 सदस्य के पूछने का सही मकसद है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन इधर के वर्षों में यह प्रजाति लुप्त हो रही थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न हो गया।

प्रदेश में युवा प्रतिभाओं को विभिन्न खेलों में प्रोत्साहन देने हेतु तह0 मुख्यालयों पर स्टेडियम के निर्माण की मांग

'07–श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा प्रतिभाओं को विभिन्न खेलों में प्रोत्साहन देने हेतु क्या सरकार सभी तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

जी नहीं।

प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम निर्माण की योजना ड्राप कर दी गयी।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में, खासतौर से नवसृजित जनपदों में कई स्टेडियम करोड़ों रुपये खर्च करके बनाये गये हैं लेकिन इधर कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का नाम इण्टरनेशनल खिलाड़ी में कभी सुनने को नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के जनपदों में कितने कोच हैं ? स्टाफ है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मूल सवाल का भाग नहीं है। यह जो आप पूछ रहे हैं यह संगत हो सकता है लेकिन मूल प्रश्न का भाग नहीं।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

कितने कोच हैं और स्टाफ कितना है। स्टेडियम में खिलाड़ियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है? नवसृजित जनपदों में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती में तीन वर्षों में एक लाख रुपये खिलाड़ियों के लिये दिया गया है तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह खिलाड़ी बैडमिन्टन खेलें या फुटबाल खेलें इतने कम धन में या गुल्ली डंडा खेलें।

श्री अध्यक्ष–

आपको कौन सा खेल पसन्द है ?

(हंसी)

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं। मैं अपने ज्ञान के लिये और माननीय सदस्यों के ज्ञान के लिये माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा योग्य मंत्री बनाया है। माननीय मंत्री जी सदन को यह बतायें कि बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

यह आपने लिखकर नहीं पूछा।

श्री चेतन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सवाल है यह युवा कल्याण से संबंधित है। दो विभाग अलग–अलग हैं। युवा कल्याण अलग विभाग है और खेल विभाग अलग है और यह जो सवाल पूछ रहे हैं अधिकतर खेल विभाग से संबंधित पूछ रहे हैं। जो जानकारी यह मांग

रहे हैं वह हम इनको लिखकर दे देंगें। लेकिन आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि पिछले 15 साल से यहां कोई काम नहीं हो रहा है युवा कल्याण में। यह जो विभाग है लगभग–लगभग बन्द है। इसके चलाने के लिये हम लोग जो खेल विभाग है कुछ यहां पर जो स्टेडियम बने हुए हैं युवा कल्याण में ग्रामीण अंचलों में हैं उनको हम किस प्रकार से सुचारु रूप से चला सकें एक योजना बन रही है और यह हो सकता है कि खेल विभाग के पास थोड़ा धन है, कर्मचारी हैं तो अब यह जो स्टेडियम बने हैं इनका स्ट्रक्चर है युवा कल्याण का, हम उसको ले लें अधिग्रहीत कर लें चलाने के लिये और सुचारु रूप से हम इनको चला सकें।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो भी सरकार का मंत्री खड़ा होता है पिछले 15 साल पीछे चला जाता है। 15 साल पीछे जब हम नाबालिग रहे होंगे। तो पीछे पिछले 15 साल क्या हुआ था मैं माननीय युवा कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 15 साल पहले कौन–कौन सी योजनाएं चल रहीं थीं, कौन–कौन सी योजनाएं बंद हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

उन्होंने कहा है कि 15 साल में यह काम बन्द हुए हैं तो 15 साल पहले कौन–कौन सी योजनाएं चल रही थीं कौन–कौन सी योजनाएं पिछले 15 साल में बंद हुई हैं और आगे सरकार कौन–कौन सी योजनाएं चलाने का काम करेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम को स्थापित करने के लिये विगत समय में विभिन्न ग्राम सभाओं और नगर पालिकाओं के द्वारा जो जमीन युवा कल्याण विभाग को दी गई थी और आपने बताया कि योजना बन्द कर दी गई। उस जमीन को क्या सरकार दूसरे विभागों को वापस करेगी जो काम के लायक होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब यह तो राजस्व से प्रश्न हो जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

आपके नाम दर्ज है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम की स्थापना के लिये पीछे के समय में जो जमीनें युवा कल्याण विभाग को ट्रांसफर की गई थीं आप यह बतायें कि आपने उसको ड्राप कर दिया है या भारत सरकार ने ड्राप कर दिया है। जमीन युवा कल्याण के नाम बेकार पड़ी है। क्या उन जमीनों का ग्राम सभाओं को वापस करेंगे।

खेल युवा कल्याण कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

अध्यक्ष जी, हमने कोई भी स्कीम ड्राप नहीं की है यह जो स्कीम है ड्राप करने वाली यह 2011 में ड्राप हुई है। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो योजनायें पिछली चल रही हैं हम उनको कोई रोक नहीं रहे हैं। जहां तक जमीनों का सवाल आता है बहुत से माननीय सदस्य मुझे लिख रहे हैं और वह लोग तहसीलों में और छोटे–छोटे ब्लाकों में कोई न कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं मिनी स्टेडियम बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की एक योजना आई है हालांकि इस सवाल से उसका संबध नहीं है लेकिन जानकारी के लिए, पूरे हाउस के लिए बताना चाहूंगा 'खेलो इण्डिया' एक योजना निकलकर आई है केन्द्र सरकार की, उसमें जो प्रस्ताव आप लोगों के आ रहे है वह प्रस्ताव बनाकर हम लोग जिलाधिकारी को दुबारा से चिट्ठी लिख रहे हैं उनसे वह प्रस्ताव हम मंगा रहे हैं क्योंकि धन जो उपलब्ध करायेगी वह केन्द्र सरकार उपलब्ध करायेगी, तो यह प्रस्ताव बनाकर हम लोग वहां पर दे देंगे और जो प्रस्ताव पहले हो गये हैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा जो प्रस्ताव जमीनों के लिए हैं हम किसी भी विभाग को जमीनों को वापस नहीं देंगे इसको हम अपने पास रखेंगे। किस प्रकार से इसका उपयोग हो सके यह देखा जाएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, राजीव गांधी खेल स्थापना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में कई ब्लाकों से युवा कल्याण विभाग ने पांच–पांच एकड़ जमीन अपने आप दर्ज करवा ली और यह कहा कि यहां पर स्टेडियम खोलेंगे स्टेडियम खोले नहीं जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी कह तो रहे हैं कि आगे उनका उपयोग करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

नहीं, वह योजना ही ड्राप कर दी गई। मेरी कांस्टीटुएन्सी में तीनों ब्लाकों में पांच–पांच एकड़ जमीन आपको दे रखी है। वह योजनायें ड्राप कर दी गईं तो उस जमीन का स्टेट के दूसरी चीज के लिए उपयोग हो सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपके साथ बैठकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, युवा कल्याण मंत्री जी जैसा कि देखने में भी लगता है कि इनसे युवा सदन में कोई है नहीं, और यह इण्टरनेशनल खिलाड़ी हैं केवल यह सदन को इतना बता दें कि बास्केट बाल में कितने खिलाड़ी होते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

बास्केट बाल का हमें भी नहीं मालूम कितने होते हैं। कबड्डी का मालूम है। (हंसी)

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या के दृष्टिगत छात्रों को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की कार्य योजना

'08–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों की निर्धारित क्षमता के सापेक्ष घटती संख्या के दृष्टिगत छात्रों को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

छात्रों की कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की कार्य योजना है।

उक्त कार्य योजना निम्नवत है :–

प्रदेश के अन्तर्गत स्थित चारों कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों की वर्ष 2017 की प्रवेश परीक्षा में सामान्य जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 10 प्रतिशत कट आफ मेरिट निर्धारित किया गया है। सीट रिक्त रह जाने के स्थिति में प्रवेश समिति को 05 प्रतिशत की सीमा तक शिथिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, जिससे कृषि विश्वविद्यालयों के सीटों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित कालेजों/प्रोग्रामों का एक्रीडिटेशन कराकर उसकी महत्ता बढ़ाने की कार्य योजना है, जिससे अधिक छात्र कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकें।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता का विकास कर छात्रों को कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाना है।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय स्थापित है, जो डिग्री धारक छात्रों हेतु रोजगार की व्यवस्था करता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न बैंकों में कृषि अधिकारी/प्रबन्धक के पद पर तथा फर्टिलाईजर/सीडस/बायोटेक्निकल कम्पनियों में भी नौकरियां प्राप्त हुई है।

स्वरोजगार के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट व मधुमक्खी पालन पर प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मूल प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी है इसके लिए आपको धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 67.2 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है । इस बात का प्रमाण है कि देश के जो भी राज्य कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े हैं वह कहीं न कहीं जब व्यवसायिक कृषि की ओर उन्मुख हुए हैं तभी आगे बढ़े हैं। मंत्री जी से मैं अनुपूरक के रूप में चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य में संचालित हैं उनमें पिछले तीन वर्ष में वर्षवार छात्रों की संख्या का क्या अनुपात रहा है। दूसरा क्या कृषि शिक्षा में छात्रों की गिरती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार कृषि शिक्षा से

सम्बंधित छात्र बी0एस0सी0ए0जी0 और एम0एस0सी0ए0जी0 की ओर जाते हैं उनके प्रोत्साहन की ओर सरकार क्या कोई योजना बना रही है या बनाई है नम्बर तीसरा जो डिग्री प्राप्त छात्रों के रोजगार की बात माननीय मंत्री जी ने कही है हम जानना चाहते हैं कि जो बच्चे कृषि विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकले हैं उनमें तीन वर्ष में कितने बच्चे निकले हैं ? कितनों को रोजगार में आज तक लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तीर्ण बात है इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

यह प्रश्न मूल प्रश्न में है और उत्तर में आ गया है कि हम रोजगार से लगा रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विगत वर्षों में स्वीकृत सीटों के मुकाबले प्रवेशित छात्रों की संख्या में कमी आई है। यह कमी एन0आर0आई0कोटे के कारण आई0सी0आर0कोटा को न भरे जाने के कारण कालेजों का एक्वीडेशन न कराए जाने के कारण कृषि विश्वविद्यालयों के मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां पिछले पांच वर्ष नहीं हुई उनके कारण और उत्तर प्रदेश की संयुक्त कृषि और औद्योगिक प्रशिक्षण की काउंसिलिंग बी0एच0यू0और अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं के पहले हो जाने के कारण छात्र संख्या में कमी आई है । जो आपने संख्या पूछा वह बता रहा हूं यू0जी0 पाठ्यक्रम में विगत तीन वर्षों के भीतर 2014–15 में 1435 के मुकाबले 1265 छात्रों के प्रवेश हुए 2015–16 में 1549 छात्रों के मुकाबले 1368 छात्रों का प्रवेश हुआ। 2016–17 में 1461 छात्रों के मुकाबले 1206 छात्रों का प्रवेश हुआ इसी प्रकार पी0जी0पाठ्यक्रम में 682 के मुकाबले 502, 673 के मुकाबले 458 और 627 के मुकाबले 396 बच्चों का इन वर्षों में प्रवेश हुआ। पी0एच0डी0कोर्स में इन वर्षों में क्रमशः 221 के मुकाबले 153, 225 के मुकाबले 115 और 227 के मुकाबले 100 छात्रों ने प्रवेश लिया। इस प्रकार से यह संख्या जो कारण मैंने बताए उन कारणों से इसमें कमी हुई है हम लोगों ने इस आधारभूत संरचना को ठीक करने उनको जैसा मैंने बताया कि सेन्टर फार एक्सीलेंस तय करके उसके लिए बजेटरी प्राविधान भी हम कर रहे हैं सरकार स्तर पर हमने समीक्षा भी की है और हमने यह निर्धारित भी किया है कि जो शिक्षकों का न्यूनतम मानक है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए कार्यवाही आगे की ओर ले जाने की प्रक्रिया हम चला रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। मंत्री जी ने केवल छात्रों की संख्या बताई है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इन्होंने रोजगार के संदर्भ में पूछा है रोजगार की पूरी संख्या यहां पर एकत्र नहीं है। प्रदेश के भीतर आत्मा योजना के भीतर जो बच्चे काम करते हैं उनके

लिए बी0एस0सी0ए0जी0 होना अनिवार्य है। जो बी0टी0एम0 और ए0टी0एम0 के रूप में काम करते हैं उसके माध्यम से उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। एग्री जंक्शन योजना के माध्यम से उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो बी0एस0सी0 एग्री0 के छात्र हैं, ऊपर की कक्षाओं पी0जी0 और पी0एच0डी0 में कमी होने का यह भी कारण है कि चूंकि वह बी0एस0सी0 एग्री0 के लेवल पर बैंकों के भीतर या अन्य प्राईवेट संस्थाओं के भीतर समायोजित हो जाते हैं इस नाते वह आगे पढ़ने का अवसर आर्थिक कारणों के कारण वहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बी0एस0सी0 एग्री0 के लेवल पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, यह भी उसका एक कारण है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है, अब अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। मा0 मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि तीनों वर्ष मिलाकर के लगभग 42 प्रतिशत की कमी आई है जो छात्रों की संख्या निर्धारित है, मा0 मंत्री जी के पास जो सीटें हैं। उस राज्य में जहां पर सबसे बड़ी संख्या में लोग कृषि पर आश्रित हैं, उस राज्य में 42 प्रतिशत की कमी आई है। यह कृषि से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि छात्रों को और प्रोत्साहित करने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है। यह मा0 मंत्री जी नहीं बता पाये कि कोई योजना हमनें बनाई है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिन कारणों से प्रवेश में कमी आई है उन कारणों का निवारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा में माईनस मार्किंग को समाप्त किया जाना, उसको हटा दिया जाये, यह एक सुझाव है। दूसरा एन0आर0आई0 और आई0सी0आर0 कोटे से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं इसलिये उन कोटों के ऊपर भी रिव्यू किया जाना है। यह विचाराधीन विषय हैं और कालेज का एक्रिडिएशन कराया जाना विचाराधीन है। कृषि विश्वविद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस प्रकार से उनके छात्रावासों को ठीक किया जाना, पढ़ाई की गुणवत्ता के लिये उनके विषयों के संबंध में पुनर्निर्धारण किया जाना, यह सब प्रक्रियारत है। इस नाते यह सरकार जब से आई है तब से हमनें कृषि विश्वविद्यालयों की घटती हुयी संख्या के बारे में चिंता भी व्यक्त की है और पठन–पाठन की दृष्टि से क्या परिवर्तन किया जाए इस संबंध में कुलपति स्तर पर बातचीत भी की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 पाण्डेय जी, एक प्रश्न में बहुत लम्बा डिस्कशन हो गया है और आपके प्रश्न का पूरा उत्तर भी आ गया है इसलिये अब आप बैठें। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

(सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा सदस्य, श्री नितिन अग्रवाल जी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके माईक ऑफ थे।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आज का एजेण्डा बड़ा है। मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलना है तथा अन्य मा0 नेताओं को बोलना है। आज नियम–300 तथा नियम–301 के अन्तर्गत कई सूचनाएं हैं। इसलिये आप लोग कृपया बैठ जायें।

प्रदेश में व्यापार की सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर करने की कार्य योजना

'09–श्री पारस नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यापार की सुगमता (इजी आफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर बनाने हेतु क्या सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर–6 में व्यापार की सुगमता (इजी आफ डूइंग बिजनेस) के संबंध में प्राविधान उल्लिखित है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

मा0 पारसनाथ यादव जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं उत्तर दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप उत्तर दे दीजिये।

(मंत्री, श्री सतीश महाना द्वारा उत्तर पढ़ा गया।)

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसी नीति बनाई है कि पी0पी0पी0 मॉडल पर अगर कोई व्यक्ति नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना चाहता है, अभी तो सिर्फ सरकार ही ऐसा करती है, तो क्या कोई बाहरी व्यक्ति भी पी0पी0पी0 मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 सदस्य बहुत विद्वान हैं तथा विद्वान पिता के विद्वान पुत्र हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इण्डस्ट्री पी0पी0पी0 मॉडल पर नहीं लगती है, इण्डस्ट्री प्राईवेट ही लगती है। इस नीति के अन्तर्गत हमनें प्राईवेट इण्डस्ट्रियल पार्क इनवाइट करने की बात की है। मान्यवर, प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क के लिए नीति तय करी है कि यदि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आकर 100 एकड़ के ऊपर अपना औद्योगिक पार्क लगाना चाहता है तो हम उसको प्रोत्साहन देंगे और उस प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो हमारे अनुमन्य इन्सेन्टिव हैं, वह भी हम उनको देंगे। बहुत सारे इन्सेन्टिव हैं आप विस्तार से पूछेंगे तो उसको हम अलग से बता देंगे।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इजी आफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर स्किल, सेमी स्किल लेबर की बहुत ही ज्यादा तादाद उपलब्ध है। लेकिन अभी भी इस मामले में उत्तर प्रदेश चौदहवें नम्बर पर आता है। इजी आफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सरकार ने सिंगल विण्डो सिस्टम और हाई पावर कमेटी जिसके चेयरमैन आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री जी रहते हैं और उनके साथ–साथ कई–कई विभागों के प्रिन्सिपल सेकेट्री और सेकेट्रीज रहते हैं। यह सब आज पूरी तरह से डाई फंक्सनल हो गये हैं यानी कि पूरी तरह से डिफंग पड़े हुये हैं इसमें कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती हैं। तो क्या सरकार यह सिंगल विण्डो सिस्टम और जो सरकार के एक्ट और आर्डर हैं जो नहीं फालो हो रहे हैं क्या उसके ऊपर सरकार फिर से विचार करके इनको फालो करवाने के लिए क्या कोई नीति बना रही है और यह जो हाई पावर कमेटीज बैठाई गई हैं, इनकी मीटिंग होगी या नहीं होगी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपनी बात में यह स्वीकार कर लिया है कि यह नहीं होता था, यह नहीं होता था और यह नहीं होता था। मान्यवर, अभी तो शुरूआत हुई है। अभी तो हम पॅलिसी लेकर आये हैं। पहले तो पॉलिसी ही नहीं थी। पिछली सरकार में माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं थे। मैं विपक्ष की तरफ वहां पर बैठकर सरकार से पूछता था कि सरकार की इस संबंध में क्या पॉलिसी है, तो मंत्री जी बता भी नहीं पाते थे कि पॉलिसी है भी की नहीं है। तब यह होता था। मान्यवर, पिछले मंगलवार को ही हम कैबिनेट में इस नीति को लेकर आये हैं। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो पिछली सरकार में नहीं होती थी, वह अब होना शुरू होगी। जो बात हम इस पॉलिसी के अंदर लेकर आये हैं उसमें सबसे प्रमुख यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में हम एक सिंगल पोर्टल सिस्टम बनायेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। एक ही जगह पर हम कॉमन अप्लीकेशन फार्म लेंगे और कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर इण्डस्ट्रियलिस्ट को विभिन्न विभागों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत हर विभाग को यह निर्देश

दिये गये हैं कि अपना क्लीयरेंस वह अपने आप भेजेंगे और यदि उनका क्लीयरेंस समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होता है तो जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और वह क्लीयरेंस अपने आप दिया जाना माना जायेगा। इस तरह की कार्यवाही हम करने जा रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को एक जानकारी मैं भी दे दूं जो आप कॉमन अप्लीकेशन फार्म की बात कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समय इसकी शुरुआत की थी और यह हैवी इण्डस्ट्रीज के लिए की थी और यह ए0एम0एस0एम0ई0 इण्डस्ट्री के लिए भी की थी। हमारी सरकार ही पहली बार ए0एम0एस0एम0ई0 इण्डस्ट्री के लिए पॉलिसी लेकर आई थी और इस कॉमन अप्लीकेशन फार्म की हमारी सरकार में ही शुरूआत हुई थी।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले जब कॉमन अप्लीकेशन फार्म जमा किया जाता था तो सारे विभागों के पास इण्डस्ट्रियलिस्ट दौड़–दौड़ कर परेशान होकर घर चला जाता था वह इण्डस्ट्री नहीं लगाता था। हमने कहा है कि कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म को हम प्रभावी बनायेंगे। जितना इन्वेस्टमेण्ट आप एक साल के अंदर लेकर आते थे, उतना इन्वेस्टमेण्ट हम सौ दिनों के अंदर लेकर आ चुके हैं। हम इसे लायेंगे नहीं, बल्कि इसे ला चुके हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो एम0ओ0यू0 साइन किये थे, उसका प्रतिफल अब सामने आ रहा है, वही आंकड़े यह अपनी सरकार के नाम से दे रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय नितिन जी जो बात कर रहे हैं उसको मैं क्लीयर किये दे रहा हूं। जब हमारी सरकार बनी तो सैमसंग वाले हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि हम तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। छह महीने से स्वीकृति के बाद आज तक हमारे को किसी प्रकार की कोई सुविधा नही मिली। पिछली सरकार में 547 करोड़ रूपये का उनका जो इन्वेस्टमेण्ट प्लान था, तो हमारी सरकार की विश्वसनीयता के कारण उसे बढ़ाकर उन्होंने 4915 करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेण्ट प्लान किया है। इसे हमने कैबिनेट से किया है, इसे हमारी इम्पावरमेण्ट कमेटी ने किया है। यह पहले नहीं हुआ है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, सैमसंग का एम0ओ0यू0 हमारी सरकार ने किया था, यह आपकी सरकार का कैसे हो गया।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह एम0ओ0यू0 पहले 4915 करोड़ रुपये का नहीं हुआ था, यह हमने कराया है।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुपूरक प्रश्न और है। कृपया उसे पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया अब आप बैठिये। अनुपूरक प्रश्न तो पूछ लिया है आपने।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती के कृषि विभाग में आत्मा कार्मिक वेलफेयर एसोसियेशन के कर्मचारियों को ऑन लाइन नवीनीकरण तथा विभागीय संविदा दिलाने की मांग

01–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के कृषि विभाग में आत्मा कार्मिक–वेलफेयर एसोसिएशन के कर्मचारियों का सेवा प्रदानता तथा नवीनीकरण किये जाने हेतु हो रहे आर्थिक शोषण का संज्ञान लेकर क्या सरकार ऑन लाइन नवीनीकरण तथा सेवा प्रदाता को हटा कर विभागीय संविदा दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

शासनादेश संख्या–2511/12–3–09–7/09 दिनांक 07 अगस्त, 2009 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से ही कार्मिकों से सेवा लिये जाने का प्राविधान है। शाासनादेश में कार्मिकों के आनलाइन चयन आदि की व्यवस्था नहीं है।

जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित योजनाबद्ध ढंग से बसाये गये नोएडा शहर में भीषण जाम से निजात दिलाने की कार्य योजना

02–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित योजनाबद्ध ढंग से बसाये गये नोएडा शहर में भीषण जाम एवं अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सरकार की कोई ठोस कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0–9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सतीश महाना–

जी हां।

पुलिस अधीक्षक, यातायात, गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगमता से संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना संलग्न[४] है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

---

४ छापी नहीं गयी।

03–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण में स्थाई रूप से तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था न होने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–2/वि0/नोएडा/2017, दिनांक–24 मार्च, 2017 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। इस संबंध में यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा–5–ए के प्राविधान के अनुरुप यू0पी0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट–1976 की धारा–5 के पश्चात् धारा–5ए जोड़ने हेतु ऐक्ट में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में दिये जा रहे दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पेंशन की जानकारी

04–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कितने लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जनपद में कितने आवेदकों के दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन–पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदनों का निस्तारण कराकर कब तक आवेदकों की पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)–

1857 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन प्रदान की जा रही है।

जनपद बागपत के दिव्यांग पेंशन हेतु कुल 175 आवेदन–पत्र लम्बित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित किया जाएगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में दिये जा रहे वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन की जानकारी

05–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कितने लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा कितने आवेदकों के आवेदन–पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदनों का निस्तारण कराकर आवेदकों की पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में 3431 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा 547 आवेदकों के आवेदन–पत्र लम्बित है।

जी हां।

योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले लम्बित आवेदकों की पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

06–श्री दलवीर सिंह–

खदिनांक 11–07–2017 को अता0प्र0सं0–37 द्वारा उत्तरित।,

प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने स्कूलों एवं कालेजों पर किसानों द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर उनके बच्चों के प्रवेश पर आरक्षण/रियायत देने के सम्बन्ध में

07–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने स्कूलों और कालेजों में, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षण/रियायत देने की शर्त पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या स्कूलों और कालेजों ने इस शर्त का पालन किया है ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्ष का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

जी हां।

नोएडा क्षेत्र में कार्यशील स्कूलों से प्राप्त सूचना का विवरण संलग्न[४] है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा सामाजिक एवं कला सेन्टर के लिये रियायती दरों पर आवंटित किये गये भू–खण्ड का प्रकरण

08–श्री दलवीर सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04–05–2017 तक रियायती दरों पर कितने भू–खण्ड सामाजिक एवं कला सेंटर्स की स्थापना हेतु आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त भू–खण्डों पर नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर नियम विरुद्ध किये गये आवंटन को निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

---

४ छापी नहीं गयी।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04–05–2017 तक सामाजिक एवं कला सेन्टर की स्थापना हेतु कुल 22 संस्थागत भू–खण्ड प्रचलित दर पर आवंटित किये गये हैं। उक्त भू–खण्डों को रियायती दर पर आवंटित नहीं किया गया है।

उक्त भू–खण्डों में से जवाहरलाल नेहरु नेशनल यूथ सेन्टर को आवंटित भू–खण्ड संख्या–यू–1, सेक्टर–11, नोएडा को छोड़कर अन्य भू–खण्डों पर नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।

जवाहर लाल नेहरु यूथ सेन्टर को आवंटित भू–खण्ड संख्या–यू–1, सेक्टर–11, नोएडा के परिसर में अवैध निर्माण व अवैध भू–उपयोग पाये जाने पर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24.02.2015 द्वारा भू–खण्ड का निरस्तीकरण किया गया है, जिसके विरुद्ध भू–खण्ड के आवंटी तथा अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद योजित किये गये, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के अनुपालन में निस्तारण की कार्यवाही संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की तालानगरी योजना आवंटित भूमि का उपयोग न करने वाली संस्थाओं का आवंटन निरस्त करने की जानकारी

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0, अलीगढ़ की तालानगरी योजना में शिक्षण संस्थाओं हेतु कुल कितनी भूमि आरक्षित है तथा इसमें से कितनी भूमि का आवंटन किया जा चुका है ? क्या सरकार बतायेगी कि आवंटित भूमि पर कौन–कौन सी शिक्षण संस्थायें स्थापित हो चुकी हैं तथा कौन–कौन सी सस्थाओं ने आवंटन के वर्षों बाद भी संस्थायें स्थापित नहीं की हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में आवंटित भूमि का उपयोग न करने वाली संस्थाओं का आवंटन नियमानुसार निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

तालानगरी योजना में शैक्षणिक एवं आवासीय सेक्टर में कुल 63.33 एकड़ भूमि शिक्षण संस्थाओं हेतु आरक्षित है, जिसमें से शिक्षण संस्थाओं को 60.78 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

शैक्षणिक सेक्टर में आवंटित भू–खण्ड संख्या–एसएच–1, जो मे0 रोमन कैथोलिक डायोसिस आफ आगरा को आवंटित है, पर स्कूल कार्यरत है। भू–खण्ड संख्या–एसएच–2, जो मे0 पं0 दीन दयाल शिक्षा प्रसार समिति को आवंटित है, पर स्कूल कार्यरत है। भू–खण्ड संख्या–एसएच–3, जो मे0 न्यू डिवाइन एजूकेशनल सोसाइटी के पक्ष में आवंटित है, वर्तमान में रिक्त हैं। भू–खण्ड संख्या–एस0एच0–4, जो रोमन कैथोलिक डायोसिस आफ आगरा को आवंटित है, पर स्कूल कार्यरत है। भू–खण्ड संख्या–एसएच–5, जो मे0 के0के0 जैन, एजूकेशनल ट्रस्ट को आवंटित है, पर स्कूल कार्यरत है। भू–खण्ड संख्या–एसएच–6, जो मे0 ब्रजधाम एजूकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी को आवंटित है, पर स्कूल कार्यरत हैं। भू–खण्ड संख्या–एसएच–7, जो मे0 आर्यभट्ट एजूकेशनल ट्रस्ट है, पर भवन निर्माणाधीन है। भू–खण्ड संख्या–एसएच–8,

जो मे0 रिनाईसेन्स सोसाइटी को आवंटित है, पर भू–खण्ड रिक्त है तथा भू–खण्ड के हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवासीय सेक्टर में भू–खण्ड संख्या–एसएच–3 दिनांक 03.01.2017 को आवंटित किया गया है।

जी हां।

निर्धारित अवधि समाप्त होने पर आवंटित भू–खण्ड का उपयोग न करने वाली संस्थाओं का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में जिला सतर्कता व अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक बैठक आहूत कराने हेतु जानकारी

10–श्रीमती सुषमा पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला सतर्कता व अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक बैठक आहूत की जाती है ? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक कितनी बैठकें हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

दो बैठकें हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में कृषि के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने तथा न्याय पंचायत स्तर पर मण्डियों/क्रय केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की मांग

11–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करने तथा कृषि उपज विक्रय के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार न्याय पंचायत स्तर पर मण्डियों/क्रय केन्द्रों की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में कुल 251 मण्डियां तथा 372 उप मण्डियां विनियमित हैं, जिनमें से 218 मण्डियों एवं 94 उप मण्डियों का निर्माण हो चुका है, इसके अतिरिक्त कृषकों को उनकी उपज के क्रय–विक्रय हेतु प्रदेश के प्रत्येक 10 किमी0 की लगभग दूरी पर 1643 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण कराया गया है। बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में एक–एक विशिष्ट मण्डी एवं 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पंजीकृत समितियों, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी व शासन द्वारा नामित क्रय एजेन्सियों के माध्यम से समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान/गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया जाता है। उक्त नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा सामान्यतः 08 किमी0 की दूरी पर जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त क्रय केन्द्र स्थापित करते हुए धान/गेहूं किसानों से सीधे खरीद करती है तथा कृषकों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ओनली एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। उक्त क्रय केन्द्र गेहूं खरीद में 01 अप्रैल तथा धान क्रय में 01 अक्टूबर को सक्रिय कर दिये जाते हैं।

प्रदेश के वर्तमान विधायकों को आवास आवंटित व कब्जा दिलाने की जानकारी

12–श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट–

12–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 04–05–2017 तक कितने वर्तमान विधायकों को उन्हें आवंटित सरकारी आवासों पर कब्जा मिल गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष मा0 सदस्यों को सरकार कब तक आवंटित आवासों का कब्जा दिला देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

दिनांक 04–05–2017 तक 236 वर्तमान मा0 विधायकों द्वारा आवंटित आवासों पर कब्जा प्राप्त कर दिया गया था तथा उक्त तिथि तक 139 मा0 विधायकों द्वारा आवंटित आवासों का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया।

जिन मा0 सदस्यों द्वारा अपने आवासों पर कब्जा दिनांक 04–05–17 तक प्राप्त नहीं किया गया था, उनमें से 74 मा0 विधायकों द्वारा अब तक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। शेष 65 मा0 सदस्यों द्वारा आवंटित आवासों में परिवर्तन की अपेक्षा के कारण आवंटित आवासों का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत पयागपुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति के निर्माण में की गयी गड़बड़ियों की जांच व कार्यवाही

13–श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत पयागपुर में निर्माणाधीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उसे कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मण्डी समिति के निर्माण में की गयी गड़बड़ियों की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03–05–2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह–

मण्डी स्थल, पयागपुर का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 2016 में पूर्ण हो चुका है।

हस्तगत किये जाने की औपचारिकता पूर्ण कर प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जी हां।

शिकायत की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0ए0एस0/आई0पी0एस0/पी0सी0एस0 एवं राजपत्रित अधिकारियों से लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर आवास खाली कराने की समय सीमा निर्धारित करने हेतु मांग

14–श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी हैं जिन्हें लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटित था और एक वर्ष पूर्व लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण होने के बाद अभी तक कब्जा जमाये हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार ऐसे लोगों से आवास खाली कराने की कोई समय–सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

पांच

जी हां।

जी हां।

दो माह।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायकों को वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन करने की जानकारी

15–श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विधायकों को आवास आवंटित करने का क्या आधार है ? क्या आवास आवंटन में विधायकों की वरिष्ठता भी देखी जा रही है तथा वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन में आवासों की कोई श्रेणी भी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 में विहित व्यवस्था के अनुसार मा0 विधायकों को आवास आवंटित किया जाता है।

मा0 विधायकों द्वारा की गयी मांग के दृष्टिगत उनकी वरिष्ठता एवं वांछित आवासों की उपलब्धता के आधार पर विचार कर आवास आवंटन अथवा परिवर्तन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर विधायक आवासों की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा नागापुर में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम का प्रकरण

16–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा नागापुर (पूरे मोतीलाल) में मिनी खेल स्टेडियम स्वीकृत है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में मंडी समितियां संचालित हो रही है तथा समितियों की साफ सफाई की नियमित व्यवस्था की जानकारी

17–श्री राम नरेश रावत–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समितियां किस–किस स्थान पर संचालित की जा रही हैं ? क्या संचालित की जा रही मण्डी समितियों में साफ–सफाई की नियमित व्यवस्था की गयी है ? तथा कब तक सफाई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाति सिंह–

विधान सभा क्षेत्र बछरावां में महाराजगंज में उप मण्डी स्थल संचालित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में चहरी फार्म को श्री महन्थ अवैद्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने का प्रकरण

18–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के चहरी फार्म को उच्चीकृत कर महन्थ श्री अवैद्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

जनपद महराजगंज स्थित चहरी फार्म राज्य सरकार का फार्म नहीं है। यह गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर फरेन्दा का है, जो वर्तमान में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन आफ इण्डिया (एन0टी0सी0) के अन्तर्गत निहित है।

प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा अध्यापकों को नियमित करने की मांग

19–श्रीमती सुषमा पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा अध्यापकों को नियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रकरण विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रायबरेली में मंडी समिति के माध्यम से सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में

20–श्री राम नरेश रावत–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली में मण्डी समिति के माध्यम से गत तीन वर्षों में बछरांवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कहां–कहां निर्माण कराया गया है ?

श्रीमती स्वाती सिंह–

जी हां, जनपद–रायबरेली में मण्डी समिति के माध्यम से गत तीन वर्षों में बछरावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र एक नग सम्पर्क मार्ग राजापुर से गुरुकुल महाविद्यालय होकर हल्लौर पुरासी मार्ग का निर्माण कराया गया है।

नोएडा शहर के सेक्टर 21, 25, 28, 29 और 37 में बह रहे गंदे नाले से हो रही समस्याओं के संबंध में पत्र दि0 24–4–2017 पर कार्यवाही की मांग

21–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा शहर सेक्टर 21, 25, 28, 29 और 37 में बह रहे गन्दे नाले से हो रही समस्याओं विषयक प्रश्नकर्ता के पत्रांक 49/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 व पत्रांक 63/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 24 अप्रैल 2017, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

प्राधिकरण की आख्या दिनांक 11.07.2017 के अनुसार सेक्टर–21, 25, 28, 29 तथा 37 के निवासियों की खुले नालों से हो रही समस्या एवं नालों की सफाई आदि बिन्दुओं के दृष्टिगत एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट के पश्चात ही नोएडा क्षेत्र में नालों की समस्या के निवारण की कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त सेक्टर–21 एवं 25 में विद्युत केबिलों को भूमिगत करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेक्टर–21 एवं 25 काफी

पुराने सेक्टर हैं, जिनकी सड़कों की चौड़ाई काफी कम है। इन सड़कों के नीचे पानी की लाईन, सीवर, टेलीफोन लाइन गुजर रही है। पर्याप्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण भूमिगत केबिल डालने का कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की राजकीय कालोनी बादशाहनगर में बने आवासों की मरम्मत, रंगाई, पुताई कराने की मांग

22–श्री अमिताभ बाजपेई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ, यू–ब्लाक में बने आवासों की मरम्मत, रंगाई–पुताई काफी समय से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रंगाई–पुताई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ के यू–ब्लाक में बने आवासों की मरम्मत रंगाई–पुताई का कार्य आवश्यकतानुसार समय–समय पर कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित नोएडा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना

23–श्री पंकज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित नोएडा में खारा पानी की वजह से लोगों को पेयजल की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाकर वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक एवं किस योजना के तहत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

नोएडा क्षेत्र के कतिपय नेटवर्कों में खारे पानी की शिकायत है।

90एम0एल0डी0 (37.50 क्यूसेक) की गंगाजल योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे वर्ष–2020 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस प्रकार वर्ष 2021 तक के लिए गंगाजल के नियोजन 330 एम0एल0डी0 को समय से पूर्ण कर लिया जायेगा। यह जलापूर्ति मास्टर प्लान भारत सरकार की संस्था मेसर्स वाप्कोस (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा तैयार किया गया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.00, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाऐं लेता हूं।

आज दिनांक 13–07–2017 को कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई। जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई।

पहली इन्जी0 बृजेश कठेरिया की जनपद–मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में समाना पंछी विहार की भूमि अधिग्रहण की अवशेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट की जनपद–लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम–आनन्दपुर, मउरा हुलासखेड़ा से कनकहा तक खड़न्जा पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसरी श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद–कानपुर नगर के अन्तर्गत आनन्द स्वरूप पार्क वार्ड–59, सिविल लाइन्स में रख–रखाव व सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ग्राम–समरी व किशनपुर के मध्य नाले पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद–मेरठ के लौटी (सफियाबाद) के पास काली नदी पर पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठवीं श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद–खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड–ईसानगर के ऐरा शुगर मील के श्रमिकों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं डा0 जी0एस0 धर्मेश, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री राम प्रताप सिंह तथा श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद–आगरा की पेयजल की समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपिया को 100 शैय्या का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं श्री प्रमोद उटवाल की जनपद–मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बा में परिवहन डिपो न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं श्रीमती साधना सिंह की जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री राम अचल राजभर की जनपद–अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अकबरपुर अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के पूरब टन्ना–मन्ना गांव के पास शारदा सहाय नहर पर बनी पैदल पुलिया के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, बारहवीं श्री दलवीर सिंह की जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद–कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर स्थित अमराहट कैनाल योजना का द्वितीय चरण चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद–जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत बरही बम्बा से शहीदनगर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं श्रीमती लीना तिवारी की

जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं एवं रामपुर रोडवेज बसों का बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीः– श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री राजीव कुमार सिंह, श्रीमती बिमला सिंह सोलकी, श्री नरेश सैनी, श्री तसलीम अहमद, श्री रितेश पाण्डेय, श्री अनिल सिंह, श्री सुखदेव राजभर, श्री उमाशंकर सिंह, श्री मसूद अख्तर, श्री मूलचन्द्र सिंह, श्री सुभाष पासी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री संजय प्रसाद जायसवाल, श्री राहुल प्रकाश, श्री संगम लाल गुप्ता की।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाऐं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में समाना पंछी विहार की भूमि अधिग्रहण की अवशेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

इन्जी0 बृजेश कठेरिया–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में समाना पक्षी विहार के भूमि अधिग्रहण राशि के लिए पिछली सरकार ने पैसा दिया था। जोकि मुख्यालय पर है, अवशेष धनराशि सरकार द्वारा किसान हित में जारी किया जाना अतिआवश्यक है। साथ ही किसानों को मुआवजा राशि वर्तमान भूमि अधिग्रहण नियम के तहत दिया जाना उनके हित में है। मुआवजा न मिलने से किसान आत्म हत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद–लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम–आनन्दपुर, मउरा हुलासखेड़ा से कनकहा तक खड़न्जा पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलाल गंज, अन्तर्गत ग्राम आनन्दपुर, मउरा हुलास खेड़ा से कनकहा तक शारदा नगर की पटरी का मार्ग खड़ंजा निर्माण हुआ था जो उखड़ गया है जिसकी लम्बाई लगभग 3 किमी0 है। स्थानीय जनता को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित में उपरोक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आनन्द स्वरूप पार्क वार्ड–59, सिविल लाइन्स में रख–रखाव व सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई–

ख्मान्यवर, जनपद कानपुर के अन्तर्गत आनन्द स्वरूप पार्क वार्ड 59 सिविल लाइन्स में रख रखाव व सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद–कानपुर नगर के वार्ड 59 सिविल लाइन्स में आनन्द स्वरूप पार्क स्थित है जिसमें स्थानीय लोग टहलने व बच्चे खेलने आते है। उक्त पार्क की स्थिति बहुत ही जर्जर है मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वही पर अराजक तत्वों का भी जमावड़ा लगता है एवं तत्काल पार्क की साफ सफाई व रख रखाव कराये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर सदन के माध्यम से तत्काल समुचित कार्यवाही किये जाने एवं शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ग्राम–समरी व किशनपुर के मध्य नाले पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्मान्यवर, जनपद फतेहपुर में खागा विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम सेमरी व ग्राम किशनपुर पम्पकैनाल के मध्य नाले में पुल तथा ग्राम चन्दापुर गढ़ा व ग्राम बलवन्तपुर बरार के मध्य नाले में पुल के अभाव में एक–दूसरे क्षेत्र का सम्पर्क टूटा हुआ है, जिससे जनमानस तथा कृषकों को प्रतिदिन नाला पार करने हेतु दूर का चक्कर लगाकर आने–जाने में समय, श्रम व धन का अपव्यय हो रहा है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।,

जनपद मेरठ के लौटी (सफियाबाद) के पास काली नदी पर पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर जनपद मेरठ में लौटी (सफियाबाद) ब्लाक खरखौदा अन्तर्गत काली नदी पर पुल का निर्माण न होने के कारण आम जनमानस को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। काली नदी के दूसरी तरफ जाने हेतु जनमानस को काफी चक्कर लगाकर आना–जाना पड़ता है। लोग चक्कर लगाने से बचने के लिए जुगाड़ करके उस पार अपने कार्यों के निष्पादन के लिए जाते हैं जिससे कई बार दुर्घटनायें हो जाती है। इस लिए काली नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लौटी के पास काली नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

---

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड ईसानगर के ऐरा शुगर मील के श्रमिकों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–ईसानगर के अंतर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया स्थित है। उक्त ऐरा शुगर मिल में सैकड़ों की संख्या में दैनिक मजदूर तथा सीजनल मजदूर व श्रमिक कार्य करते हैं। ऐरा शुगर मिल द्वारा श्रमिकों से वेतन बाउचर पर हस्ताक्षर कराकर सरकार द्वारा घोषित मजदूरी न देकर कम मजदूरी का भुगतान करके श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। सरकार द्वारा घोषित मजदूरी का भुगतान किये जाने हेतु ऐरा शुगर मिल के श्रमिकों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी की गयी और न ही दोषियों के विरुद्ध श्रमिकों एवं क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से ऐरा शुगर मिल के हित में सरकार द्वारा घोषित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं तथा दोषी ऐरा शुगर मिल के प्रबन्धक, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।,

जनपद आगरा की पेयजल की समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0एस0 धर्मेश, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री राम प्रताप सिंह, श्री जितेन्द्र वर्मा–

[मान्यवर, आगरा में पेयजल समस्या बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। यमुना नदी में पानी है ही नहीं। शहर के नालों का गंदा पानी ही यमुना में रह गया हैं। आगरा भू–गर्भ जल स्तर गिरता जा रहा है। आम जन मानस पेयजल संकट से त्रस्त है। जब तक यमुना नदी में पेयजल का एकत्रीकरण करने हेतु बैराज का निर्माण नहीं कराया जाता तब तक पेयजल समस्या का निदान हो पाना बहुत कठिन है। बैराज बनाकर जल के एकत्रीकरण से जहां एक तरफ पेयजल समस्या का निदान होगा वहीं दूसरी तरफ भू–गर्भ जल स्तर के गिरावट में भी कमी आयेगी। जनहित में आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाकर पेयजल समस्या का निदान कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करते हैं।,

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपिया को 100 शैय्या का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा–

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र गौरा काफी पिछड़ा क्षेत्र है। जिला मुख्यालय से 100 किमी0 दूरी पर स्थित होने के कारण आने–जाने के लिए 2 से 3 घंटा का समय लगता है। वहां पर स्वामी नरायन छपिया मन्दिर स्थापित है जो भगवान घनश्याम महराज की जन्मभूमि है। यहां पर गुजरात समेत पूरे देश–विदेश से भी काफी संख्या में तीर्थयात्री

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आते हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता के उपचार के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं है और न ही कोई नर्सिंगहोम है। इससे उपचार के अभाव में अक्सर लोगों की मौत भी हो जाती है। जनहित में एक 100 बेड का अस्पताल बनाने की आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बा में परिवहन डिपो न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूरकाजी कस्बा जनपद मुजफ्फरनगर में बार–बार अनुरोध करने पर परिवहन डिपो नहीं बन पाया है। नगरवासियों द्वारा शासन और परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनता के हित में कस्बा पुरकाजी में डिपो बनाना अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 380–मुगलसराय जिला चन्दौली में निम्न रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त है :–

1. चन्दौली से बबुरी बाजार तक (लगभग 14 किमी0)।
2. डी0आर0एम0 बिल्डिंग से रामनगर बाजार तक (लगभग 15 किमी0)
3. दुलहीपुर से वेदव्यास मन्दिर होते हुए पड़ाव तक (लगभग 8 किमी0)।
4. रामनगर इण्ड्रटियल्स रोड से हमिदपुर पटनवा तक (लगभग 5 किमी0)।
5. जगदीश सरायं से बहेरा खुरखुजा नकटी होते हुए जगदीशपुर तक (लगभग 10 किमी0)।
6. पड़ाव से कुण्डाकलां होते हुए सहजौर तक (लगभग 12 किमी0)

यह रोड विगत 10 वर्षों से अत्यंत जर्जर स्थिति में है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अकबरपुर अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के पूरब टन्ना–मन्ना गांव के पास शारदा सहाय नहर पर बनी पैदल पुलिया के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामअचल राजभर–

[मान्यवर, जिला–अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर, ब्लाक–अकबरपुर अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के पूरब टन्ना मन्ना गांव के पास शारदा सहाय नहर पर बनी पैदल पुलिया अत्यन्त सकरी है। उक्त पुलिया के दूसरी तरफ प्राइमरी पाठशाला है, दोनों तरफ गांव बसे हुए है, पैदल सकरी पुलिया के दोनों तरफ क्षेत्रीय जनता की काफी भूमि स्थित है जिस पर खेती होती है, उक्त पुलिया सकरी होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों के टैक्टर आदि वाहन नहीं निकल पाते हैं, उक्त पैदल पुलिया से दर्जनों गांवों के लोगों को आना जाना पड़ता है। पैदल पुलिया सकरी होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी होती है। आपातकालीन स्थिति में खाट पर लिटा कर मरीजों को नहर पार कराया जाता है। बच्चों एवं क्षेत्रीय जनता को संकरी पुलिया से दोहरी नहर पार करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा रास्ता को सुगम बनाने हेतु उक्त पैदल पुलिया को चौड़ीकरण करने हेतु उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक सकरी पैदल पुलिया को चौड़ीकरण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सरकार से उक्त पैदल पुल को चौड़ीकरण करने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ के निम्न लघु सेतु/पुलिया अति क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण भविष्य में कोई भी बड़ी दुर्घटना संभावित है एवं जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

1. दौरऊ मोड़ पिसावा के किमी–4 में लघु सेतु का पुनर्निर्माण।

2. गभाना–बरौली मार्ग के किमी–5 में क्षतिग्रस्त पुलिया संख्या 5/2 का पुनर्निर्माण।

3. गभाना–बरौली मार्ग के किमी–6 में क्षतिग्रस्त पुलिया संख्या 6/1 का पुनर्निर्माण।

4. कटरा बरौली मार्ग के किमी–8 में क्षतिग्रस्त पुलिया संख्या 8/1 का पुनर्निर्माण।

5. कटरा बरौली मार्ग के किमी–3 में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर स्थित अमराहर कैनाल योजना का द्वितीय चरण चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार कटियार–

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद–कानपुर देहात में स्थित अमराहट कैनाल योजना का द्वितीय चरण चालू करवाने हेतु आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इसके चालू होने से जनता का काफी लाभ होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि इस योजना का द्वितीय चरण तुरन्त चालू करवाने की कृपा करें।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत बरही बम्बा से शहीदनगर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्रपाल सिंह–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान मेरी विधान सभा कालपी, जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा में बरही बम्बा से शहीदनगर मार्ग लम्बाई लगभग 14 किमी0 है, जो कि बहुत ही खराब है। यह मार्ग जनपद हमीरपुर को जोड़ता है। जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः इस सड़क का जीर्णोद्धार करने का कष्ट करें।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं एवं रामपुर रोडवेज बसों का बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहती हूं कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं एवं रामपुर रोडवेज बसों का बस स्टैण्ड न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां की क्षेत्रीय जनता को निजी बसों से यात्रा करनी पड़ती है जिससे जनता का समय नष्ट होने के साथ–साथ मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।

अतः मैं जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं एवं रामपुर में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।,

ख्12.04, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब नियम–300 की सूचनाएं लेते हैं।

आज दिनांक 13 जुलाई, 2017 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचना प्राप्त हुयी।

पहली श्री अगयश रामसरन वर्मा की पूर्व मा0 सदस्य विधान सभा एवं अधिकारियों के नाम से आवंटित गैराज किराये पर धोबियों, नाईयों, वस्त्र विक्रेताओं आदि को आधिपत्य प्रदान किये जाने से गैराज में सरकारी बिजली, पानी एवं आवास के रूप में प्रयोग किये जाने से दूसरे मा0 सदस्यों को कथित गैराज आवंटित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री रितेश पाण्डेय की विधान सभा की आनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली के अन्तर्गत मा0 सदस्यों के लिए आनलाइन प्रश्न पूछने की सुविधा

नोटः–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सप्ताह के सातों दिन चौबिस घंटे उपलब्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में है तथा तीसरी श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की आय–व्यय पर साधारण चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की है। मा0 अगयश रामसरन वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे।

पूर्व मा0 सदस्य विधान सभा एवं अधिकारियों के नाम से आवंटित गैराज किराये पर धोबियों, नाईयों, वस्त्र विक्रेताओं आदि को अधिपत्य प्रदान किये जाने से गैराज में सरकारी बिजली, पानी एवं आवास के रूप में प्रयोग किये जाने से दूसरे मा0 सदस्यों को कथित गैराज आवंटित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने गैराज आवंटन जो विधायकों तथा अधिकारियों के आवासों पर हैं के संबंध में मुझे ग्राहयता पर उद्गार व्यक्त करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मा0 विधायकों और अधिकारियों के आवासों में जो गैराज हैं वह पूर्व विधान सभा सदस्यों को अधिकांशतः आवंटित हैं। जिन्होंने यह सारे गैराज या तो किराये पर उठा रखे हैं या गैराज को उठाने में कोई न कोई प्रतिकर प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार से गैराज इन्होंने धोबियों, नाईयों, वस्त्र विक्रेताओं, होटल स्वामियों आदि को आधिपत्य में दे रखी हैं। यह सारे के सारे व्यवसायी सरकारी बिजली और बिजली के साथ–साथ ही यह पानी का भी भारी दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ उस गैराज को आवास के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से सरकार का भारी क्षति हो रही है और यह काफी समय से क्षति हो रही है और एक प्रकार से यह क्षति अपूर्णीय है और इस क्षति की भरपाई की जानी चाहिए और साथ ही साथ इन गैराजों को खाली कराकर जो नये सम्मानित सदस्य विधान सभा हैं उनको आवंटित किया जाना चाहिए। ताकि उनके भी वाहन उसमें रह सकें और उनको विधान सभा आने–जाने में कोई असुविधा न हो। इस दृष्टि से गैराजों के आवंटन रद्द करके उनका पुनः आवंटन नये सदस्यों को किये जाये। यह हमारा अनुरोध है। धन्यवाद।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है लेकिन आपने कृपापूर्वक सुन लिया तो शासन ने इसका संज्ञान भी ले लिया और हम इसमें आवश्यक निर्देश जारी कर देंगे। लेकिन मान्यवर, यह नियम–300 में नहीं आता है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमने यह प्रश्न पहले भी प्रस्तुत किया था जिसमें मा0 अध्यक्ष जी ने और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इसमें कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हुयी है। इसलिए पुनः इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री अध्यक्ष–

पहले भी ऐसे दृष्टान्त हैं जब इस सदन की कार्यवाही से जुड़े प्रश्नों के बाहर की कोई बात यहां लायी गयी है तो उसे औचित्य का प्रश्न नहीं माना गया था। मैं वह दृष्टांत नहीं पढूंगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी सदाशयता के साथ खड़े होकर पहले ही पूरी बात कह चुके हैं। इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूँ। सरकार का ध्यान आकर्षण हो गया। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस पूरी व्यवस्था को आप लोगों के साथ बैठकर यथा नियम हल करें।

विधान सभा की आनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली के अन्तर्गत मा0 सदस्यों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पूछने की सुविधा सप्ताह के सातों दिन चौबीस घण्टे उपलब्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना मा0 श्री रितेश पाण्डेय जी की है।

श्री रितेश पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा की आनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली के अन्तर्गत मा0 सदस्यों को आनलाइन प्रश्न पूछने की व्यवस्था केवल सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक उपलब्ध होती है। सदन की अवधि में इस दौरान हम लोग सदन में ही रहते हैं और पांच बजे के बाद जब घर पर पहुंचते हैं तो फिर प्रश्नों को भेजने का कोई साधन नही मिलता है और साथ ही साथ जब सदन नहीं चलता है तो प्रायः जितने भी सदस्य रहते हैं वह अपने क्षेत्र के कार्यों में रात्रि 8–10 बजे तक लगे रहते हैं। और यह ऑनलाइन प्रणाली जो हम लोगों को दी गयी है इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि आनलाइन प्रणाली का मतलब यह होता है कि हम पेपरलेस या मानवश्रम को बचाने के लिए इस व्यवस्था को देते हैं और अगर हम शाम को रात को या चाबिसों घण्टे जब हमारा मन करे तब अगर हम अपने प्रश्नोत्तर आनलाइन नहीं चढ़ा पायेंगे। मान्यवर, यदि सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे के ब्रेकेट में रह करके और सोमवार से शुक्रवार के ब्रेकेट में रह करके इसको लागू करेंगे तो इसका कोई औचित्य बनता ही नहीं है, इससे बढ़िया तो जैसा अभी तक चलता आ रहा है कि लोग कागज ले करके दौड़ते हैं और आ करके यहां जमा करते हैं वही करना पड़ेगा। हम लोगों को यह सुविधा चौबीसों घण्टे और सातों दिन देनी चाहिए और इसका एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर कार्यवाही के बाद प्रश्न दिया जाता है तो उसको उसके दूसरे दिन की कार्यवाही में लिया जाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगर हमें पेपर लेस प्रणाली को तरफ बढ़ना है ओर मानव श्रम बचाना है तो इस व्यवस्था को चौबीसों घण्टे और सातों दिन देना चाहिए और मैं इसकी

मांग करता हूं। इसलिए मान्यवर, आप इस विषय को ग्राह्य करके इस पर उचित कार्यवाही कराने का काम करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

एक सुझाव के रूप में हमने इसे ग्रहण किया है और कतिपय कठिनाइयां हैं, यह औचित्य का प्रश्न तो नहीं बनता लेकिन हमारा सचिवालय इसका नये सिरे से पुनरीक्षण कर लेगा, अध्ययन कर लेगा और जो भी उचित होगा, वैसा किया जायेगा।

श्री रितेश पाण्डेय–

मान्यवर, प्रमुख सचिव जी से हमारी इस पर बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी उनसे जो बात हुई है, उसको यहां नहीं कहना चाहिए, यह परिपाटी नहीं है, उसको सदन में नहीं कहते हैं। आपके घर में भी यदि कोई बात हुई हो तो यहां नहीं बतानी चाहिए। (हंसी) यह घर का मामला है। लेकिन आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, हमारा सचिवालय इस पर विचार करेगा।

आय–व्ययक पर साधारण चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है।

'श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं नियम–300 के औचित्य के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सामान्य बजट पर नियमावली में कम से कम 5 दिन चर्चा का प्रावधान है और मदवाइज 24 दिन चर्चा कराये जाने का प्रावधान है। इधर सामान्य बजट पर जो चर्चा आपको मिल रही है, वह 03 दिन मिल रही है और मदवाइज बजट पर चर्चा करने को हमें 07 दिन मिल रहे हैं। आपसे हम आग्रह करना चाहेंगे और इस औचित्य के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और मदवाइज बजट की चर्चा को बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेन्द्र वर्मा जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, मान्यवर, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, पिछली बार तो जब इनको नियमावली की किताब दी गयी थी, वह खो गयी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार वह किताब खोयी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो बजट की सामान्य चर्चा है, उसमें 04 दिन का समय रखा गया है, 03 दिन का नहीं है, बजट की सामान्य चर्चा 04 दिन की है। इस पर एक दिन बात हो गयी थी कि यह 04 ही दिन रहेगी, वह आप करें और कार्य–मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से आपने यहां स्वीकृति भी दी थी, उसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

04 दिन की चर्चा है, दिनांक 13, 14, 18 और 19 अगर आप याद करें, 04 दिन इस पर चर्चा की बात हुई थी, आप भी थे और सभी दलों के माननीय नेता थे, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी भी थे।

श्री अध्यक्ष–

उसे सदन ने अनुमोदित किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, मान्यवर 04 दिन में चर्चा अनुमोदित हुई है और आपने कृपापूर्वक यह भी कहा था कि हम देर तक, 7.00 बजे तक 8.00 बजे तक बैठ लेंगे। तो 2–3 घण्टे का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, मान्यवर, मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य अपनी बात बजट के सम्बन्ध में रख देंगे और अनुदान मांगों के सम्बन्ध में तो हम अभी कई बार बैठेंगे, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा समय तक हो, कोई माननीय सदस्य ऐसे न रहें कि वह अपनी बात न कह पायें, यह हमारी कोशिश होगा और मान्यवर, इसका उद्देश्य भी यही है। मान्यवर, नियमावली में जो व्यवस्था है, वह सही है और हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग बोल लें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह औचित्य का प्रश्न है, हमारे पास नियमावली कल भी थी, परसों भी थी पिछले कार्यकाल में भी थी और आज भी है। खन्ना साहब जरूर इसको अब प्रस्तुत कर रहे हैं, जो देर रात तक सदन चलने की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी है, हमारे बड़े भाई भी हैं, हम लोगों का घर परिवार है, हम बार–बार कहते आये हैं और देर रात नौ–दस बजे तक इनको कोई काम नहीं है घर में, तो हमारा आग्रह है कि आप कार्यवृत्त बढ़ा दीजिए, हम लोगों के घर परिवार बाल–बच्चे हैं घर जाना पड़ता है, आपको भी जाना पड़ता है, तो खन्ना साहब इसमें जो शादी–शुदा हैं, उनको भी आप देखिये, आप केवल एक पक्ष लेकर चल रहे हैं कि रात नौ–दस बजे तक हाऊस चलता रहे, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, 90 दिन तो वैसे भी सदन चलना चाहिए, आगे शीतकालीन सत्र आयेगा और कोई सत्र तो होगा नहीं, तो थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, बड़े–बड़े जो विभाग हैं उन पर एक–एक दिन चर्चा हो जाय। वैसे भी गृह विभाग पर डेढ़ दिन चर्चा होती है, पी0डब्ल्यू0डी0 एक दिन लेता है, ऊर्जा एक दिन लेता है, जितने बड़े–बड़े विभाग हैं, एक–एक दिन पूरा उसमें दे दीजिए, उसमें सभी लोगों की बातें आ जायेंगी, सत्ता पक्ष भी कहना चाहेगा, हम लोग भी कहना चाहेंगे, इसलिए 90 दिन का सदन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है और इस आदरणीय सदन ने ही कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं, इस तरह का प्रसंग औचित्य के प्रश्न में नहीं आता, मैं 24 फरवरी, 1999 की कार्यवाही का अंश पढ़ रहा हूं, मा0 अध्यक्ष जी ने तब कहा था– ''सदन का कार्यक्रम और विभिन्न अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान की तिथियां कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सदन द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद सुनिश्चित हो जाती हैं,'' इसलिए इस पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आपका विषय आ गया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी घर के हैं, वह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

[12.17, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017[४]

पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

[12.18, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13–07–2017 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम एवं दूसरी सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा एवं तीसरी एवं चौथी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

प्रथम सूचना श्री रितेश पाण्डेय की प्रदेश की राजधानी में तेजी से फैल रहे डेंगू से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की प्रदेश में बालू, मौरंग, गिट्टी एवं मिट्टी खनन पर रोक के कारण विकास कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 संग्राम यादव की जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त भी पशु

---

४ दिनांक 18 जुलाई, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

चिकित्सा महाविद्यालय को अन्यत्र स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री संजय गर्ग की सम्पूर्ण प्रदेश में हस्तशिल्प द्वारा निर्मित लकड़ी की नक्काशी को जी0एस0टी0 के दायरे में लाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः–

1–श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह, श्री सोहिल अख्तर अंसारी,

2–श्री नितिन अग्रवाल,

3–श्री प्रभुनारायण सिंह यादव,

4–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

5–श्री संग्राम सिंह यादव,

6–श्री सुखदेव राजभर, श्री विनय शंकर तिवारी,

7–श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर,

8–श्री रफीक अन्सारी,

9–श्री सुभाष पासी तथा

10–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला।

'**श्री अजय कुमार लल्लू–**

माननीय अध्यक्ष जी, किसान कर्ज माफी पर मेरा नियम–56 में था, यह महत्वपूर्ण है अगर कार्य–स्थगन की सूचना पर इस सदन में चर्चा न हो। आज प्रदेश का किसान किन हालातों में है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कर्ज माफी का विषय नियम–56 में इसलिए नहीं आता कि कर्ज माफी बजट का बहुत बड़ा उल्लेखनीय भाग है और उस पर आपको बहुत देर तक बोलने का मौका मिलने वाला है।

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, उसमें एक समय–सीमा होगी और मुझे पूरे विषय पर बोलना होगा। किसान से सम्बन्धित कर्ज माफी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष–

जी यह बड़ा मुद्दा है और यह बजट का भाग है। अजय जी आप सुन नही रहे हैं, आप अध्यक्ष की बात भी नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मात्र 50 लाख किसानों की बात की गयी है। मात्र एक लाख रूपया कर्जा माफ किया गया है। सरकार इतनी पूर्ण बहुमत से आई है।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं आप विषय को घुमा रहे हैं। आप पहले हमारी बात तो सुनिये, आप कृपया हमें सुनिये। मैं बिनती करता हूं कि आप सुनिये। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ने माननीय विधान सभा के हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने बजट में शामिल प्रमुख विषयों पर उसके ठीक पहले नियम–56 को उचित नहीं माना। जब आज शाम से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। आपका भी हो सकता है आज ही शाम को बोलना हो और कर्ज माफी तो बजट का महत्वहपूर्ण भाग है और अगर आप इसे कहते हैं कि अविलम्बनीय है तो अविलम्बनीय का मतलब तत्काल नहीं होता। यह भी अर्सिकिन में से लेकर अब तक जितनी संसदीय कौलशकधर किताबें है आपका विषय अविलम्बनीय नहीं लगता, आपको आज ही तो बोलने का मौका मिलने वाला है।

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन चूंकि यह विषय पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा है। हमारे क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है। उस आत्महत्या के सवाल पर अगर हम किसानों की चिन्ता न करें, नौजवानों की चिन्ता न करें, आज इस सदन में इस पर चर्चा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, चर्चा के लिए ही तो सदन बना है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा 4 दिन चलेगी।

श्री अजय कुमार लल्लू–

चार दिन चलेगी तो यह चर्चा के लिए ही तो बना है। कर्ज माफी से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अध्यक्ष जी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने कल भी आपसे विनती की थी, आज भी आपसे विनती कर रहे हैं। हमने कल भी नियम–56 में दिया था और आज भी दिया है। पूरे प्रदेश में हजारों किसान जेल भेज दिये गये, उनका दोष क्या है ?

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें, आप माननीय रितेश पाण्डे जी को बोलने दीजिए। अजय जी आप क्या चाहते हैं कि हम सबको नियम–56 में सुने और नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, नेता कांग्रेस को बोलना है, वे न बोलें। आपकी बातचीत से यही लग रहा है। जो विषय आप उठाना चाहते हैं वह पूरी तरह से बजट का विषय है।

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक घण्टे तो उस पर बोलूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बोल चुके, आप तो आधा घण्टे से बोल रहे हैं, आप बिना अनुमति के किसानों की संख्या बता चुके हैं, धन बता चुके हैं, बिना अनुमति के तमाम बातें बता चुके हैं। वह बजट का भाग है।

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी इसी 11 तारीख को जिस दिन सत्र प्रारम्भ हुआ, पहले ही दिन माननीय वित्त मंत्री ने पूरा बजट प्रस्तुत किया। 36 हजार करोड़ रुपया किसानों के फसल ऋण मोचन के लिए इस बजट में सुनिश्चित किया गया और मान्यवर, जितने भी उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसान हैं, उनके फसल ऋण मोचन का निर्णय लिया गया है और जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा, वैसे ही अर्ध लघु एवं सीमान्त किसान फसल ऋण मोचन करेंगे। मान्यवर, इनको छपास की शौक लगी है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी आप बैठिये।

श्री अजय कुमार लल्लू–

अगर ये किसानों के प्रति इतना गम्भीर चिन्तावान हैं तो पंजाब की तरह 2 लाख रुपया किसनों का कर्जा माफ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय जी आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आप सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। आप कृपया बैठें। आप नये माननीय सदस्य को बोलने दें। आप बाद में भी अपनी बात कह सकते हैं। मैंने मा0 सदस्य को पुकार लिया है पहले उनको बोलने दीजिए। क्या आप निर्णय का परिवर्तन कराना चाहते हैं ?

(सदस्य अजय कुमार लल्लू द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहने पर)

पहले आप बैठें। लल्लू जी, कृपया आप पहले बैठें, आप 15 मिनट से बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आप कृपा करिए, इस सदन पर कृपा करिए, हम पर कृपा करिए और आप बैठिए। आप सबको बजट में पूरा समय मिलेगा। अब आप बैठिए, आपने 10 मिनट ज्यादा ले लिए हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अब चार लोग एक साथ खड़े हो गए। बताइए मैं कैसे कण्ट्रोल करूं, मैं कैसे करूं। अब आप भी खड़े हो गए। पहले आप लोग बैठें।

(सत्तापक्ष के कतिपय सदस्य द्वारा यह कहा गया कि प्रश्न ग्राह्य नहीं है, उसका निर्णय आ चुका है तो किस व्यवस्था के तहत बोल रहे हैं ?)

आप लोग बैठिए। आप सब बहुत पढ़ने वाले विधायक हैं। आप लोगों को सुन लेंगे कभी, बैठिए। पहले उनका आने दीजिए, वादा काहे कराते हैं, बैठिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि बजट पर कार्यवाही न हो। क्या यह नहीं है कि आप नियम–56 में जो हमने

निर्णय लिए हैं उनको आप चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सुन लिया जाए। आप सब बैठ जाइए, आप सब हमारे सदन के तेज–तर्रार और सुयोग्य विधायक हैं। कृपया आप लोग बैठिए।

'**श्री दुर्गा प्रसाद यादव**–

मान्यवर, एक आजमगढ़ का महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आजमगढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कृपया बैठ जाइए। सभी हमारे साथी है। आप लोग बैठें, नये सदस्य को लग रहा होगा कि उनको दल वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया अब आप लोग बैठें।

'**श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा**–

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हम दिन भर सुना ही तो करते हैं। हम इतना सुनते हैं कि सुना ही करते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, बहुत ही आवश्यक विषय है।

श्री अध्यक्ष–

सबसे पहले आप लोगों का बैठना आवश्यक है।

श्री रितेश पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा लगातार खड़े रहकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप उन मा0 सदस्य को बाधित कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों इसी में बोलना जरूरी मान रहे हैं। अब आप लोग बैठिए। आप लोग जितनी सूचनाओं को कहेंगे, हम सब पर ध्यान आकर्षित कर देंगे लेकिन आप लोग बैठ जाइए। सब पर ध्यान आकर्षण कर देंगे, आप कृपया बैठ जाओ। हम आपकी बिल्कुल सुनेंगे, आप 6 बजे के बाद बैठिए हमारे साथ, हम पूरा तीन घण्टा सुनेंगे।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर बैठ जाने पर)

आप सबने बड़ी कृपा की इतने परिश्रम के बाद।

श्री रितेश पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय और लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल ही डेंगू से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और करीब 19 लोग डेंगू से इन्फेक्टेड हो रखे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। लोगों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। खासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं क्योंकि ये बच्चों, खासतौर से स्कूली बच्चों में बहुत तेजी से फैलता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसको रोकने के लिए स्कूलों को एलर्ट किया गया है। लेकिन वे भी अभी अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यहां तक कि अस्पताओं के बाहर भी डेंगू के लारवा पाए जा रहे हैं। डेंगू से पिछले साल ही लखनऊ में करीब 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं मानता हूं कि करीब हजारों लोगों की मृत्यु हुई होगी। मेरे क्षेत्र में ही करीब 50 लोगों की मृत्यु डेंगू से हुई थी। जिला अस्पतालों में खून की जांच के लिए या डेंगू की जांच के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कराई गई हैं कि वहां पर जा करके खून का सस्ता सैम्पल लिया जा सके और फ्री में जांच हो सके। वहां पर जो गरीब किसान पहुंचता है जब खून की जांच की बात आती है तो उससे कहा जाता है कि आप बाहर जा करके खून की जांच करवा लीजिए। उसको मौके पर खून की जांच के लिए फ्री में कोई भी सुविधा नहीं मिलती जिसके कारण वायरल की दवा खा कर उसकी मृत्यु हो जाती है और डेंगू के लिए डाइगनोस ही नहीं हो पाता है।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्य द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री रितेश पाण्डेय–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह पूरे प्रदेश की बात है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा भी सीरियस नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी तरफ मुंह करके बोलिए। आप कृपया हमारी ओर देखिए, उधर नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय–

मान्यवर, कहीं न कहीं इस विषय पर हमें चर्चा करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष–

एक मा0 सदस्य बोल रहे हैं और उनके पड़ोस में बैठे लोग आपस में बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह मा0 सदस्य बोल रहे हैं और हमारे तीन मित्र सदस्य, जो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं वे तीनों इनके बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं। अब आप बताइए।

श्री रितेश पाण्डेय–

डेंगू का प्रकोप दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है इससे प्रदेश पिछले सालों में पूरी तरह से ग्रसित रह चुका है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर एक विस्तार चर्चा कराई जाए जो इसके रोकथाम के लिए जरूरी है क्यों कि अब से लेकर सितम्बर तक ये रोग फैलने का काम करेगा। इसके रोकथाम के लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या योजना रहेगी इस पर पूरी डीटेल चर्चा होनी चाहिए इसकी मैं मांग करता हूं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थनाथ सिंह)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो विषय है बहुत गंभीर है। माननीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि गंभीरता से ही इसका जवाब दूं। कुछ आंकड़े आपने पहले दिये हैं उसको मैं विस्तार से आपके बीच रखना चाहूंगा। जब डेंगी की 2015 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 3101 रिपोर्ट आई थीं, उसमें 10 मृत्यु हुई थी। वर्ष 2016 के अन्दर 15033 रिपोर्ट आई थीं, जिसमें हजार नहीं मगर 42

मौतें हुई थीं। यह आंकड़े पिछली सरकार के हैं फिर इस साल अभी तक जो आंकड़े आए हैं, मैं 11.07.17 तक की बात करूंगा तो 104 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें तीन डेथ हुई हैं जिसमें से एक का आपने भी जिक्र किया है। विषय यह बनता है कि सरकार क्या कर रही है उसके लिए मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से क्योंकि यह हर साल आता है ऐसी कोई नई चीज नहीं है। हर साल आती है। कभी–कभी हम सब लोग एक प्रोएक्टिव मोड में न जाते हुए रिएक्टिव मोड में रहते हैं इसलिए अप्रैल के महीने में हम लोगों ने मुख्य सचिव के अधीन एक कमेटी केन्द्र में अर्थात् लखनऊ में गठित की, जिसको हाईपॉवर कमेटी कहते हैं। साथ ही–साथ डिस्ट्रिक्स लेविल पर भी जिलाधिकारी के तहत हम लोगों ने ऐसी ही कमेटी गठित कर दी है। इस साल हम लोगों ने तैयारी के रूप में 4 करोड़ 12 लाख हम लोगों ने ज्यादा पैसा रिलीज किया। ज्यादा दिया और केन्द्र सरकार से भी 88 लाख हम लोगों ने लिया है और यह इसलिए लिया है कि जो महसूस हुआ है हमेशा कोई मशीन होती है एण्टी लार्वा की, स्प्रे करने की जो फागिंग मशीन होती हैं वह कहीं न कहीं कम पायी जाती हैं तो उसको समय से पूर्व हम लोग खरीद लें और नये जो आपने कहा उसको एण्टी लार्वा या जो ये पैरासाइट होते हैं, बैक्ट्रियां होते हैं उनको टेस्ट करने की 13 एस0एस0डी0 लैब्स् भी हम लोगों ने यहां पर बनाई है। साथ–ही–साथ अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ था। सरकार की तरफ से नोटिफाइड करवाया और उसको इनफोर्स करवाया। नोटिफाइड मैं मानूंगा कि पिछले साल यह हो चुका था। नवम्बर के आस–पास हुआ था मगर उसको लागू जमीन पर नहीं करवाया गया था। आप कहीं अखबार पढ़ते हैं तो आज लखनऊ में भी आप पढ़ेंगे, उसके अन्दर भी पिछले एक हफ्ते से हम लोग कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, जहां पर नोटिसेस दे रहे हैं, वहां पर सीलिंग करने या उनको पेनाल्टी भी लगाने की बात कर रहे है जो पेपर में बड़ी मात्रा में आ रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जो सी0एम0ओज के आधार पर नीचे तक ये ले जाएंगे कि डॉक्टर्स या सी0एच0सीज् हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं इस प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज करेंगे और यह प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं। कल के0जी0एम0यू0 में जो डेथ हुई है, उस केस के सम्बन्ध में आपको एक जानकारी दे दूं और यह गंभीर विषय भी है। के0जी0एम0यू0 में जो डेथ हुई है उसकी मृत्यु के क्या कारण हैं, उसके साथ–साथ सी0एम0ओ0 को यह भी आदेश दिया गया है कि आप चेक करेंगे **जो** प्रोटोकाल हम लोगों ने पास किया है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, यदि नहीं हुआ तो सदन के बीच में मैं कह रहा हूं कि कार्यवाही होगी। इसके साथ ही जो कभी पहले नहीं हुआ है, हम लोगों ने रिस्पॉस टीम बनायी है क्योंकि घटना सिर्फ लखनऊ में नहीं होती, कहीं भी होती है मगर रिस्पॉस टीम को, जहां भी घटना होती है तुरन्त वहां पर भेजा जाता है। वहां पर 100 मीटर के दायरे के अंदर पूरा इंस्पेक्शन होता है कि पानी कहीं कलेक्ट है या जो लार्वा है, वह पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ ही हर हफ्ते एण्टी मॉस्किटो ड्राइव चल रही है। एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अलग से हर डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अन्दर 10 बेड अलग से कर दिए गए हैं, 5 बेड सी0एच0सी0 में करवा दिए गए हैं। मरीज को यदि बुखार तेज है और वह लम्बी लाइन में लगेगा तो

दिक्कतें आएगी, इसके लिए अलग से एक हेल्प डेस्क बनवा दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। जेई वेक्सिनेशन एक और बीमारी है चूंकि यह इससे सम्बन्धित नहीं है, मैं जेई वेक्सिनेशन में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि एक लक्ष्य था कि 88 लाख बच्चों को 38 डिस्ट्रिक्टस के अंदर उनको वेक्सिनेशन करेंगे। मुझे सदन को बताते हुए खुशी होती है कि 1 करोड़ 3 लाख बच्चों को हम लोगों ने, यह शायद पहली बार हो रहा है कि वेक्सिनेशन प्रोग्राम 103 प्रतिशत हुआ है यह भी हम लोगों ने किया है। यह अलग बात है मगर मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है और मैं कहना चाहता हूं कि यह स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ विषय है। जहां पर पानी इकट्ठा होता है, एक छोटा सा कप या ढक्कन जिसमें 5 एम0एल0 का पानी आता है यदि उसको भी आप रख लेंगे तो उसके अंदर भी लार्वा पैदा हो जाता है। इन चीजों का सभी लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत व्यापक बता दिया अब क्या बचा है ?

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मरीज यदि अस्पताल में जाता है तो उसको ब्लड टेस्ट देने के लिए बाहर भेजा जाता है। ब्लड टेस्ट से डेंगू का डायग्नोसिस हो सकता है। ब्लड टेस्ट मंहगे होते हैं और गरीब किसान जो लाचार है और उनके पास ब्लड टेस्ट के लिए उतना धन नहीं है। तो क्या सरकार इन लोगों के ब्लड टेस्ट जो डेंगू की जांच के लिए होता है उसकी सुविधायें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या सी0एच0सी0 में देने का काम करेगी ?

श्री सिद्धार्थनाथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है वहां पर प्रत्येक अस्पताल के अन्दर उपचार की व्यवस्था रखी गयी है। ब्लड टेस्ट की भी व्यवस्था रखी गयी है, प्लेटलेट्स की भी जहां जरूरत है उसकी भी व्यवस्था की गयी है। सभी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है मगर पूरा प्रयास है कि ब्लड हम लोग डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, जहां डिजिटल नहीं है वहां पर बोर्ड के माध्यम से ब्लड की एवेलिबिलिटी भी रखें और वहां पर उनके नम्बर्स भी रखें।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

तो ब्लड्स की आपको कोई जानकारी आती है, जहां कोई गया है क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेण्ट बहुत भारी पड़ जाता है, तो कहीं आपके पास कोई जानकारी आयी है जहां पर कोई गया है और वहां पर उसको ब्लड टेस्ट करने के लिए उसको बाहर भेजा है और वहां पर उससे ज्यादा पैसा लूटा जा रहा है तो कृपा करके आप मुझे अपने लेटर हेड पर दे दीजिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उस पर कार्यवाही जरूर करूंगा।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी जो नियम–56 की सूचना माननीय रितेश पाण्डेय जी की आयी थी उस पर बहुत विस्तृत जवाब और सरकार के द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत कराया। मान्यवर, यह बहुत दुखद है कि डेंगू से जो भी केस सामने आए हैं लेकिन इसके इलाज से ज्यादा इसका बचाव बहुत जरूरी है और इसलिए हम आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अपील करना चाहते हैं कि जो इस बीमारी का कारण बताया गया उसके प्रति सभी माननीय सदस्य इस बारे में सचेत रहें कि कहीं पर इस प्रकार का पानी या कहीं इस प्रकार की गन्दगी इकट्ठा न हो। जिससे डेंगू का लारवा पैदा हो, यह अपने आप में बहुत दुःखद है लेकिन सरकार पूरी तरह से सचेत हैं और हर स्थित से निपटने के लिए हमारे पास पूरे इंतजाम हैं हम हर स्थिति में हर मौके इसके लिए पूरी सजगता के साथ पूरी सावधानी के साथ इसका उपचार भी करेंगे और इसके बचाव का प्रबन्ध भी करेंगे यह नियम–56 में नहीं आता है इसलिए इसमें हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी एक सूचना आजमगढ़ की है उसको आप ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

अमन मणि जी नहीं है इसलिए दुर्गा प्रसाद यादव जी की सूचना ली जाती है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। हमारे आजमगढ़ जिले में 2012–13 में हमारी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ जिले के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया था लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा पशु वेटेनरी हास्पिटल है इस हास्पिटल को दूसरी जगह ले जाने का काम किया है मैंने कल भी सूचना दिया था लेकिन वह नहीं आ सकी। यह बहुत गम्भीर मामला है। इससे हमारे सभी आजमगढ़ के एमएलए और आजमगढ़ की जनता दुखी है वहां की जनता में रोष व्याप्त है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उससे यह किसान जुड़ा हुआ था और यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय पूर्वान्चल में कहीं नहीं था। हमारी सरकार के माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वान्चल में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति देने का काम किया था अभी हाल में हमारे यहां जिला योजना की बैठक थी हमारे मौर्य जी गये थे जो पीडब्लूडी मंत्री है और उप मुख्य मंत्री भी हैं वह गये थे, उनके सामने मैंने इस मामले को उठाने का काम किया था कि आजमगढ़ का जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है इसको कहीं अलग ट्रांसफर करने का काम जो सरकार ने किया है वह न करे। मैं यह कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि अगर कहीं ले जाना है तो यह सरकार अपना विद्यालय ले जाने का काम करें हमारी सरकार ने जो हमारे आजमगढ़ में स्वीकृति दिया है उसको ले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं आपके संरक्षण में रहा हूं मैं 8 बार का एमएलए हूं लगातार मुझे इस सदन में आने का जनता ने मौका दिया है। पूर्वान्चल में इससे किसानों को लाभ मिलेगा पशुपालकों को लाभ मिलेगा, जनता को इससे लाभ मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं कल से ही आपसे निवेदन कर रहा था कि मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं बहुत–बहुत आभारी हूं और मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। आजमगढ़ में जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है इसको आजमगढ़ में ही रखने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसमें ध्यानाकर्षण किया था हलांकि इसकी डिटेल सूचना मेरे पास नहीं आई है लेकिन जो भी सूचना मेरे पास है माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने नियम–56 की सूचना के माध्यम से सदन में अपनी बात रखी है, उसके बारे में हम जानकारी दे दें। यह सही है कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा पिछली सरकार द्वारा की गयी थी और इसके लिये 77.02 एकड़ जमीन क्रय किये जाने के लिये लगभग 31.38 करोड़ रुपये धनराशि की आवश्यकता थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2012–13 तथा 2016–17 तक कुल 28.26 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। यह धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ के खाते में जमा है लेकिन आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने जब समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी, तभी दिनांक 02.01.2017 को यह सूचित किया था कि परियोजना हेतु चिन्हित भूमि में कतिपय कृषकों के नाम की प्रविष्टियां संदिग्ध पायी गयी। चूंकि जमीन जो चिन्हित की गयी थी, वह विवादित थी मान्यवर, इसलिये विवादित जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था तो जिलाधिकारी आजमगढ़ ने परियोजना हेतु इस भूमि को लिया जाना शासकीय हित में उचित नहीं बताया। अतः भूमि की उपलब्धता न होने के कारण यह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मान्यवर, जो परिस्थिति थी, हमने आपके माध्यम से अवगत करा दिया है और यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, यह जमीन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक्वायर की गयी थी और कुछ लोगों ने बैनामा भी कर दिया था । डी0एम0 ने क्या किया, क्या रिपोर्ट दी मुझे यह नहीं मालूम। मगर सरकार ने जमीन खरीदने के लिये पैसा भी दे दिया था और जमीन अगर विवादित थी तो जमीन कहीं और भी खरीदी जा सकती थी और महाविद्यालय को बनवाया जा सकता था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय है, इसको आजमगढ़ में ही रहने दिया जाय और इसे अन्यत्र ट्रांसफर न किया जाय।

'डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो इतनी बड़ी परियोजना आजमगढ़ के लिये स्वीकृत हुयी थी और धन भी आवंटित हो गया था। अब जिलाधिकारी ने क्या रिपोर्ट लगाई, वह माननीय विधायक जी को भी सूचित नहीं किये। लेकिन हम सबको जो सूचना है, वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में नहीं रख रहे हैं लेकिन कहीं यह बात आई, कि यह पूरी परियोजना गोरखपुर ले जाई जा रही है। गोरखपुर से माननीय योगी जी आते है और वह पूरी योजना गोरखपुर ले जाये जाने से आजमगढ़ की जनता में बड़ा आक्रोश है। इसलिये हमारी प्रार्थना है और संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं कि इस योजना को आजमगढ़ में ही रहने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें हमारा सुझाव है आप सब जो आजमगढ़ के माननीय विधायक है, आपके पास कुछ सूचनायें हैं और सरकार के पास भी सूचनायें हैं। तो आप सब किसी दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कक्ष में बैठकर अपने तर्क, तथ्य सारे रखिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुनने को तैयार हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, 02 जनवरी, 2017 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 02 जनवरी, 17 को जिलाधिकारी ने यह रिपोर्ट दिया था कि इस जमीन में जो कृषकों के मल्कियत के नाम हैं, उसकी प्रविष्टियां संदिग्ध पायी गयीं, तो यह आपकी सरकार के समय में जिलाधिकारी की रिपोर्ट है जहां तक पैसे का सवाल है हमारे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार 31.38 करोड़ धनराशि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2012–13 से 2016–17 में मात्र 28.26 लाख रुपये की धनराशि रिलीज हुयी। अब सवाल यह है कि मात्र 28 लाख रूपये में इतने बड़े पशु चिकित्सा विज्ञान महा विद्यालय की स्थापना कैसे होगी। 2012–13 में इसकी घोषणा हुयी, अगर यह मान्यवर, सीरियस होते तो यह 2012–13 में इसकी घोषणा के बाद इसे पूरा करवा देते और ऊपर से नाम हमारे मुख्य मंत्री जी का ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, यह नहीं होना चाहिए। यह पूरे सदन को भ्रमित करने वाली बात है अगर इनकी ढकोसली घोषणा न होती तो मान्यवर, 2012–13 की घोषणा और 2016–17 तक 28 लाख रुपए रिलीज हुए और उसके बाद 2 जनवरी, 2017 को इन्हीं के सामने यह आ गया था इसलिए यह सारा कुछ जो कर्मकाण्ड है यह इन्ही की सरकार का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। जमीन चिन्हित इनकी सरकार में हुई, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी इन्होंने नामित किया, जिलाधिकारी इनकी सरकार के थे, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है, यह आपके सामने है। इसलिए मान्यवर, यह नियम–56 में नहीं आता है।

(सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में मैंने इसे अग्राह्य किया। आपको अगर कोई और बात करनी है तो मैंने कह दिया है कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी के साथ आप बात कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इन्होंने जो स्पष्टीकरण मांगा था जो अपनी तरफ से शंकाएं व्यक्त की थीं उसका जवाब हमने दे दिया है इसलिए इस पर अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलना है और आप देख रहे हैं कि वह काफी तरोताजा हो करके आये हैं, आप उनके चेहरे की तरफ देखिये कि चमक रहा है या नहीं। अब आप बैठ जाएं, मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है दो मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

हम आपकी सूचना पर ध्यानाकर्षण किये देते हैं।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, विषय बहुत गम्भीर है, हमारे जनपद में लकड़ी की नक्काशी का काम लोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

उसे आप अगले दिन दे दीजिएगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें। यह विषय दस्तकारी से सम्बन्धित है, इन लोगों की पूरी व्यवस्था इस पर निर्भर है। लकड़ी की नक्काशी और हस्तशिल्प पर आज तक कोई कर नहीं लगा। हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते इसलिए हमें रोजगार छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ये चाइना से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जी0एस0टी0 काउंसिल में लकड़ी की नक्काशी को करमुक्त श्रेणी में रखा जाए। वास्तविक लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर लोग घरों में रखना पसन्द करते हैं। यह लाखों लोगों के रोजगार का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी पूरी बात आ गई, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री संजय गर्ग–

पिछली सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने वास्तविक लकड़ी से बने फर्नीचर को भी इसे करमुक्त रखने का प्रावधान किया था लेकिन ऐसा करके इन लोगों को हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जी0एस0टी0 काउंसिल में लकड़ी की नक्काशी से निर्मित वस्तुओं को कर के दायरे से बाहर रखा जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई है, अब आप कृपया आसन ग्रहण कर लें।

'**श्री रफीक अन्सारी–**

मान्यवर, मेरा विषय बहुत गम्भीर है तीन दिन से।

श्री अध्यक्ष–

आप भी बैठ जाएं, आप कल दे दीजिएगा।

श्री रफीक अन्सारी–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आप आज ही शाम को दे दीजिएगा, मैं कल ले लूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, इनका बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इनकी सूचना को कल ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले आपको तो सुन लें।

श्री रफीक अन्सारी–

मान्यवर, मैं पहली बार सदन में आया हूं, मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप आज के उपवेशन के बाद हमसे मिलें। वित्तीय वर्ष 2017–2018 का जो बजट यहां माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उस पर नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी अपने विचार रखेंगे।

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अध्यक्ष जी, एक परम्परा रही है कि बजट भाषण के ऊपर जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन उपस्थित रहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह आ रहे हैं, उनके आने की सूचना है। तब तक माननीय सदस्य रफीक अंसारी जी अपनी बात कह लें।

श्री रफीक अन्सारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ के अन्दर 9 जुलाई, 2017 को एक घटना घटित हुई। हम सब राजनीतिक लोग हैं, एक पार्षद, जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुनकर आता है। निश्चित रूप से जितने लोग बैठे हैं सबका सियासी विरोध होता है, सियासी दुश्मनी होती है। सरेआम भरे बाजार के अन्दर शाम को 6.00 बजे और वहां से थाने का रास्ता सिर्फ 01 मिनट का है जहां पर यह घटना हुई। गुण्डे व शूटर आते हैं, नाई की दुकान पर पार्षद बाल कटवाने जाता है। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता जो घर पर बाल कटवाता हो, मेरे जैसा फकीर आदमी, हम तो दुकान पर ही जाते हैं। लेकिन दुकान पर जनप्रतिनिधि की हिफाजत नहीं होती, शूटर आते हैं और दनादन गोली चलाकर पार्षद और उसके साथी की हत्या कर दी जाती है। एक घण्टे तक उसकी डेड–बॉडी वहीं पड़ी रहती है जबकि वहॉ से थाने का रास्ता मात्र एक मिनट का है। दो चौराहे हैं जो दो बजे तक खचाखच भरे रहते हैं, एक घण्टे के बाद पुलिस आती है और डेड–बॉडी को ले जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम जनप्रतिनिधि क्या दरवाजे बन्द करके घर में रहेंगे ? यहां जितने भी लोग हैं हमारी सबकी सियासी दुश्मनी रहती है। आज जमाना ऐसा है कि गुण्डा एलीमेण्ट राजनीति में आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका विषय आ गया।

श्री रफीक अन्सारी–

मान्यवर, अभी मेरा विषय नहीं आया है, बड़ा गम्भीर विषय है, एक मिनट सुन लीजिए। हम सबका राजनीतिक विरोध होता है अगर हम लोग जनता के बीच में नहीं जायेंगे तो हमारी कौन सुनेगा ? आप जैसे फकीर हम लोग जनता के बीच में कैसे सेफ रहेंगे। आज पैसा देकर शूटरों से गोलियां बरसवा दी जाती हैं और दिन–दहाड़े पार्षद और उसके साथी की हत्या कर दी जाती है लेकिन आज तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 15 घण्टे के अन्दर एक और घटना हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र मेरठ में होती है उसमें भी दो लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसमें भी कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, अब आप बैठें।

श्री रफीक अन्सारी–

मान्यवर, यह मेरठ का बहुत ही गम्भीर विषय है, 15 घण्टे के अन्दर 4 कत्ल हुए। मैं 6 महीने पहले मा0 मौर्या जी को सुनता था, कहते थे कि लॉ–एण्ड–आर्डर खराब है, गुण्डाराज है। मैने नहीं सुना लेकिन मैंने मेरठ की धरती पर देखा है गुण्डाराज और जंगलराज। 15 घण्टे के अन्दर 4–4 कत्ल हो गये परन्तु सरकार इस पर कतई गम्भीर

नहीं है और कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मा0 योगी जी बैठे हैं, बहुत गम्भीर विषय है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर कत्लेआम हो रहा है और सरकार गूंगी–बहरी बनकर बैठी हुई है, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। आपने एक मिनट कहा था 3 मिनट हो गया। अब आपसे विनती है, आग्रह है कि आप बैठें।

श्री रफीक अंसारी–

अध्यक्ष जी, मुझे आपने पहली बार बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आपका बहुत धन्यवाद, अब आप बैठें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो घटना आपने बताई है उसको पूरी संजीदगी के साथ यह सरकार संज्ञान लेती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जायेगी जो लोग इसमें इनवॉल्व होंगे। (मेजें थपथपाई गईं)

ख12ण्55, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष–

अब जो बजट माननीय मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया था उस पर सामान्य चर्चा के लिये श्री राम गोविन्द चौधरी, नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित कर रहा हूं।

'नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर हमको बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैंने उसका काफी अवलोकन किया, और जो साहित्य भी वित्त मंत्री जी के द्वारा वितरित किया गया हालांकि उसका भी मैंने बहुत गम्भीरता से अध्ययन किया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह बजट दिशाहीन है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। यह पूरा बजट दिशाहीन है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यह लोक कल्याण संकल्प–पत्र, इसको भी मैं लाया हूं। जो महामहिम राज्यपाल जी ने यहां पर अभिभाषण पढ़ा उसको भी मैं लाया हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण पढ़ा, वह भी मौजूद है और पिछला बजट जो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह भी यहां मौजूद है। लोक कल्याण में प्रतिबद्धता करने का प्रयास किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर वित्त मंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर होता। ठीक वही परिस्थिति है श्रीमन् जैसे चुनाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के समय जनता को छला गया। इस बजट में भी जनता को बिल्कुल छलने का काम किया गया है (मेजों की थपथपाहट) जन भ्रमित करके। आप भी इस सदन के सदस्य रहे हैं। हमेशा बजट की कापियां वितरित की गई हैं लेकिन इस बार उनको अतिक्रमित कर दिया अव्यवस्थित। जिससे आप पढ़ न पायं। माननीय नये सदस्य इस विधान सभा के सदस्य हैं। बजट साहित्य ऐसा होता है कि पुराने विधायकों को भी पढ़ने में कठिनाई होती है तो ऐसा इसको इस बार बना दिया गया है कि जो नये विधायक आयेगें उनको उसको पढ़ करके समझ में ही नहीं आयेगा कि कहां पढ़ें कहां खत्म करें। कहां कौन सा मद है, कहां कौन सा मद है। यह है साहित्य में, पढ़ लीजियेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा जंजाल करके उसको लीपा पोती करके एक पोथी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया है। श्रीमन् भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ ऐसा छलावा किया जिसका बार–बार बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने उसी तरह से छलावा किया इसके लिये मैं दो लाइन कहना चाहता हूं।

झूठे वायदों से फुसलाकर यह जनता को फूल बनाते हैं,
और उनके दिल जीत लेने के बाद अपने वायदों को भूल जाते हैं।

वायदा तो बहुत किया इन्होंने। अब वायदा की बात कर दी जायेगी तो नई जो सरकार गठित हुई है बेनकाब हो जायेगी। यह बजट समाजवादी पार्टी की सरकार के बजट की नकल तो की गई है लेकिन जो उस बजट में बातें थीं हर बजट में कमी कर दी गई है बजट तो बहुत बड़ा है बजट हमने बता ही दिया कि व्यतिक्रम के अनुसार रखा गया है।श्रीमन् इस तरह से चलने वाला नहीं है 2017–18 का यह बजट 3,84,659.71 करोड़ रुपये का है यह कहा गया है कि अब तक के जितने बजट इस सदन में पेश हुए हैं यह सबसे बड़ा बजट है।

2016–17 का जो बजट माननीय अखिलेश जी ने इस सदन में पेश किया था वह 3 लाख 2 हजार 687.23 करोड़, अर्थात पिछले बजट से 81 हजार 972.38 करोड़ बजट यह अधिक दर्शाए हैं। किसानों का कर्जा माफी अगर 36 हजार करोड़ और सातवें वेतन आयोग खर्चे में 35 हजार करोड़ जोड़कर 71 हजार करोड़ घटाने पर केवल 10 हजार 972.48 करोड़ की ही वृद्धि होती है इसको कोई नकार नहीं सकता है। मुद्रास्फीति की दर यदि इसकी गणना की जाए तो यह बजट पिछले बजट से काफी कम है जो पिछला बजट पेश हुआ था आपके किसानों का कर्जा था 36 हजार करोड़, सातवां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों को लागू करना और मुद्रास्फीति की दर जो पांच–छः के बीच में रहती है अगर इन सबको जोड़ घटा दिया जाए तो जो इन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है यह पिछले बजट से भी कम है और इसीलिए तो एक योग्य वित्त मंत्री को, एक योग्य व्यक्ति को वित्त मंत्री का चार्ज दिया गया। यह उपाध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं लेकिन हमको लगता है कि बजट बनाते समय माननीय वित्त मंत्री जी को भी अंधेरे में रखा गया। इसीलिए तो शुरू में जब इन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया तो लगा एकदम पढ़ते–पढ़ते जब यह पन्ना पलटने लगे तो इनका हौसला टूट गया, यह सोचे मैं क्या चाहता था और क्या हो गया। जब तीसरा, चौथा पन्ना इन्होंने पलटा तो कुर्सी पर धम्म से बैठ गए, अरे, राम–राम, (हंसी) तब यह

हुआ भई बैठकर ही पढ़ लीजिए, जब पाचवां–छठा पन्ना इन्होंने पलटा तो आवाज ही बन्द हो गई, जब इनकी आवाज बन्द हो गई तो बड़े तेज तर्रार जो हमारे मित्र हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, तो यह खड़े हो गये, इनकी भी आवाज पहले बहुत बुलन्द थी, ज्यों–ज्यों पन्ना पलटते गए धीरे–धीरे धीरे–धीरे होते गए, और अन्त में सांस के सहारे अन्तिम शब्द कहकर यह भी बैठ गए। यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा है, बेईमानी है यह उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देकर के, बहुमत से भी अधिक बहुमत से सरकार बनाई कि यह सरकार आएगी हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगी, पूरब में कहा जाता है माननीय अध्यक्ष जी, ''का कहूं कुछ कहा ना जाए, साठ गांव बकरी चर जाए।'' सब सफाचट जो पिछली सरकार ने व्यवस्था की थी जो हमसे बड़ा यह बजट बता रहे हैं उसमें भी इन्होंने कटौती की श्रीमन् जरा 2225 पर देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग का कल्याण मद में व्यय समेकित निधि 5,02,018. 78 लाख यह 2016–17 में 2017–18 में 4,91,092.90 लाख यानी 10,925.88 लाख की कमी अनुसूचित जातियों में अम्बेडकर जी को सर पर लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं कि अम्बेडकर जी हमारे हैं जब अम्बेडकर जी आपके हैं तो अनुसूचित जाति के लोग भी आपके हैं उनके लिए जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने बजट प्राविधान किया था उसमें आपने इतनी कमी कर दी। 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण समेकित निधि में 14,35,651.51 लाख यह वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017–18 में 13,94,379.52 लाख यानी 41,271.99 लाख की कमी इसमें कर दी। प्राकृतिक विपत्ति के बारे में कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के जो इनसे मांग कर रहे थे उनके लिए इन्होंने आश्वासन भी दिया हमने इसके लिए जो प्राविधान समेकित निधि में किया था 20,69,582.80 लाख था इन्होंने कितना किया है 15,50,795.54 लाख यानी पांच लाख 18 हजार 787.26 लाख इसमें कमी कर दी। डेयरी विकास समेकित निधि में 10,988.95 लाख वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017–18 में 9,189.96 लाख 1,798.99 लाख इसमें कमी कर दी। उद्योग जो हमारे मित्र संभाल रहे हैं अभी बता रहे थे कि पूरी दुनियां इन्हीं के यहां उद्योग लगाने के लिए आ रही है समेकित निधि 1,48,369.13 लाख वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017–18 में 37,324.43 लाख, 1,11,044.7 लाख की कमी इसमें कर दी उद्योग में। सड़क तथा सेतु उप मुख्य मंत्री जी हैं ही नहीं शायद इसीलिए हैं नहीं समेकित निधि 4,33,380.48 लाख वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017–18 में 3,74,293.09 यानी 59,087.39 लाख की इसमें कमी हो गई। सड़क पुल पुलिया में। सड़क तथा सेतु पूंजीगत परिव्यय इसमें 20,53,199.67 लाख और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14,98,189.11 लाख, इसमें 555,010.56 लाख की कमी हो गयी। सड़क परिवहन समेकित निधि मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4,53,545.85 लाख व्यय और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4,00,253.64 लाख, इसमें 53,292.21 लाख की कमी हो गयी। सड़क परिवहन पूंजीगत परिव्यय मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 20,92,831.17 लाख व्यय और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 15,45,389.11 लाख, इसमें 547,442.06 लाख की कमी हो गयी।

पर्यटन के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी कल कहा है। पर्यटन की समेकित निधि मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 6,863.28 लाख व्यय और वित्तीय वर्ष 2017–18 में

3,462.84 लाख, इसमें भी 3,400.44 लाख की कमी हो गयी। पर्यटन के पूंजीगत परिव्यय की मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 72,19,715.76 लाख व्यय हुये और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 53,25,759.98 लाख, इसमें 18,93,955.78 लाख की कमी हो गयी।

मान्यवर, पुलिस जिस पर पूरे प्रदेश की कानून–व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इस पर जब हम कहते हैं तो आप जवाब देते हैं और जब आप कहते हैं तो हम जवाब देते हैं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो इस प्रदेश और इस देश की जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करने का काम करता है। पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे तो उधर बैठे हुये लोग जब इधर थे तब 24 घंटे कानून–व्यवस्था की बात उठाते थे। जो कुछ भी बात हो तो कानून–व्यवस्था। हम सड़क बनाने की बात कहते थे तो यह कहते थे कि कानून–व्यवस्था। कानून–व्यवस्था कोई पुड़िया नहीं है कि बाजार से उसे कोई खरीद लाये और उसको ठीक कर दे। हमारी मंशा क्या है कानून–व्यवस्था को ठीक करने की, हम कानून–व्यवस्था को कैसे ठीक करना चाहते हैं। मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस पर काम किया था। हर थाने में वर्षों से जो सड़ी–गली गाड़ियां पड़ी थीं, अगर कोई पुलिस को बुलाता तो दरोगा जी जब दौड़कर गाड़ी पर चढ़ते थे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी वह ठेली जाती थी। प्रदेश के हर थाने में हमारी सरकार ने पुलिस के चलने के लिये नई गाड़ियों की व्यवस्था की, महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिये, छेड़खानी को रोकने के लिये 1090 को शुरू किया और तो और मा0 अध्यक्ष जी, दुनिया की जो सबसे बेहतर प्रणाली डायल–100 जिसके लिये अभी अमेरिका ने उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को सम्मानित किया है, उनको प्रशस्ति पत्र दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अभी केन्द्र सरकार की मीटिंग में भी उसकी बढ़ाई की है कि हमारे यहां डायल–100 की व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। कानून–व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। 1090 को इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया है और शायद 181 एलॉट किया है। पुलिस विभाग में क्या हो गया। पुलिस विभाग के पूंजीगत व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1,54,573.57 लाख व्यय और इसमें क्या हो गया माननीय मुख्य मंत्री जी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 63948.63 लाख रुपये आपने कर दिया, इस प्रकार इसमें 90624.94 लाख की कमी हो गई। लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय 165710.51 लाख वित्तीय वर्ष 2016–2017 में था।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

भाई आप लोग ही कह लीजिये कि क्या कहना है किसी को। मैं बैठ जाता हूं। हम लोग तो कभी टोकाटाकी करते नहीं थे। जब हम सत्ता में थे, तब भी नहीं करते थे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहे। बीच में न बोलें माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में 165710.51 लाख और 2017–18 में 145485.49 लाख, इस प्रकार 20225.02 लाख की कमी इसमें हो गई।

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के पूंजीगत व्यय में 376981.56 लाख वित्तीय वर्ष 2016–17 में था और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 172193.76 लाख है, इसमें 204787.8 लाख की कमी कर दी। अन्य सामाजिक सेवाओं में पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में 37690.08 लाख रुपये था, जो अब 34957.98 लाख कर दिया गया है, इस प्रकार इसमें 2,732.1 लाख की कमी कर दी है। मृदा तथा जल संरक्षण पर अब हम आते हैं। कृषि मंत्री जी एक दिन कह रहे थे कि जब तक मृदा का परीक्षण नहीं होगा और किसान को बताया नहीं जायेगा कि किस खेत में कैसा बीज बोना है, कौन सी फसल उगानी है तो अच्छी फसल नहीं मिल सकेगी। यह आवश्यक है, उनकी बात भी सही है। लेकिन इसमें भी देख लीजिये खेल हो गया। पूंजीगत व्यय 2593.55 लाख वित्तीय वर्ष 2016–17 में था जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1645.05 लाख कर दिया गया है, इस प्रकार इसमें 948.5 लाख की कमी कर दी गई। कृषि मंत्री जी किससे जांच करायेंगे, आपके भी बजट में कमी। पशुपालन पर अब आते हैं। पशुपालन में पूंजीगत व्यय 23055. 34 वित्तीय वर्ष 2016–17 में था और 2017–18 में 13731.10 लाख कर दिया गया है, इस प्रकार इसमें 9324.24 लाख की कमी हो गई। इसलिये कमी हो गई कि इनके दिमाग में है कि मवेशी केवल यादव ही पालता है, जबकि मवेशी आज सभी पाल रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि सत्तापक्ष के लोगों की तो गउ माता है)

गउ हमारी माता है, इनकी काहे की माता है यह तो छीने हुये हैं। इनकी काहे की माता है।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल में असहमति है इस सवाल पर।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, आप आजम खां साहब से पूछकर बताये कि किसकी माता है।

श्री इकबाल महमूद–

वह आपके भी तो मित्र हैं आप स्वयं उनसे पूछ लीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम तो महाना जी आप ही से पूछ रहे हैं। वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में 64182.70 लाख था और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 25425. 25 लाख कर दिया गया है, इस प्रकार 38757.45 लाख की कमी कर दी गई है। मान्यवर, खाद्य भण्डारण तथा भण्डारण पर पूंजीगत व्यय 7,781.97 लाख वर्ष 2016–17 में तथा वर्ष 2017–18 में 3,029.33 लाख इसमें भी 4,752.64 लाख की कमी हो गयी। सहकारिता में पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 1,25,522.29 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 72,238.14 श्रीमन् इसमें भी 53,284.15 लाख की कमी हो गयी। अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम वर्ष 2016–17 में पूंजीगत व्यय 4,60,426.50 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 3,37,760.01 लाख इसमें 1,22,666.49 लाख की कमी हो गयी। मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 4,83,530.07 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 2,37,544,09 लाख इसमें

2,45,985.98 लाख की कमी हो गयी। मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 61,806.00 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 28,492.50 लाख इसमें 3,331.5 लाख की कमी हो गयी। लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 59,482.65 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 42,557.32 लाख इसमें 16,925.33 लाख की कमी हो गयी। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 6,61,433.57 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 409,323.90 लाख इसमें 2,52,109.67 लाख की कमी आ गयी। बिजली परियानाओं में पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 12,32,465.68 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 7,33,622.36 लाख इसमें 4,98,843.32 लाख की कमी आ गयी। नये और नवीनीकृत उर्जा पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2016–17 में 12,42,161.21 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 7,38,351.05 लाख इसमें 5,03,810.16 लाख की कमी आ गयी। ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत व्यय 2016–17 में 4,271.67 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 2,793.15 लाख इसमें 1478.52 लाख की कमी आ गयी। लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत व्यय 2016–17 में 636. 50 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 309.00 लाख इसमें 327.5 लाख की कमी आ गयी। अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय 2016–17 में 324.00 लाख तथा वर्ष 2017–18 में 00 लाख इसमें 324.00 लाख की कमी आ गयी। श्रीमन् हम अगर और कहेंगे तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी इसलिए मैं यहीं बंद करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, एक तरफ इस बात का ढिंढोरा कि अब तक इस सदन में जितने भी बजट पेश हुए हैं उन सबसे बड़ा बजट है। जो मैंने घटाकर बताया पिछली सरकार के अंतिम सत्र के बजट से भी कम बजट और हर विभाग में जो योजनाओं में विकास के लिये प्राविधान किया था उसमें इतनी भारी कटौती की गयी है। सरकार क्या करना चाहती है। कैसे पुल, सड़क बनेंगे। कैसे छात्रवृति मिलेगी, कैसे किसानों को लाभ मिलेगा ? बताये सरकार, बतायें मा0 मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी। इन्होंने अपने संकल्प–पत्र में बार–बार इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी विभागों के जो खाली पद हैं उसका हम विज्ञापन जारी करके 90 दिन के अंदर हम बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, क्या जब से यह नयी सरकार बनी है एक भी कोई वान्ट निकाला। बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो अपने शासनकाल में भर्ती किया था, आयोग से जिनकी नियुक्यिां हो गयी थीं, परीक्षा, इंटरव्यू में पास हो गये थे, उनका पुलिस वेरीफिकेशन भी हो गया था। चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी। चुनाव हुआ, नयी सरकार आ गयी। रोज यहां धरने पर बैठे हैं। जब आते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी से गुहार लगाने के लिए कि मा0 मुख्य मंत्री जी हमें अपनी योग्यता के अनुसार सारी प्रक्रिया पास करके हमें नौकरी मिल गयी है ज्वाइन करा दीजिए हमारे परिवार का पालन पोषण तो हो। ज्वाइन कराना तो दूर उनको लाठियों से धुना जा रहा है। जैसे हम लैपटाप बांटे थे तो मा0 श्रम मंत्री जी नेता विपक्ष थे। तो कह रहे थे कि झुनझुना। इन्होंने क्या किया है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 और कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना बनाकर यह इतिश्री कर दिये कि तुमको रोजगार मिल गया। अगर संकल्प–पत्र के अनुसार यह सरकार काम की होती तो अब

तक हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल गया होता। उनके परिवार जो रोजीरोटी के लिए बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, खेत गिरवी रख देता है। इस आशा में हमारा बच्चा जब कम्प्टीशन बीट करेगा तो हमारा परिवार चलेगा। उस अभिभावक को निराशा हाथ लगी। सरकार ने कृषक हितकारी किसी योजना पर धन नहीं दिया। नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनेइजेशन नेशनल मिशन आन सीड एण्ड आयल पाम जैसी योजनाओं का जिक्र करके केवल भ्रमित करने का काम किया है। कृषि के किसी भी मद में कोई पैसा नहीं है और सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से तीन लाख तक फसली ऋण के तीन प्रतिशत ब्याज पर जो लोन दिया जा रहा था उसका भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन आदमी कोई असली चीज को छुपा कर नकली चीज प्रस्तुत करता है, इनके मन में तो हित दूसरे का करने का, जो देश के बड़े–बड़े, माने–जाने पूंजीपति हैं, जिन्होंने इस देश और प्रदेश की गरीब जनता का खून चूस–चूस करके अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है, उनकी तरफ तो इनका दिमाग है, उनके लिए इनके पास कार्यक्रम है लेकिन गरीब के लिए, किसान के लिए इनके पास कोई फण्ड नहीं है, पैसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इस प्रदेश में सबसे पहले किसानों की तरफ किसी का दिमाग गया, चौधरी चरण सिंह के बाद तो माननीय मुलायम सिंह यादव का गया। उन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश में किसान का 10 हजार रुपया, पहली दफा हिन्दुस्तान की राजनीति के इतिहास में 10 हजार रुपया कर्जा माफ किया। दूसरी बार जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार आयी, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जायेगी तो उत्तर प्रदेश के जो सहकारी बैंक हैं, उनसे जो किसान कर्जा लेगा।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के कुछ कहने पर)

है मेरे पास, आपका भी है और मेरा भी है, उसमें हल्ला करने से थोड़े काम चलेगा। आपका भी है, मेरा भी है, कोई गलतफहमी में नहीं बोल रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश सरकार के बैंक हैं, भूमि विकास बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है, उसका हम 50 हजार रुपया तक का कर्जा माफ करेंगे और उन्होंने किया। मा0 मुलायम सिंह यादव ने इस प्रदेश में सबसे पहले किसान बीमा दुर्घटना योजना लागू की, एक लाख रुपया और जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुए तो उन्होंने उसको पांच लाख रुपया किया। हमने किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था कर दी कि सरकारी नहर से और सरकारी ट्यूबवेल से जो किसान अपने खेत की सिंचाई करेगा, उससे एक पैसा सिंचाई का नहीं लिया जायेगा, नहीं लिया गया। हमने तो किसानों के हित की रक्षा की इसलिए कि हम किसान हैं लेकिन ये नकली किसान का चोला पहन करके किसान के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं, इन्होंने किसान की तमाम सुविधाओं को छीनने का काम किया है। हमने संकर बीजों के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, प्रमाणित बीजों के लिए हमने 81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी और रसायनिक खादों के भण्डारण के लिए हमने 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। लेकिन आपने रसायनिक खादों के भण्डारण के लिए कुछ नहीं किया है। बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक

निर्देश दिया था कि किसानों ने जो कर्ज लिया है, उसकी वसूली तब तक न की जाए जब तक कर्ज माफी की पूरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी, हम लोगों को आपकी नेकनीयती पर शक नहीं है, लेकिन ये अधिकारी भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफे हुआ कि जितने किसानों ने कर्ज लिया था, उनके साथ इतना जोर–जबर्दस्ती किया कि मुख्य मंत्री का आदेश आने से पहले से पूरा वसूल लें और मुख्य मंत्री जी, इस बार क्या हुआ, आप जांच करवा लीजिएगा कि पहले किसान यदि लोन लेने में गिरफ्तार होता था तो वह तहसील की जेल में रखा जाता था, लेकिन मुख्य मंत्री जी, इस बार अधिकारियों ने उनको सीधे जेल भेज दिया। यह उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन किसानों को मेन जेल में भेजा गया। श्रीमन्, यह किसानों की हितैषी सरकार है ? हमने कहा था कि जो किसान निजी ट्यूबवेल लगाते हैं, उनका बिजली का कनेक्शन करने के लिए ज्यों ही एप्लीकेशन आए, तुरन्त उसको कनेक्शन दिया जाए। 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित है जनता इस प्रदेश की और आपने जो कर्जा माफ किया है 31 मार्च, 2016 तक जो किसान कर्जा लिये हैं और 2017 तक जमा नहीं किये हैं उनका एक लाख तक, इसमें है कि लघु सीमांत कृषक जितने भी होंगे सभी लघु सीमांत कृषकों का हम माफ करेंगे कर्जा, माफ करेंगे शब्द है, सभी शब्द हटा दिया गया, बजट भाषण मे सभी शब्द हटा दिया गया और जब आप माफ करने की प्रक्रिया चलायेंगे मा0 मुख्य मंत्री जी तो शायद किसान कम ही मिलें जो बकाया में तय किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी क्वेश्चन आवर में हुआ था मा0 अध्यक्ष जी, किसान कोई साधारण चीज नहीं है, नौकरी करने वाला आदमी अपने परिवार को जिलाता है, बिजनेस करने वाला आदमी अपने परिवार को जिलाता है और कृषि करने वाला आदमी पूरा मानव, इस धरती पर जितने जानवर हैं उनका, जीव–जन्तु सबका पेट पालने का काम करता है, जो सबका पेट पालने का काम करता है किसान, वह आज दुःखी और बैठ कर के जो बिजनेस करता है वह सुखी, यह कैसे चलेगा श्रीमन् बार–बार बात आती है कहा है आपने भी हम भी कहते हैं कि किसानों की उपज का मूल्य दुगना दिया जाय।

श्रीमन् यह कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, एक ही किसान का एक बेटा जो फौज में नौकरी करता है, उसी किसान का दूसरा बेटा खेतों पर काम करता है, फौज में काम करने वाले सिपाही को जो भी उसके परिवार के लिए आवश्यक चीजें होती हैं एक खास रिटेल में मिलती हैं और किसान का बेटा जो खेती करता है वह जब सामान खरीदने जाता है तो दोगुने, तीनगुने, चारगुने मंहगे दाम पर खरीदता है, यह कौन सी नीति है। मैं मांग करना चाहता हूँ अगर आप किसान के सबसे बड़े हितैशी हैं, कहने के लिए, करने के लिए नहीं, करने के लिए तो हम हैं और मा0 अध्यक्ष जी इनकी जो कथनी और करनी है, अगर ऐसे ही रही तो जैसे महाना जी और ये संसदीय कार्यमंत्री जी कहते थे कि अगली बार हम लोग यहां आ रहे हैं तो हम लोग जानते थे कि यह झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को गलतफहमी हुई कि अरे राम–राम इतना हमने विकास किया है प्रदेश में, हम कहां सरकार से हटने वाले हैं, लेकिन यह तो आ गये भइया, आज मैं कहता हूं कि किसानों को जो आपने छला है, कर्ज माफी के नाम पर जो छला है, उनकी उपज का उचित दाम देने पर जो आपने छला है, इसलिए छला है कि आपको आता तो कुछ

है नहीं, नकली शेर कब तक असली शेर बना रहेगा। हम असली किसान हैं, नेता सदन महात्मा हैं, सन्त हैं, आर्शीवाद मैं इनसे ले रहा हूं कि योगी जी आर्शीवाद दें कि आप पिछली बार यहां आवें और हम वहां चले जांय।

श्री अध्यक्ष–

बहुत जल्दी में हैं ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

योगी जी हंस दिये, आर्शीवाद उनका मिल गया कि तुम आवोगे अगली बार इधर, क्योंकि हम लोग तो मठ वाले हैं, जाने वाले हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी जब किसान खुशहाल होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उसको इतना पैसा मिलेगा कि वह अपने बच्चों को कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ा सके। यदि उसके घर कोई भी बीमार पड़े, हार्ट का मरीज हो जाये, किसान के घर किडनी का मरीज हो जाये तो वह भी अपने बच्चे का पी0जी0आई0 में इलाज करा सके। एक किसान के बेटे की यदि किडनी फेल हो जाये तो सिवाय मरने के उसके पास कोई चारा नहीं है और एक पैसे वाले का बेटे की यदि किडनी खराब हो जाये तो 10 किडनी वाले पैसे के बल पर देने के लिए आ जायेंगे। किसान की हालत कैसे सुधरेगी, इस पर कभी विचार किया आपने ? केवल लोक संकल्प–पत्र माध्यम से। आपने चुनाव में जिन–जिन बातों का वादा किया, अगर जाकर संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी बात छोड़ दीजिए अगर गांव में पूछेंगे तो आप सर पटक करके वहीं आत्महत्या कर लेंगे कि अरे राम–राम हमारी पार्टी इस तरह की जालसाजी किया है, इस तरह की जालसाजी। किसानों की कर्ज माफी में बजट में सबको हटा दिया गया केवल लघु और सीमान्त किसान का जिक्र है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार तो हमने केवल प्रस्ताव रखा था लेकिन इस बार यह यकीन कर लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म बनाने वालों की अगर टीम गठित हो तो ये उसके अध्यक्ष और डायरेक्टर दोनों होंगे और मान्यवर, यहां दर्शक दीर्घा में अगर कोई प्रड्यूसर डायरेक्टर आ जायेगा तो बहुत बड़ा नुकसान यह होगा कि हमारे पास से एक बहुत बढ़िया नेता छिन जायेगा। मान्यवर, दर्शक दीर्घा में किसी ऐसे को पास न जारी करें कि जो कोई फिल्म इण्डस्ट्री का प्रड्यूसर डायरेक्टर आ जाये। मान्यवर, इतनी बढ़िया एक्टिंग अगर प्रेम चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार यहां बैठें हों तो मान्यवर उसी दिन वो आत्महत्या कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप कोई फिल्म बनवा रहे हैं, क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि इनको कष्ट है, ये जब लड़के थे तो रामलीला में सीता जी का पात्र करते थे। आइये हम राम बनते हैं आप सीता बनिये और देखिये किसका पात्र ठीक होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, अब केवल एक लंगूरी बन्दर की कसर रह गयी है। उसकी कसर रह गयी है, लोगों के साथ अगर एक लंगूरी बन्दर कर दिया जाये और एक डुगडुगिया दे दिया जाये तो मान्यवर, किसी का कोई मुकाबला नहीं होगा। कोई सामने नहीं खड़ा हो सकता। मान्यवर, हमने तो हमेशा भीष्म पितामह और रावण का रोल किया है, आप ये समझ लें। सीता जी का रोल तो आप लोग करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत दुखी हैं, इनको याद आता है कि हम तुम कमरे में बन्द हो, चाबी खो जाये तो क्या। ये इसलिए डरे हुए हैं कि चाबी खो जायेगी तो क्या होगा। अगर नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री एक कमरे में बन्द हो जाये और चाबी खो जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूं अभी कल बात आई थी, या तो मुख्य मंत्री जी को आज हंसते मैंने सदन में देखा है या कल, इन्होंने कल से शुरू किया है धीरे–धीरे हंसना। जब पर्यावरण मंत्री जी ने कल कहा कि आलू बहुत पैदा हो गया तो इन्होंने कहा कि योगी जी के आते ही आलू एकदम पैदा होने लगा। हुआ है, आलू इस बार बहुत पैदा हुआ है, किसानों ने मेहनत करके क्योंकि गेंहू, चावल, दाल ये सब जो है इसमें तो उसको लाभ मिल नही रहा है तो गन्ना बो रहा है, आलू बो रहा है, मेंथा बो रहा है और कोई सब्जी की खेती कर रहा है। आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ था और जब आलू खेत से निकलने लगा तो चुनाव हो गया। चुनाव के बाद यह सरकार बन गई। इन्होंने समर्थन नीति की घोषणा तो की लेकिन तब तक आलू किसान उजड़ गया था। इसमें है कहीं आलू किसान का, सभी के क्षेत्र में आलू बोया गया होगा। आलू किसान बरबाद हो गया, ऐसे बरबाद हुआ कि जो आलू रखा था कोल्ड स्टोरेज में उसको उसी में छोड़ दिया, नया बेच नहीं पाया और कौड़ी के मोल हो गया। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की जगह नहीं है, सड़ रहा है। आलू किसान, मैंने अपनी सरकार में भी मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा था और फिर मैं आपसे भी कहता हूं। आप सन्त हैं, हो सकता है कि इसमें आप कोई उपाय निकालें। आलू का उत्पादन अब उत्तर प्रदेश में इतना हो रहा है कि अब केवल खाने से किसानों के आलू की खपत नहीं हो पा रही है इसलिए आवश्यक है कि ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे आलू किसानों के आलू की खपत हो जाए, उसको उचित मूल्य मिले। इसके लिए एक बहुत बड़े कारखाने की आवश्यकता है।

हमारे मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने उस कारखाने के लिए कुछ प्रयास किया था जब मैंने उनसे इस बात के लिए कहा। पहली दफा मैं जब उद्यान मंत्री था तो मैं रूस गया था तो जब पहली दफा मैं उद्यान मंत्री था, उस समय से अब तक बहुत दिन बीत गए हैं। इस समय काफी आलू हो रहा है, पहले केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होता था और मैं रूस क्यों गया था, यह हंसी की बात नहीं है। रूस में एक कारखाना है जो आलू की खपत करता है, उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन वोदका की शराब बनती है। साथ ही आलू के और जितने भी सामान बनते हैं, चिप्स आदि वह सब बनाता है। रूस का आलू किसान आत्मनिर्भर है। तब मैं गया था और प्रधानमंत्री थे

चन्द्रशेखर जी, हम उनकी कांन्स्टीचुएंसी के एम0एल0ए0 थे। मैंने प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी से कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा काम करिए और उसके लिए वे सहमत हो गए और कृषि मंत्री थे देवी लाल जी, वह भी सहमत हो गए लेकिन दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि अध्यक्ष जी और देवी लाल जी के सहमत होने के चार दिन के बाद ही सरकार का इस्तीफा हो गया इसलिए आलू किसानों के लिए कोई ठोस नीति होनी चाहिए। जैसे पूरब में अब गन्ना बोना धीरे–धीरे किसान ने कम कर दिया। बलिया में तो एकदम कम हो गया, बलिया में गन्ना बोना तो एकदम कम हो गया है। देवरिया में भी जितना गन्ना बोया जाता था उससे बहुत कम हो गया, गोरखपुर में भी कम हो गया। अब बस एक चीज बची है आलू पूरब के किसानों के लिए। पश्चिम में भी पूरा एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा यह तो पूरा आलू का गढ़ है। पूर्वी उत्तर अब आलू बोने में है तो आलू के किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए ठोस नीति मा0 मुख्य मंत्री जी आपको बनानी चाहिए क्योंकि आपकी सरकार है। आपके बजट भाषण में पशुओं की नस्ल सुधार के बारे में बहुत कहा गया है। मा0 वित्त मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है लेकिन क्या किया है, क्या किसानों का फ्री में टीकाकरण हुआ। क्या जो पशु अस्पताल हैं, उनके पैसे की व्यवस्था हुई इस बजट में, नहीं हुई तो कैसे आप पशु संरक्षण करेंगे। गाय हमारी माता है, घर–घर से उसका नाता है। बात सही है लेकिन केवल यह कहने से तो कुछ होगा नहीं। गाय हमारी माता है, बेटा खूब दाल, भात, तरकारी खा रहा है और माता जी पॉलीथीन खा रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यह जो गौशालाएं खुली हैं केवल सेवा भावना के लिए नहीं, उसमें मुख्य स्रोत है अनुदान का और जो बड़े–बड़े पूंजीपति लोग होते हैं वे गौ–सेवा के लिए अपने बजट का एक प्रतिशत देते हैं उसमें भी गाएं इतनी अधिक संख्या में रखी हैं कि मर जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश के पशुपालकों के लिए और गौशाला चलाने वाले लोगों के भी सामने गाय हमारी माता है उसे बछिया हुई तो ठीक और बछड़ा हुए। मैं मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से कि जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं या किसानों के पास गायें हैं, बछड़े कहां गए, कहां हैं बछड़े। गाय की बाछी तो है बछड़े कहां हैं ?

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

हल्ला मत करके सुनिये। हल्ला करने से नहीं होगा, बैठ जाइये। हल्ला करने से नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पहले बछड़े होते थे तो खेत जोतने का काम बैल करते थे, बैलगाड़ी चलाने का काम करते थे, बहुत सारे उनके काम थे।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई, आप लोगों ने कटवा दिये)

आप जिया के रखिएगा तो बताइये क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बछड़े का ट्रैक्टर हो गए हैं, कोई हल चला नहीं रहा है। क्या कोई हल चला रहा है तो बछड़े का उपयोग हल में था। बछड़े का उपयोग बैलगाड़ी में था। बछड़े का प्रयोग जब हम दौरी करते थे उसमें था। दाना जब पेरते थे उसमें बछड़े का काम था। आज बछड़े का काम कहां और कैसे होगा मुख्य मंत्री योगी जी आप ही बताइये कि बछड़े का क्या होगा। हर किसान

जो खेती करता है, मवेशी पालता है। अभी कृषि मंत्री जी ने कहा कि उसकी आय के लिए मवेशी है, साग–भांजी है, फल–उद्यान है उससे किसान अपनी इनकम बढ़ाएगा। तो अगर बछड़ा दूध पीना छोड़ दे थोड़ा बड़ा हो जाए। गरीब किसान कब तक उसको खिलाएगा तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जैसे गायों को गौ–शाला बनाकर रक्षित करने का काम हो रहा है, किसानों की जान बचाने के लिए बछड़ों को भी आप गौ–शाला की तरह बछड़ाशाला बनाकर उनको पालने का काम आप करिये। (मेजों की थपथपाहट) पालिये उसको यह एक गंभीर समस्या है, मजाक की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। कोई साथी कहे कि आप कटवा दिये और हम कहें आप कटवा दिये। ये गंभीर समस्या है किसानों के साथ, यह समस्या गंभीर है गौशालाओं के साथ। इसकी कोई ठोस नीति सरकार के पास नहीं है। पहले तो हल चलता था, पहले तो बैलगाड़ी चलती थी, पहले तो कोल्हू चलते थे। पहले तो बैल का ही उपयोग था अब तो उसका उपयोग है ही नहीं। एक और समाज का अंग है जो गरीबी, बेबसी और लाचारी से अपना जीवन–यापन करता है, वह है मछुआ समुदाय। बिन्द, मल्लाह, केवट, तुरहा आदि जितनी तरह की ये जातियां हैं। इनका परिवार चलाने का साधन था नाव खेना, मछली मारना उसको बेचना और परिवार को चलाना। हमारी सरकार ने 200 एकड़ पक्के तालाबों को मछली पालने के लिए और 1 लाख से अधिक मछली पालकों को सुविधा देकर उनको जीविकोपार्जन करने हेतु हमने उसमें 21 करोड़ की व्यवस्था की थी और 750 मछुआरों को लोहिया आवास देने की हमने व्यवस्था की थी। एक लोहिया आवास का दाम था 3 लाख 20 हजार रुपये इनको आवास देने की हमने व्यवस्था की थी और उसके पहले माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था इनके लिए, उन्होंने कहा कि तालाब, नदी, पोखरे और झील का जो पट्टा होगा केवल मछुआ समुदाय की समितियों को होगा। नदी के जो घाट चलते हैं नाव के माध्यम से, उसका ठेका मछुआ समुदाय का होगा। अब तो गिट्टी, मौरंग, बालू का बहुत बड़ा मामला हो गया है, उस समय ऐसा भी किया गया था कि बालू के खनन का भी ठेका मछुआ समिति को ही दिया जायेगा और अखिलेश यादव जी ने जलाशय बनवा करके उसमें मछली पालने का काम भी किया। जो 750 आवासों के लिए काम किए गए थे उसमें भी आपने 660 आवास कर दिए, इसमें भी घटा दिया। तो न आपके समक्ष कोई मछुआ पद्धति है, न उनके जीने–खाने की कोई व्यवस्था है, न रहने की कोई व्यवस्था है। मछुआ समुदाय के लिए 2 लाख से भी अधिक निःशुल्क प्रीमियम दुर्घटना बीमा योजना हम लोगों ने लागू की थी। उसको भी आपने खत्म कर दिया। अब आप आखिर करना क्या चाहते हैं ? कुछ तो वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण किया, तो जो मतस्य पालकों के लिए हमने किया था, उसका जिक्र तो आपने किया है, उसका धन्यवाद आपको, लेकिन आपने और जगहों पर कटौती क्यों कर दी, अब गरीब आदमी कैसे जियेगा, क्या आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की ? हमने की थी।

श्रीमन्, चुनाव के समय, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हों, चाहे हमारे केन्द्र के माननीय केंद्रीय मंत्री लोग हों, चुनाव में जिन लोगों ने भाषण दिया, जनता को यह आश्वासन दिया कि जब

हमारी सरकार बनेगी हम डिग्री कालेज तक शिक्षा निःशुल्क करेंगे और नाम लिखते ही हम छात्रों को लैपटॉप बॉट देंगे। यह नकल थी। एक कहावत है कि साधे बोल, जन्म दिया पराया, चूंकि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा तो हम तो उससे आगे बढ़कर के बांटेंगे लेकिन उसका बजट में कहीं पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका यह बजट छलावा है, प्रपंच है, जनता को धोखा देने वाला है। मैं यह शिकायत की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, अभी तक पूरे बच्चों को यूनिफार्म नहीं बंट पाएं, पूरी किताबें नहीं पहुंच पायी, बैग नहीं पहुंच पाये और आपके बैग दूसरे प्रदेश में चले गए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक पढ़ाने वाले गुरूओं की कमी है, अध्यापकों की कमी है। तो जब पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे तो अच्छी शिक्षा की हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के विश्वविद्यालयों तक जो अध्यापकों की जगहें रिक्त हैं उसको तत्काल भरे जाने की कार्यवाही होनी चाहिए। लैपटॉप तो मिला नहीं, हमने बांटा था जिसको श्रममंत्री ने झुनझुना कहा था। इसलिए हमने बांटा था कि हमने भी चुनाव में वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बी0ए0 में नाम लिखाने वाले तमाम छात्र–छात्राओं को लैपटॉप देंगे। क्योंकि दुनिया टेक्निकल दिशा में बढ़ रही है, लड़कों–लड़कियों को, छात्रों को, छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन से सुसज्जित करना चाहिए। नेट की आपने व्यवस्था की है इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है आपके बजट में, कहीं जिक्र नहीं है क्या बात करते हो (शोर)

मुंह के तो आप धनी हई हैं न, मुंह के धनी हैं करनी के धनी नही हैं कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो कहती है उसको करती है जो नहीं कहती है उसको करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहती है उसको करती नहीं है यह जनता के सामने खुलासा हो गया है (शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी लम्बी संख्या है वह कोई हमारी सरकार की नहीं है, सतत् प्रक्रिया है। लोग स्कूल खोलते हैं मान्यता लेते हैं सरकार मान्यता देती है सरकार ही मान्यता देती है जो लम्बे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं हमारी सरकार मे उन लोगों ने काफी धरना किया प्रदर्शन किया और हम लागों ने उनके मानदेय की व्यवस्था की है और जब यह सरकार आई है तो कहीं इनके बजट में उनके लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। धरने पर बैठे है एक महीने से जहां धरना स्थल है वहां, संकल्प–पत्र में हर एक एक घर को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण देने के वायदे के अनुसार आपके इस बजट भाषण में इस बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं है, कहीं कोई प्राविधान नहीं है तो हल्का बजट है यह बजट चो–चो का मुरब्बा है। कुछ हई नहीं, चो–चो को मुरब्बा है।

श्री अध्यक्ष–

यह मुरब्बा कहां मिलता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे आवश्यक है मानव का स्वस्थ रहना जब स्वस्थ मानव नहीं रहेगा तो वह समाज पर बोझ बन जायेगा और जब स्वस्थ मानव रहेगा तो प्रदेश का विकास होगा हर क्षेत्र में इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो 10 रुपया का पर्चा मिलता था उसको एक रुपये का कर दिया था। फ्री में दवाई की व्यवस्था, सभी तरह की जांच हमने फ्री किये थे हमने अन्त में यह व्यवस्था कराई थी कि मण्डल स्तर पर हम डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे और यह सरकार अब तो आपके जिम्मे हो गया देखिये अब क्या हो रहा है मंत्री जी दवाओं की कमीं हो गयी है अस्पताल में दवा नहीं मिल रहा है। (टोका–टाकी होने पर)

आपको तो मिल ही रहा है जिसको चाहिए उसको तो मिलना चाहिए आप तो 5 वर्ष के लिए जीतकर आ गये आपको तो सब कुछ मिल रहा है और आप कहने के लिए मजबूर हैं कि आपको सब कुछ मिल रहा है। यह जो गांव का गरीब जो असहारा, बेसहारा, किसान है, मजदूर है जो बड़ी मुश्किल में जाता है अस्पताल में अपना काम छोड़ करके 300 रूपया मजदूरी छोड़कर जाता है उसकी दवा की व्यवस्था कहां से होगी, उसकी किडनी खराब हो जाय तो दवा की व्यवस्था कहां से होगी ? हर जांच में पैसा लिया जाने लगा, कैसे होगा, तो स्वास्थ्य विभाग भी बेहतर काम नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग, मंत्री जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो बड़े–बड़े डाक्टर हैं वह शहर में हैं गांव में कोई डाक्टर जाता नहीं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। गांव के मरीज क्या करेंगे, व्यवस्था तो है। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सारी व्यवस्था है, अरे 5 वर्ष सारी व्यवस्था है पंडित जी, जब आप 5 वर्ष बाद क्षेत्र में जायेंगे तो वही लोग आपको बतायेंगे कि व्यवस्था थी कि नहीं थी और तब आपको पता चलेगा। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पी0एच0सी0 पर सी0एच0सी0 पर माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिये कि कितने डाक्टर हैं। आप इनका ट्रांसफर करेंगे तो भी यह वहां जायेंगे नहीं। मैंने अपनी सरकार में डाक्टरों का ट्रांसफर कराकर देखा है यह नहीं जाते हैं। आप इन्हें वहां पहुंचायेंगे कैसे और जो स्थानान्तरण नीति आपने बनायी है उसमें भी अच्छे डाक्टर को शहरों में ही रहने की व्यवस्था है तो फिर गांव के लोग अच्छे डाक्टर से इलाज कराने से वंचित रह जायेंगे, इसलिये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारी मांग है कि कुछ दिन के लिये जो अच्छे डाक्टर हों, उनका पी0एच0सी0 और सीएच0सी0 पर स्थानान्तरण हो और वह वहां पर मरीजों का इलाज करें। इन डाक्टरों के पास एक घमंड है कि हम इस्तीफा दे देंगे और प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। तो प्राइवेट प्रैक्टिस हम अपने प्रदेश में उनको नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे, आप इस पर प्रतिबंध लगाइये। आज हालत खराब है, दवा के मामले में, जांच के मामले में, डाक्टर के मामले में। मरीज तडफड़ा जाता है और लौट आता है तो कैसे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। केवल कह देने से और मुंह से बक–बक बोलने से कुछ होने वाला नहीं है।

विद्युत के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि आज गरीब आदमी भी चाहता है कि हमारा घर प्रकाशित हो। काफी मेहनत हमारी सरकार ने इस दिशा में की। पिछले सरकार में देश की नेता माननीय मायावती जी ने जितने एम0ओ0यू0 किये थे, उस सब पर अखिलेश यादव आगे बढ़े और उसको पूरा करवाने का काम किया। जब सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली तो उन्होंने मार्च में घोषणा की, कि हम 18 घन्टे गांव को, 20 घन्टे तहसील क्षेत्र को और 24 घन्टे महानगरों को बिजली देने का काम करेंगे और दिया भी।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इसमें यह होता है कि जब आपकी अपनी बारी आवे तो आप खड़े होकर हमारी बात का खंडन करिये। यह बैठकर यों–यों करने से कोई फायदा तो है नहीं। आप अपने नम्बर पर पूरी मुस्तैदी से अपनी बात कहिये। अगर यही आदत बराबर बनी रहेगी तो आदत खराब हो जायेगी। आपने एम0ओ0यू0 का प्रपत्र हस्ताक्षरित किया है, मुख्य मंत्री जी मैं आपसे ही कहता हूं कि आप हर जिले का शेड्यूल मंगा लीजिये कि कहां कितनी बिजली मिल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी यह सदन है और यह वह सदन है अब तो बिगड़ गया सब मामला। संसदीय कार्य मंत्री जी भी जान रहे हैं और महाना जी भी जान रहे हैं, मौर्य जी भी जान रहे हैं। यह वह सदन है जब यहॉ कोई सदस्य बोलता था सत्तापक्ष से प्रश्न करता था, मंत्री उसको नकारते थे लेकिन अगर कोई सदस्य खड़ा हो करके यह कह दे कि क्या मा0 मंत्री जी मेरी बात को सही मान करके इस बात की जांच करायेंगे तो मंत्री के सामने कोई विकल्प नहीं होता था वह कहते थे हमारा सदस्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं एक दिन गांव रहने के लिए गया, मेरा गांव मेरे क्षेत्र से बाहर है, मैं जब पढ़ने आया तब से बलिया में ही हूं, जब गांव गया तो सोचा कि आज गांव में खाया जायेगा, सोया जायेगा लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी खा तो लिये लेकिन उसके बाद हमें बक्शा उठा करके बलिया आना पड़ा। आप शिड्यूल मंगा लीजिए कहने दीजिए इन लोगों को, ये यही कहते रहेंगे तो फिर मामला खत्म हो जायेगा। आप मंगा लीजिए, वास्तविकता से आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, लखनऊ में हमको बिजली मिल रही है, बनारस में मिल रही है, गोरखपुर में मिल रही है, मेरठ में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है लेकिन गॉव में नहीं मिल रही है। बिजली की हालत इस समय सबसे खराब है हालांकि इस समय मांग भी बहुत अधिक नहीं है, फिर भी खराब है। हमने कहा था कि यदि सरकार में लौट करके आयेंगे तो 24 घण्टे बिजली देंगे लेकिन आये ही नहीं, आते तो देते, आप आये हैं तो दीजिए हंसिये मत। अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का जो बजट वर्तमान में आपने रखा है, इसके लिए जो हमारी सरकार ने बजट रखा था उसमें से भी आपने 10 करोड़ 925.11 लाख की कटौती कर दिया। आप कहते हैं कि हम उनके हितैषी हैं, कभी बाबा अम्बेडकर के चरण साफ करते हैं, कभी

दलित बस्ती में जा करके भोजन करते हैं, ये दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की भोली भाली जनता को तो भरमा लिया फिर बजट में क्यों कम कर दिया, कैसे इनके लाभ का काम करेंगे, यहां भी कमी कर दी। वित्त मंत्री जी, इन लोगों के जंजाल में आप फंसे, नहीं तो उपाध्यक्ष रहते, ठीक था वहां।

मा0 अध्यक्ष जी, हम जाते हैं बलिया, यहां से फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ मऊ होते हुए बलिया, सभी जगह पर हर दीवार पर लिखा है कि ''ना गुण्डाराज, ना भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार''। अरे ! वाह रे भाजपा सरकार, मा0 मुख्य मंत्री जी, थाने से ले करके तहसील, जिला, प्रदेश कहॉ आपने घूसखोरी रोकी है। कहां घूसखोरी रोकी है उसका एक भी उदाहरण दीजिए बल्कि मा0 दारा सिंह चौहान जी अपने जिला शायद महोबा गये थे मैंने अखबार में पढ़ा था तो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम कहां डूब करके मरें, अगर पहले हमारा जो काम 10, 50, 100 रुपए में हो जाता था आज वही काम 5 हजार, 6 हजार में हो रहा है। केवल दीवाल पर लिख देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कौन सा ऐसा नियम बनाया है, हम केवल आपकी बात नहीं करते हैं भ्रष्टाचार एक रोग है इस देश का, इस समाज का। माननीय मुख्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में शरीक हो करके मैंने राजनीति में आने का काम किया है। हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी मौजूद हैं जिस दिन हम लोग सम्मानित हो रहे थे, तो हमने वहीं से कहा था, भ्रष्टाचार पर बात हम लोग किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं करते हैं, मैंने वहीं से कहा था। हम तो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में शरीक होकर इस राजनीति में आये हैं लेकिन 30–35 वर्षों के बाद हम उससे बड़ा भ्रष्टाचार देख रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह रसूख हो गया है तो फिर उसको लिखना नहीं चाहिए जब आप जानते हैं कि आपके बूते के बाहर की चीज है भ्रष्टाचार को हटाना। भ्रष्टाचार और गुण्डाराज, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक पार्टियां, हम हर राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को चोर, गुण्डा, बदमाश कह रहे हैं। आज यह स्थिति हिन्दुस्तान की राजनीति में आयी है कि राजनीति करने वाला ऐसा बेइज्जत आदमी इस धरती पर कोई आदमी नहीं है। अध्यक्ष जी, किसी एम0एल0ए0, एम0पी0 या मंत्री का कोई सम्मान समाज में नहीं है। हम कहते हैं कि वह चोर हैं, वह कहते हैं कि हम चोर हैं, हम कहते हैं कि वो गुण्डा हैं, वह कहते हैं कि हम गुण्डा हैं तो समाज ने मान लिया कि जब सब, सबको चोर, गुण्डा, बदमाश कह रहा है तो नेता सब, चोर, गुण्डा ही हैं। यह परिपाटी गलत है। ठीक है कि हम सत्ता में आ गये। पांच वर्ष कोई पांच हजार वर्ष नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ। हम बहुत दिनों से, जब बहुत छोटे थे तब से देख रहे हैं घूसखोरी, भ्रष्टाचार केवल आर्थिक ही नहीं होता है, भ्रष्ट आचरण भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। हमारा आचरण क्या है ? कैसे हमको आचरण करना चाहिए। हम राजनीति में हैं, हमको कैसे काम करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, यह भी आचरण है राजनीति में। आज आप लोगों ने उसको ऐसा कर दिया है कि लगता है कि पूरे देश में राजनीति में

काम करने वाला आदमी भ्रष्ट और बेईमान के सिवाय कुछ नहीं है। यह स्थिति पैदा हो गयी है इस देश में।

मुख्य मंत्री जी, आप एक सिद्ध पीठ के योगी, आप भी इसी जंजाल में आकर फंस गये। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न गुण्डाराज। मैं नहीं, मैं ऐसी छोटी बात नहीं कहता लेकिन अगर लोग ही कहें कि यह सरकार डकैतों की सरकार, छिनैती की सरकार, बलात्कारियों की सरकार है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) हम नहीं कह रहे हैं, न ही मेरे जैसा आदमी इस बात को कह सकता है। मैंने शुरू में ही कहा कि यह गलत परम्परा है राजनीति में। एक नेता, कार्यकर्ता को गुण्डा, बेईमान अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहना ठीक नहीं है। कानून–व्यवस्था, छाती पर हाथ रखकर सोचिये 33 प्रतिशत इस नई सरकार के आते ही क्राइम बढ़ गया। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि ख ग ग ग , बोल रहे हैं।) रोज सदन में आ रहा है, नहीं भी आवे तो क्राइम बढ़ा है। कोई आपने नहीं बढ़ाया है। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि आपने बढ़ाया है।) पाठक जी, आप छात्र नेता रहे हैं और मेरे जैसा आदमी इस बात को मानता है कि छात्र नेता अगर सक्रिय राजनीति में आता है और अगर उस पर बेईमानी का आरोप लगता है कि तो किसी भी घनघोर बेईमान से भी वह ईमानदार रहता है, छात्र नेता। हम भी नहीं किये, आप भी नहीं किये, यह सतत् प्रक्रिया है। अब इसको कम करना अधिक करना आपके हमारे हाथ में है। इसको कैसे कम किया जा सके, कैसे कन्ट्रोल किया जा सके। अगर हम करते आप करते। आदि काल से एक आदिवासी खेमा दूसरे पर हमला करके कब्जा करता है। राजा के जमाने से पुलिस भ्रष्ट है और थानों की व्यवस्था कब से है, काहे को है। अब आप ऐसा ऐसा मत करिये, बताइये कब से है। इसलिये किसी को दोष देने से पहले अपने गिरेबां में भी झांक कर देखना चाहिए। किसी को दोष देने से पहले अपने को तौल लीजिये। मैंने उस दिन भी कहा था माननीय मुख्य मंत्री जी और आज भी कह रहा हूं कि कल घटना तो घटना, संगठित अपराध, 10–10, 20–20 की संख्या में, जैसा पहले जब हम छोटे थे, आप छोटे होंगें तो बड़े–बड़े डकैत गिरोह होते थे जो आज सफाया हो गया बीच में। जिनके पास बन्दूक भी नहीं थी, भाला, लाठी, बरछे से डकैती करते थे, वैसी डकैती की शुरुआत हो गई है। 10–10, 15–15 यह संगठित अपराध हो रहे हैं। यह बडे दुःख की बात है, समाज के लिये दुःख की बात है, हमारे आपके लिये दुःख की बात है। इसको कैसे कन्ट्रोल करेंगे ? हम लोग भी आपका साथ देंगें। कानून–व्यवस्था अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। समाज को कैसे हम व्यस्थित करेंगे, सब नेता हो रहे हैं। एम0एल0ए0 बनने के लिये लोगों में एकदम छटपटाहट है कि कैसे जल्दी से एम0एल0ए0 बन जायं। सामाजिक नेता बनना इस देश में बंद हो गया। कोई सामाजिक नेता बन ही नहीं रहा है। कैसे होगा। कानून–व्यवस्था वर्तमान सरकार

नोट :–[ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की चौपट ही नहीं है, खराब ही नहीं है, क्राइम का सुनामी लहर पैदा हो गया है। सुनामी आ गई है और तो और।

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)–

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नाम किसी का मैंने नहीं लिया।

श्री ब्रजेश पाठक–

नहीं एक मिनट। मान्यवर, मुझे भी पांच मिनट का मौका अन्त में दीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपको भी मौका मिलेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री ब्रजेश पाठक–

चूंकि मेरे को आपने इंगित किया है तो मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ऐसा है, यह बजट है। इस पर चार दिन चर्चा है। उसके बाद विभागवार बजट आयेगा तो कोई सदस्य बाकी नहीं रहेगा जिसको बोलने का मौका न मिले। मिलेगा सबको। कानून–व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष–

कानून व्यवस्था पर आप बोल चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इस पर है अध्यक्ष जी। आपने कहा कि आप कानून–व्यवस्था पर बोल चुके हैं। तो इस बजट भाषण में कानून व्यवस्था की बात आई है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं अभी आप बोल रहे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी तो भूमिका बांध रहे थे। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

मैंने पुराने वाले के लिये नहीं कहा जो आप अभी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि विषय हो गया।

श्री ब्रजेश पाठक–

इनके दुष्परिणामों का ही आज परिणाम है कि हम लोग इतनी कठिन व्यवस्था को झेल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल बैठे नहीं हैं तो उसमें इस तरह से।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह जानकारी नहीं होगी उनको। ज्ञान भी तो आवश्यक है। कोई एम0एल0ए0 होना जरूरी थोड़े है, ज्ञान भी जरूरी है। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, रोज डकैती, रोज छिनैती, रोज बलात्कार। अब तो घर से जो महिला निकले उसका चेन खत्म। गहना पहन कर कोई महिला नहीं निकल रही है। घर में अगर गहना जमा हो तो उसको डकैत ले ले। बैंक में जमा हो तो बैंक वाला कहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बैंक में जिसमें गहने रखते हैं क्या कहते हैं उसे, लॉकर, लॉकर में जो लोग गहने रखे थे उसको भी सफाचट कर ले गये तो बैंक कहता है कि लॉकर की जिम्मेदारी मेरी नहीं। महिला गहना पहनकर निकले तो सड़क पर छीन लें, गहना घर में रखें तो डकैत डकैती डाल कर ले ले, तो हमारी घर की महिलाओं का निकलना दूभर, गहना पहनना दूभर, कौन कानून–व्यवस्था है ? एक दिन में ठीक होगी,दो दिन में ठीक होगी,तीन दिन में ठीक होगी, और बात का प्रतिवाद किया जाए तो आपके बाद में कभी ठीक नहीं होगी। गम्भीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। भयमुक्त वातावरण नहीं है कहीं भी, अभी उस दिन कहा, भइया साधू तो सब मोह माया छोड़कर साधू बनता है अब उस साधू को भी मारपीट कर जो दान पुण्य में मिला है उसको भी चोर ले ले रहा है अभी मैंने उस दिन उठाया था सीतापुर का, किसान से डकैती, महिला से डकैती, पुरुष से डकैती,साधू से डकैती अब तो पशुओं की भी डकैती हो रही है और तो और माननीय मुख्य मंत्री जी पेड़, पौधों पर डकैती हो रही है आपके राज्य में माननीय मुख्य मंत्री जी, मुर्गी पर डकैती हो रही है तो कोई बाकी ही नहीं रहा (हंसी) कुछ भी बाकी नहीं रहा महिला उत्पीड़न माननीय अध्यक्ष जी महिला उत्पीड़न को रोकने में बजट में कोई व्यवस्था नहीं है इनके बजट में,जघन्य अपराध पीड़ित महिला, बालिकाओं की आर्थिक क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग का, कोई बजट व्यवस्था में उल्लेख नहीं है इस बजट में, हमने 11 करोड़ रुपया बजट की व्यवस्था की थी, आपने एक रुपया नहीं दिया सबके हितैषी हैं कन्या विद्या धन में जो गरीब लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, प्रोत्साहन के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इजाद किया था, पिछली सरकार ने उसे चालू रखा, वो भी आपने बन्द कर दिया। हमने 300 करोड़ रुपया की व्यवस्था की थी आपने एक पैसे की व्यवस्था नहीं की। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान दिए जाने का कोई जिक्र आपके इस बजट में कहीं नहीं है। हमने 637 करोड़ रुपया रखा था। कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि– मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं अंधा नहीं हूं हम सब कारगुजारी देख रहे हैं छात्राओं के सुरक्षार्थ शिक्षण ग्रहण करने हेतु हास्टल निर्माण के लिए आपके बजट में कोई व्यवस्था नहीं है हमने 244 करोड़ की व्यवस्था की थी कि जो गांव से देहात से, लखनऊ

इलाहाबाद बनारस अपने उत्तर प्रदेश में जो लड़कियां पढ़ने आती हैं उनके लिए हास्टल की व्यवस्था हो आपके बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 244 करोड़ की व्यवस्था की।आपने लोहिया आवास बन्द कर दिया इन्दिरा आवास बन्द कर लिया। माननीय मुख्य मंत्री जी योजनाएं किसी सरकार की खराब नहीं होती। लोहिया आवास में एक आवास का दाम था 3 लाख 20 हजार कैबिनेट में बहुत से मंत्रियों ने कहा मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव से कि आवास का दाम कम कर दीजिए जिससे अधिक लोगों के मकान बन जाएं। उन्होंने कैबिनेट में कहा था कि अधिक आवास बनाने की जरूरत नहीं है जो आवास बनें कम से कम एक दो पुश्त चले तो और अगर हमारी अगली सरकार बन जाएगी कहा था माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कोई इस प्रदेश में गरीब नहीं बचेगा जिसका हम लोहिया आवास न बनाएं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया है उसका दाम है एक लाख बीस हजार रुपया माननीय अध्यक्ष जी ओवरलोडिंग बालू खनन मंहगाई इतनी है कैसे वह बनेगा। वही मौर्य जी का झुनझुना गरीबों को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी चुनाव में बहुत भाषण हुए यहां तक कि वोट के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने जिनसे शक्तिशाली हिन्दुस्तान में कोई नहीं है ।

(सत्तापक्ष के लोगों द्वारा मेजें थपथपाने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने अकेले उनको नहीं कहा हर प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। उन्होंने भाषण में क्या कहा प्रदेश का मुख्य मंत्री सबसे शक्तिशाली देश का ख ग ग ग , सबसे शक्तिशाली ख ग ग ग , जी ने भाषण में क्या कहा कि ख ग ग ग , आप इस सदन के सदस्य नहीं है माननीय प्रधानमंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसलिए उनके बारे में कुछ न कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इनके जैसा झूठा सबका साथ सबका विकास वाले हम लोग नहीं हैं हम वास्तव में सबका साथ सबका विकास करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार ने कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाने का काम किया।

श्री ब्रजेश पाठक–

अध्यक्ष जी जो बातें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कह रहे हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए मैंने टोका था।

'**श्री सुरेश कुमार खन्ना**–

नोट :–[ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी एक तो नेता विरोधी दल असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो असंसदीय शब्द हो उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

परम्परा रही है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी की।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें। हमने टोक दिया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं उनको भाषा का ध्यान रखना चाहिए जो इस बड़े–बड़े इस सदन के अनुभवी सदस्य हैं उनके द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं होनी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी मैं संसदीय परम्पराओं को मानने वाला आदमी हूं आपकी जानकारी में अगर कोई असंसदीय भाषा हो गई तो उसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। देश में जिसके भाषण हुए हों वह भाषण कहा जाएगा। मैं भाषण का संदर्भ दे रहा हूं कि भाषण क्या हुये कि ख्गगग, तो क्या भाषण का जिक्र नहीं होगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यहां जिक्र नहीं होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ठीक है, आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे यह तो चेयर तय करेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण कहते हैं। अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह मा0 अध्यक्ष जी तय करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, यह भी ठीक नहीं है कि मैं खड़ा हूं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बार–बार खड़े हो जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नोटः–[गगग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप दोनों लोग मित्र हैं। आप लोग बजट पर बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बजट पर ही तो बोल रहा हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी पूरी बात कह लें, मैं बैठ रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बात तब होती है जब उधर से कोई अशोभनीय बात हो, कोई ऐसी बात हो जो आपत्तिजनक हो तभी टोका–टाकी होती है अन्यथा टोका–टाकी नहीं होती है। पूरे पौने दो घंटे हो गये, हम भी गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन जब सीमा से बाहर हो जाता है या कोई अशोभनीय बात होती है जो इस हाउस में बर्दाश्त नहीं की जाती है उसी बात पर टोका–टाकी होती है। अगर इस तरीके की बात होगी तो टोका–टाकी होगी।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर टोका–टाकी होगी तो इधर से बोला–बाली भी होगी। (समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) मा0 अध्यक्ष जी, मैं बजट पर बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में भाषण दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल मुसलमानों के कब्रिस्तान की चाहरदीवारी घिरवाती है। श्रीमान्, मैंने हिन्दुओं के अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी और अंत्येष्टि स्थल बना भी।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थानों से टोका–टाकी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप लोग कृपया शांत रहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, इस बात को नोट किये रहियेगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी का भी इस सदन में भाषण होगा। इस बात को आप नोट किये रहियेगा। हमनें अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आपको जब आपको अवसर मिलेगा तब आप बोलियेगा। अभी आप लोग शांत रहिये। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, अब आप संक्षिप्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, इनके बजट में अन्त्येष्टि स्थल के लिये कोई प्राविधान नहीं है। हमने इसके लिये 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था। मत्स्य पालकों के लिये हमनें 750 आवास की व्यवस्था की थी, आपने उसको घटाकर 666 कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी,

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के लिये हमनें विशेष पैकेज की व्यवस्था की।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन है कि क्या है। हम लोग आपकी अध्यक्षता में कैसे अपनी बात कहें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप लोग बिना अनुमति के खड़े हो रहे हैं, आप लोग बैठ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने बुन्देलखण्ड में फ्री भोजन।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा अपने स्थान से टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप बार–बार बीच में क्यों बोल देते हैं। आपके बार–बार टोकने से भाषण का समय लम्बा हो जाता है। जब आपका अवसर आयेगा तो आप बोल लीजियेगा, पूरा प्रतिवाद कर लीजियेगा। बार–बार टोका–टाकी करने से भाषण का समय लम्बा हो जा रहा है। कृपया शान्त रहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, फ्री भोजन का पैकेट शुद्ध घी के साथ। एक किलो का शुद्ध घी का पैकेट और आलू, चावल, आटा सब चीज गरीबों को पैकेट में दिया जाता था। सोलर लाईट का कारखाना बुन्देलखण्ड में खोला गया और मण्डी स्थलों का निर्माण किया गया। आपने बुन्देलखण्ड के लिए क्या किया है। आपने कहा कि हम सड़क से बुन्देलखण्ड को दिल्ली से जोड़ेगे। क्या गरीब आदमी सड़क पर पेट के बल पर चलेगा, क्या उसके पास गाड़ी है। बुन्देलखण्ड में सबसे गरीब किसान है और क्या वह एक्सप्रेस–वे पर पेट के बल घिसट कर चलेगा श्रीमान्। उनको भोजन चाहिये, उनको नौकरी चाहिये, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिये, उनके बेटो–बेटियों को दवाई चाहिये। एक्सप्रेस–वे से जोड़ देंगे तो वह क्या करेंगे। आपके बजट में पीने का पानी मुहैया कराने की बात कहीं नहीं है बुन्देलखण्ड के लिए। आप सड़क से जोड़ेगे दिल्ली से जैसे सीधे उड़कर राष्ट्रपति भवन में जाकर बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप कर लीजिये। अब तो आपके विषय सारे हो गये हैं। क्या अभी कोई पन्ना आपका बचा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद फिर हमको टाइम मिलेगा। मान्यवर, बस थोड़ा–बहुत बचा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा बर्दास्त कर लीजिये हमको। बस थोड़ा और बर्दास्त कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी तो आपके मित्र हैं। वैसे अब हो गये आपके पन्ने तो।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, 434 करोड़ रुपये से हमने मण्डी स्थलों का निर्माण बुन्देलखण्ड में कराया था ताकि किसान अपने अनाज को मण्डी स्थलों में ले जाकर उचित मूल्य पर बेंचे। आपने समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपा करें और बीच में न बोले।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा लम्बा अनुभव हमारा इस सदन का है जो लोग लप–टप बोलते हैं वह उसके बाद फिर कभी इस सदन में दिखाई दिये ही नहीं। हम वर्ष 1977 से हैं इस सदन में। जो बहुत ऐंठ कर विधान सभा में लप–लप करते हैं वो फिर कभी विधान सभा का मुंह नहीं देखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इतना मनोरंजक बोलते हैं, तो यह लोग मजा लेते हैं। आपसे कोई असहमत नहीं है और न नाराज है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हां, मजा लेते हैं, तो ऐसा बोलें तो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समाजवादी पेंशन बंद कर दी। समाजवादी पेंशन किसको दी जाती थी जो गरीब महिला है, निराश्रित हो, गरीबी से बेबस हो, लाचार हो, भूखी रहती हो ऐसी 55 लाख से ऊपर गरीब महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह समाजवादी पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था हमारी सरकार में की गई थी। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जायेगी तो इसको बढ़ाकर हम एक हजार रुपये कर देंगे और कहा था कि कोई भी गरीब महिला इस प्रदेश में नहीं बचेगी जिसको हम पेंशन से आच्छादित नहीं करेंगे। उसको भी आपने बन्द कर दिया। कोई दूसरी योजना उनके लिए चलाई नहीं गई। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनी। पिछली सरकार ने चालीस करोड़ और आर्थिक सहायता के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप कोई शेर पढ़कर भाषण को समाप्त कर दीजिये जो आपके पास कागज में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए भाषण खत्म कर देंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है पत्रकार। पत्रकारों के लिए सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आवास की व्यवस्था की थी। हम यह नहीं कहते हैं कि सबको आवास मिल गये हैं। पिछली बार हमने पी0जी0आई0 में प्रदेश स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री में दवाई की व्यवस्था की थी। श्रीमन्, यह पत्रकार ही ऐसे हों जो चाहे बरसात हो, गर्मी हो, हम आप पहुंचे न पहुंचे, सबसे पहले उन स्थानों पर पत्रकार पहुंचते हैं। चाहे पहाड़ी एरिया हो, जंगल हो, कहीं भी हो वह जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पत्रकारों को भी लोकतंत्र सेनानियों की तरह से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह से पेंशन की व्यवस्था की जाये। इस पर सोच या विचार करिए हंसने की बात नहीं है। श्रीमन् उड़िसा में पत्रकार तो पत्रकार उनके परिवार को भी पेंशन की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में आसाम में पेंशन के अलावा परिवार के लोगों को अलग से फंड की व्यवस्था की गयी है। कई जगह पत्रकारों को पेंशन की व्यवस्था है और दवा की व्यवस्था है। श्रीमन् यह बात सही है यदि उनकी किसी दुर्घटना में अगर दुर्भाग्यवश यदि कोई बात हो जाए तो उनका परिवार क्या करेगा ? मान्यवर, यह व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए भी करिए और पत्रकारों के लिए भी करिए। श्रीमन्, पत्रकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था जरूर हो और उनके परिवार के लोगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो और अलग से उनके लिए दवाओं की भी सुविधा हो। श्रीमन् कल पर्यटन विभाग के विषय में मा0 मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में मल्हार, अयोध्या में सावन मेला जो विश्व प्रसिद्ध है पूरब की मिर्जापुर, बनारस की कजरी उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं। श्रीमन्, सबसे बड़ी बात जहरीली शराब से बहुत जबरदस्त मौते हो रही हैं। इसको पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। श्रीमन्, जो शराब लोग गांव–गांव में बना रहे हैं, वह सब बंद हो जाना चाहिए। मान्यवर, जो कारागारों में वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष या 85 वर्ष हो गयी है उन कैदियों को मुक्त करने के विषय में बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गयी। पावरलूम्स और हैंडलूम्स के जो कारिगर थे उनकी सहायता संबधी कोई योजना नहीं की गयी। मा0 अध्यक्ष जी, यह बजट दिशाशून्य है। श्रीमन् मैंने शुरू में कहा था यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, महिला विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इसाई विरोधी है, बौद्ध धर्म विरोधी है यह बजट किसी के हित में नहीं है। श्रीमन् यह बजट केवल भारतीय जनता पार्टी के हित में है। मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ''नगमें न जवाब पैदा कर, जज्बे बेमिसाल पैदा कर, ऐब गैरों में देखने वाले, पहले खुद अपने में कमाल पैदा कर'' बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि बजट पर वरिष्ठ नेताओं के भाषण हो रहे हैं बीच में टोका–टाकी से व्यवधान पड़ता है और फिर विषयांतर हो जाता है। मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाये रखें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आपने 2017–18 के आय–व्ययक पर चर्चा का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में किये गये वायदों के आधार पर इस बजट की प्रतीक्षा थी। लोग आस लगाये बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के हितों के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मुहैया कराये जाने के लिए बजट लेकर आयेगी। मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में चर्चा करते हुए इस बात का जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिए। इनकी पूर्ति हेतु साधन चाहिए। यह संभव होगा जब देश के हर आदमी को काम मिलेगा। इसलिए हर हाथ को काम आधारभूत व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। इस बात का जिक्र किया था। लेकिन मान्यवर, इन्होंने जब बजट का इंतजाम किया तो निश्चित रूप से उस बजट को देखने के बाद इस बजट का जो विस्तार है उसको देखने के बाद निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को निराशा हुयी। आमजन को निराशा हुयी। प्रदेश के सामने जो इन्होंने घोषणा किया था उसको इन्होंने बजट में कोई प्राविधान करने का कोई काम नहीं किया। मान्यवर, हर व्यक्ति विकास चाहता है। और सदन के दोनों पक्ष के सदस्य की यह चाहत होती है कि प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। लेकिन केवल कहने से, घोषणाओं से प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश के विकास के लिए वित्तीय अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जनहित के लिए उसके अंदर दृढ़इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए।

मान्यवर, लेकिन हम लोग लम्बे समय से देख रहे हैं और पहले भी देखा था जब 1997 से लेकर 2002 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कथनी और करनी में अन्तर है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जब सरकार रही थी तो वित्तीय प्रबंधन इस तरह से था कि लोगों का 2–2 महीने तक भुगतान नहीं हुआ करता था।

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पाठासीन हुए)

आए दिन ट्रेजरी पर रोक लगी रहती थी। मान्यवर, आज हम लोगों की जो अपेक्षा थी कि प्रदेश के लिए एक अच्छा बजट आएगा। माननीय मंत्री जी ने 3,84,659.71 करोड़ रुपये का भारी–भरकम बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। मान्यवर, इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने पिछले वर्ष के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक बजट प्राविजन किया है। हमने मान्यवर, 2016–17 का बजट देखा, 3,46,935 करोड़ का था, जो 2015–16 के सापेक्ष 14.6 प्रतिशत अधिक था और मान्यवर, 2007–2008 में जिस बजट को प्रस्तुत करने का अवसर आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी को मिला था और पहली बार उन्होंने 2006–2007 में 22 परसेण्ट से ज्यादा बढ़ाकर बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। मान्यवर, यह बजट 10.9 परसेण्ट भारी–भरकम होने के बाद भी जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए

व्यवस्था होनी चाहिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और जो इस सरकार ने बार–बार घोषणा किया है, बार–बार इस बात का जिक्र किया है कि अपराध और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, उस कानून–व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि उन सारे मुद्दों पर कमी, कटौती करने का काम किया गया है।

मान्यवर, मैं मुख्य रूप से चर्चा करना चाहता हूं। माननीय सदन के बहुत से सदस्यों को जो केवल बजट भाषण पढ़कर पूरे बजट को समझ लेते हैं, जिसको इसमें हाईलाइट किया गया है, उसको मान लेते हैं कि यह बहुत कुछ है, पूरा अध्ययन करके, समीक्षा करके उसको जानना चाहिए। मान्यवर, जो बजट है, उसमें राजस्व व्यय में, शिक्षा, कला संस्कृति में 52,332 करोड़ था, 2016–17 में, 2017–18 में हो गया 50,490 करोड़ यानी 1841 करोड़ कम हुआ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की कल्याण की योजनाओं के लिए 5228.96 करोड़ था और इस बार 4910.93 करोड़ यानी 318 करोड़ रूपया कम दिया गया। समाज कल्याण तथा पोषण के लिए वर्ष 2016–17 में 20637.01 करोड़ रुपया था, 2017–18 में 15507.96 करोड़ यानी 5129 करोड़ रुपया कम दिया गया। ऊर्जा के सेक्टर में जहॉ 2016–17 में 13942.57 करोड़ रुपये था, इस बार 7060.80 करोड़ रुपये यानी 6881.77 करोड़ रुपये कम दिया गया। उद्योग तथा खनिज, मान्यवर, पिछले वर्ष के बजट में था 3105.72 करोड़, इस बार 1775. 60 करोड़ यानी 1330.12 करोड़ रुपया कम दिया गया। मान्यवर, राजस्व व्यय तो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी देनदारी है, जो वेतन है, साज–सज्जा है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन मान्यवर, किसी प्रदेश के विकास के लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण जिसको हम पूंजीगत व्यय के रूप में देखते हैं। मान्यवर, भारी–भरकम बजट जो 10.9 प्रतिशत बढ़ाकर इन्होंने प्रस्तुत किया, वहीं जो पूंजीगत परिव्यय हैं उसमें सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, सामाजिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय, आर्थिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय इन सब में मिलाकर मान्यवर 18620.39 करोड़ कम किया और हम कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास करेंगे, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि 5–6 प्रतिशत मंहगाई दर बढ़ी और पूंजीगत परिव्यय में 18620. 39 करोड़ रुपये की कमी की गई, प्रदेश का विकास कैसे होगा, पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण कैसे होगा। दूसरी तरफ मान्यवर, इनके संकल्प–पत्र में कहा गया है कि हम 25 मेडिकल कालेज खोलने का काम करेंगे, हमने पूरा बजट देख डाला, इसके सारे वैल्यूम को देख डाला, चिकित्सा शिक्षा का अलग बजट भी देख डाला और मैंने देखा तो बड़ी निराशा हाथ लगी, कहीं भी नए मेडिकल कालेजों के लिए तो छोड़ दीजिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो 2016–17 का बजट था, मान्यवर वह था 4218.92 करोड़ का और 2017–18 का जो बजट है मान्यवर 3525.45 करोड़ यानी 693.47 करोड़ कम किया। वृहत निर्माण जिससे कि परिसम्पत्तियों का निर्माण होता 1965.1 करोड़ था अब दस सौ चार यानी 960 करोड़ रुपया कम किया गया। उपकरण के मद में मान्यवर, 350.50 करोड़ था 2016–17 में इस साल 132.3 करोड़ यानी 218.18 करोड़ रुपया कम किया गया। औषधि के मद में, जो चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कालेजों में औषधि हम देने का

काम करते हैं उसमें 63 करोड़ रुपया पहले था, मंहगाई बढ़ने के बाद भी 63 करोड़ रुपया रखने का काम किया गया।

मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो निश्चित रूप से हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं जैसा मा0 मंत्री जी ने कहा अपने बजट में चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा उसमें भी वृहत निर्माण कार्य है जो 2016–17 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथी में 527 करोड़ रुपया था 2017–18 में 489 करोड़ रुपया रखा गया, उपकरण और पूंजीगत उपकरण में 300.14 करोड़ था, 173 करोड़ रखा गया, आधे से भी कम कर दिया गया। औषधि, रसायन में 519 करोड़ रुपया था अब मंहगाई के बाद भी इस वर्ष भी जहां बजट का आकार करीब 11 परसेण्ट बढ़ा है, वहीं औषधि रसायन उसी अनुपात में बराबर ही रखने का काम किया गया, उसमें कोई बढ़ोत्तरी करने का काम नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण 2016–17 में 3055.98 करोड़ था, इस बार 2475.61 करोड़ यानी 580 करोड़ रूपया कम करने का काम किया गया। लोक निर्माण विभाग मान्यवर, माननीय उप मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त बनायेंगे, प्रदेश के हर गॉव को सड़कों से जोड़ देंगे और जो संचार साधन और सड़कों का अनुदान है, उस अनुदान में मान्यवर, 2016–17 में पुनरीक्षित जो अनुदान था वह 17011.97 करोड़ था 2017–18 में 15444 यानी 1567.25 करोड़ रुपया कम किया गया। 1567.25 करोड़ रुपया सड़क और संचार की जो सुविधा है उसमें कम करने का काम किया। मान्यवर, इसी तरह से जो सेतुओं का था, लोक निर्माण में 57 अनुदान संख्या है, जिसमें सेतु बनता है 2016–17 में था 1569.04 करोड़ रुपया और इस वर्ष 2017–18 में रखा गया है 497.57 करोड़ यानी लोक निर्माण विभाग का सड़कों का जिससे जाल बनाया जा सकता है उस बजट में भी कमी करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा शिक्षा के मद हैं मैंने पहले जिक्र किया, उसमें कमी करने का काम किया गया। खेल कूद में कमी करने का काम किया गया। इन्होंने बड़े जोर–शोर से इस बात का जिक्र किया है कि हम डिग्री कालेज तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे और उस मद में जो पैसा रखा गया है, वह 21 करोड़ 12 लाख रुपया। केवल 21 करोड़ 12 लाख रुपया रखकर डिग्री कालेज तक सारी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की बात करना मेरे समझ से जनता को गुमराह करने का काम है। इसी तरह से कहा कि हम सभी जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे और उसके लिए बजट में प्राविजन किया गया 71 करोड़ 21 लाख रुपया। मान्यवर एक किलोमीटर सड़क बनने में अगर फोर लेन की सड़क बनती होगी, हमारे तमाम साथी जानते होंगे, कितना लगता होगा, ढ़ाई–तीन करोड़ से कम एक किलोमीटर बनाने में नहीं लगता होगा। चार लेन की बनना है उससे ज्यादा ही लगेगा और 71 करोड़ 21 लाख रुपया में कितनी किलोमीटर बनेगी इसका हिसाब आप लगा लें। मान्यवर, महंगाई बढ़ी है, आज मौरंग का जो मिल रहा है, वह तो मिल ही नहीं रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ पुलिस महकमें में भी कमी करने का काम किया गया। मान्यवर, बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया, इन्होंने कहा कि हम घाटा कम करेंगे, राजकोषीय घाटा जो है हम 2.97 प्रतिशत के करीब रखने का काम करेंगे और

इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 15 साल में बेहाल किया गया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आपके इसी बजट का जो आपने हम लोगों के संज्ञान में लाने का काम किया जो असली बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, अगर आप उसको देखे होते, 2007–08 के बाद 2011–12 में प्रदेश के 15–20 सालों में अगर राजकोषीय घाटा। सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद के 2.42 प्रतिशत आया है जो 15–20 सालों में सबसे कम राजकोषीय घाटा है। मान्यवर, यह कुशल प्रबन्धन से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल प्रबन्धन से यह सम्भव हो सका था। मान्यवर, इन्होंने जिस बात का जिक्र करने का काम किया और यह जो राजस्व प्राप्तियां है, जिसका इन्होंने जिक्र किया है कि हम इस बजट में 25 प्रतिशत जो राज्य का कर है उसमें इजाफा करेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा जब वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देने खड़े हों तो यह तीन महीने का जो राजस्व प्राप्तियां हैं, इसका उल्लेख जरूर करेंगे कि हम कितने प्रतिशत इजाफा करें हैं। मुझे सत्य आकड़े पूरी तरह से सही आकड़े प्राप्त तो नही हुए हैं लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि मात्र 13 प्रतिशत आप प्राप्तियां कर पायें है जबकि आपने वृद्धि का लक्ष्य 24 प्रतिशत रखा है। अगर 13 प्रतिशत है, अगर इसी तरह से घाटा होता रहा तो मान्यवर, पूरे साल में जो घाटा है जहां आज सात हजार चार सौ अड़सठ दशमलव आठ तीन करोड़ रुपया वास्तविक घाटा है, यह बढ़कर इसका कई गुना बढ़ जायेगा। लोक–लेखा से प्राप्ति सात हजार छः सौ करोड़ रुपया आपने जो विभिन्न लोगों का जमा होता है। विभिन्न निधियों का जमा होता है उसे लेकर आपने उसको दिखाने का काम किया है। पिछला शेष भी लेकर आपने दिखाने का काम किया है और जिसको लेकर आप लाभ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इन तीन महीने के बजट का विश्लेषण करेंगे। तीन महीने में जो आपने प्राप्तियां की हैं, उसको अगर संज्ञान में लेने का काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूॅ कि आपका घाटा बढ़ेगा। आपका जो राजकोषीय घाटा है वह भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से फिर आपको अपनी पिछली सरकार की तरह रोज ट्रेजरी पर प्रतिबन्ध लगाने का काम करना पड़ेगा। मान्यवर, इन्होंने बजट में इस बात को रखा है कि हम 10 परसेण्ट की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उसको प्राप्त करना कतई सम्भव नहीं हो सकेगा। मान्यवर, इसी तरह से जहां आपने कहा कि अपराध और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। आए दिन इस बात की चर्चा होती है, छोटे–छोटे लोग नहीं बड़े लोग भी अपराधियों को संरक्षण देने में, सरकार के जिम्मेदार लोग अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं और उसी का परिणाम है कि तीन महीने में अपराधों में भयंकर वृद्धि हुई है। मान्यवर, मेरे पास जो सरकारी आंकड़े हैं, कोई मेरे द्वारा बनाए गए आंकड़े नहीं हैं। पिछले तीन महीनों के ढाई महीने का मेरे पास आंकड़ा है। मान्यवर, इस ढाई महीने में हत्या की 434 घटनाएं हुईं, 1434 घटनाएं हत्या की हुई हैं जबकि पिछले वर्ष की जो घटनाऍ थीं उससे लगभग ये चार गुना बढ़ेगा। मान्यवर, बलात्कार की 1528 घटनाएं हुईं ढाई महीने में और पिछले वर्ष 2016 में जब जंगलराज था तो बलात्कार की 3419 पूरे वर्ष में हुई थीं। ढाई महीने में यह आंकड़ा 1528 हुआ, अगर आप उससे तुलना करेंगे तो यह 6000 से ऊपर जाएगा, करीब 6500 और 7000 घटनाएं होंगी। अब ये महाजंगल राज हो गया। इसी तरह से महिला उत्पीड़न

का है, जहां 2016 में कुल 11979 महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुईं थीं तो 5293 केवल ढाई महीने में हैं। अगर इसको पूरे वर्ष के हिसाब में लेने का काम करेंगे तो इसमें दोगुना से तिगुना जाने का काम होगा, डकैती की घटनाओं का चार गुना से ज्यादा होगा, लूट की घटनाओं का चार गुना से ज्यादा होगा। मान्यवर, अभी हर वर्ष, हर महीने लगभग 27 परसेण्ट अपराध बढ़ रहा है। अगर इस तरह की बढ़ौती जारी रही तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ेंगे।

मान्यवर, बड़ा लम्बा–चौड़ा इन्होंने वादा किया, लोगों को आवास देने की बात की और मैं देखता हूं कि लोग खड़े होते हैं, बड़े विकास की बात करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जब वे अपना उत्तर भाषण देंगे तो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 2007 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कोई पहले से नारा नहीं दिया था लेकिन कुशल प्रबन्धन करके किसान के उत्पादन को बढ़ाया था और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2009 और 2010 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को 2009 और 2010 में लगातार। मान्यवर, गरीबों के आवास की बात की जाती है, सड़कों के निर्माण की बात की जाती है। हमारे मित्र मा0 नेता विरोधी दल आगरा से लखनऊ की सड़क की बात करते हैं। अच्छी सड़क बनी है लेकिन प्रदेश का 20 हजार करोड़ रुपया खर्च करके बनी है और बहन कुमारी मायावती जी ने बिना प्रदेश की सरकार पर एक पैसे का भार डाले हुए आगरा से दिल्ली तक का ताज एक्सप्रेस–वे बनवाने का काम किया था। जो दुनिया की सबसे अच्छी सड़क है।

मान्यवर, निश्चित रूप से हम गरीबों की बात करते हैं आवास की बात करते हैं। आप किसी शहर में चले जाइये शाहजहांपुर में चले जाएं, बरेली में चले जाएं, लखनऊ में चले जाए। अगर तीन मंजिला गरीबों का आवास कहीं दिखाई पड़ता है। अगर उसकी भूमि की कीमत और लागत निकाल लें जमीन मूल्यों के साथ तो एक–एक आवास 10 से 15 लाख की कीमत का होगा। एक लाख से ज्यादा लोगों को आवास मुहैया कराने का काम केवल शहारों में बहुजन पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया। हमें उससे सबक लेना चाहिए और उसी सर्वसमाज के लिए किया था। अगर उस पैटर्न पर आप आवास बनाने का काम करेंगे तो शहर में रहने वाला कोई गरीब व्यक्ति बिना आवास का नहीं रहेगा और इतना ही नहीं मान्यवर, तमाम शहरों में हमने आवास बनवाये, जिनका आवंटन नहीं हो जिनका आवंटन नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से इस सरकार से कि जो वर्ष 2012–13 में बन कर कम्प्लीट हुए आवास थे, मान्यवर, कांशीराज शहरी आवास जिनका आवंटन नहीं हुआ है कृपया उसका गरीबों को आवंटन करा दें। पांच साल तो हुआ नहीं, मैं आभारी रहूंगा कम से कम गरीब लोगों को आवास मिल जायेगा।

मान्यवर, इसी तरह से हम लोगों ने सावित्री बाई फूले शिक्षा मद्द योजना शुरू किया था। इण्टर पास करने वाली छात्राओं के लिए साइकिल और 25 हजार रूपये उस सावित्री बाई फूले शिक्षा मद्द योजना के तहत बिना किसी जात और बिरादरी का भेदभाव किये करने का काम किया था, आपने इस बजट में कहीं भी उसका उल्लेख या

उस तरह की कोई योजना अपने महापुरुषों के नाम पर भी शुरू करने का काम नहीं किया। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ग्राम्य विकास योजना शुरू की गई थी। उस पैटर्न पर भी कोई योजना शुरू करने का काम नहीं किया। हमने पहली बार शुरू किया था। इस प्रदेश में गरीब महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक मदद् योजना चलाई जिसमें 31 लाख परिवारों को पहली बार हमने 400 रुपये पेंशन देने का काम किया था। हमारी चाहत थी कि एक करोड़ महिलाओं को पेंशन मिले। उसको प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का हमारा लक्ष्य था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसका नाम बदलकर समाजवादी पेंशन किया, 400 की जगह पर 500 रुपये कर दिया। निश्चित रूप से यदि वह एक करोड़ रुपये तक बढ़ाते तो हम और स्वागत करते। नाम बदला लेकिन महिलाओं के लिए किया और आपने उसको भी बन्द करने का काम किया। मान्यवर, कानून–व्यवस्था के साथ–साथ विकास सबकी जरूरत है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में वायदा करके आता है कि हम जीतेंगे तो हम क्षेत्र का विकास करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा राजनैतिक व्यक्ति है जो विकास की बात न करता हो लेकिन उस विकास के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है। उसके लिए बजट प्रबन्धन की जरूरत है। आपने उस दिशा में नहीं दिया। आपने जो बजट के बिन्दु गिनाये हैं, जिनमें पैसे की व्यवस्था करके आप प्रदेश के विकास को उचित दिशा में ले जाने का काम करते उस दिशा में भी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट प्रबन्धन करने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारी यह चाहत है कि उस दिशा में भी विचार करने का काम करें। इसी तरह से मान्यवर, हमारी सरकार ने वर्ष 2007–2012 में महामाया बालिका आर्शीवाद योजना शुरू की थी। बढ़ते हुए लिंग अनुपात को ठीक रखने के लिए, अगर किसी परिवार में लड़की पैदा होती तो उसको पैदा होते ही हमने लखपति बनाने की योजना शुरू की थी आज वह भी बन्द पड़ी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु और सामान्य वर्ग के छात्रों के स्कॉलरशिप की प्रतिपूर्ति की पहले हमने शुरुआत की थी। आज तमाम छात्र घूमा करते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, उसके लिए भी बजट प्रबन्धन करने की आवश्यकता है। लेकिन आज खोखले नारों में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से लोगों को हवाई सपना दिखाने में, मुंगेरी लाल का सपना दिखाने में काम करती रही चुनाव के भाषणों के माध्यम से, उसी तरह से जब यह बजट प्रस्तुत किया गया तो इसमें भी उसी तरह का खोखला, अगर 36 हजार करोड़ रूपये हमारे आज कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 67 हजार करोड़ रुपया बजट कृषि का बढ़ाया है। अब उसमें से 32,399 करोड़ रुपये कृषि में हमें कर्जा माफी का है, अगर उसको निकाल दीजिए तो आपने कितना बढ़ाया है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों के घटक में कर्जा माफी के लिए करने का काम किया गया है तो आपने कौन सा बढ़ाने का काम किया। दूसरी तरफ मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने पूंजीगत परिव्यय में जो कमी की है उसके चलते आप कैसे प्रदेश का विकास करेंगे हमें भी ज्ञान वर्धन करने का काम करेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। मान्यवर, हमारा यह मानना है कि निश्चित रूप से यह सरकार जिस तरह से जनता को गुमराह करके अपार बहुमत से आयी है और अपने कर्मों के बल जिस तरह से यहां पर पहला जो बजट देखने में आया

है यह जनता को निराश करने वाला है, जनता की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं का अनदेखा करने वाला बजट है। इन्होंने अपने संकल्प–पत्र में जिक्र किया है कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 70 लाख लोगों को रोजगार का मतलब 1 महीने 1 लाख 16 हजार 700 लोगों को रोजगार। 3 महीने बीत गए 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और वह रोजगार आपने मुहैया कराने का काम नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां 3 महीने में 3 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, आप बतायेंगे कि 3 महीने में कितने लोगों को रोजगार मिला है। 70 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना जो आपने दिखाया था उसको कैसे पूरा करने का काम करेंगे। लैपटॉप देने का जो सब्जबाग दिखाया था, उसको कैसे पूरा करेंगे। मान्यवर, इसमें सबसे ज्यादा अनदेखी पूर्वांचल के लिए की गयी है। हमें याद है कि 2011–12 में जब हमने बजट प्रस्तुत किया था, पूर्वांचल विकास निधि का 291 करोड़ रुपये का 2011–12 में बजट का प्रोविजन था, 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये का बजट था। आज 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये का बजट और पूर्वांचल के लिए 3 सौ करोड़, बुन्देलखण्ड के लिए 2 सौ करोड़ यानि दूना आकार बढ़ गया। माननीय वित्त मंत्री जी इतनी ज्यादती तो पूर्वांचल पर न करिए। लोगों ने सपना देखा था कि पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो शायद पूर्वांचल का भाग्योदय होगा लेकिन आपने केवल मात्र 3 सौ करोड़ रूपये किया है इससे कैसे काम बनेगा। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बजट केवल मुंगेरी लाल का सपना है। यह बजट प्रदेश को पीछे ले जाना वाला बजट है। यह बजट बेरोजगार लोगों का रोजगार छीनने वाला बजट है और विकास कामों को रोकने वाला बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे अवसर देने का काम किया इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'**श्री अजय कुमार लल्लू**–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कही गयी बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह जो बजट इस बार सदन में प्रस्तुत किया गया है लगभग 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रूपये का, यह बजट किसानों के लिए नौजवानों के लिए आम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के साथ छलने और ठगने का काम किया गया है। यह सरकार जब चुनाव प्रचार में थी तो इन्होंने जनता से बहुत बड़े–बड़े वायदा करने का काम किया। इन्होंने किसानों के साथ नौजवानों के साथ, आम लोगों के साथ एक विश्वास की गाथा जोड़ने का काम किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में इन्हें जिताकर इतने बड़े प्रदेश की बागडोर सौपने का काम किया लेकिन सरकार के 4 महीने हो गये और इन्होंने जो–जो संकल्प में जनता से वायदा किया था यह कभी संकल्प–पत्र का जिक्र इस बजट के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान में करने का काम नहीं किया। जिन नौजवानों को रोजगार देने की बात की रोजगार के नाम पर नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान इतनी बड़ी सरकार को एक आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहा था लेकिन नौजवानों को रोजगार देना तो दूर जो नौजवान पिछले सरकार में लगभग 11 हजार 512 जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित थे वह आज भी इस प्रत्याशा में थे कि सरकार बनने के बाद जो उन्होंने प्रतियोगी परीक्षायें पास की थी, जो सारे नार्म्स होते हैं परीक्षा पास करने के उसको पास करके इधर इंटरव्यू होने के बाद पुलिस वैरीफिकेशन होने के बाद भी उनको केवल नियुक्ति–पत्र मिलकर उन्हें ज्वाइन कराना था उनके साथ भी इन लोगों ने धोखा करने का काम किया। टी0ई0टी0 अभ्यर्थी जो लगभग इतनी बड़ी संख्या में आज पास करके नौजवान एक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हाल को झेलने का काम कर रहा है लेकिन आज बड़ी विडम्बना है कि टी0ई0टी0 प्रशिक्षु जैसे अध्यापकों की भर्ती के बारे में भी इन सरकारों ने अब तक किसी तरह का इस बजट में कोई प्राविधान करने का काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि चीनी मिल, 3 चीनी मिल चलाने की बात उन्होंने की। महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जनसंख्या पर आधारित प्रदेश है और 75 जनपद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं और मुझे लगता है कि केवल गोरखपुर के बारे में उन्होंने फिक्र किया और इस पूरे प्रदेश के बारे में कहीं से चिन्ता व्यक्त करने का काम नहीं किया। गोरखपुर से संबंधित पिपराइच, मुंडेरवा और बस्ती की चीनी मिल चलाने की घोषणा तो की, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं कहीं भी उसके विरोध के बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन उन वायदों का क्या, जब चुनावी भाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पडरौना में कही थी उन्होंने 100 दिन के अंदर पडरौना चीनी मिल चलवाने की बात कही थी। यही सदन है आदरणीय श्री मौर्य जी हमारे माननीय मंत्री जी विपक्ष के रूप में थे और उस समय पडरौना चीनी मिल नीलाम होने जा रहा था । माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यहां थे, हम दोनों लोगों ने यहां पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाकर उस समय उसे बेचे जाने से रोकने की वकालत की थी। महोदय, कठकुइंया का चीनी मिल हमारी आंखों के सामने कटकर बिक गया। उद्योग लगातार धीरे–धीरे बंद होते जा रहे हैं। जो देवरिया, कुशीनगर और अन्य जगह चीनी का कटोरा कहा जाता था, आज वह पूरा चीनी मिल उद्योग बन्द सा पड़ा है और जिन उद्योगों को चालू करने की बात इन लोगों ने की थी और इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार चुनाव में जनसम्पर्क के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी वह आज एक भी चीनी मिल कहीं चलने नहीं जा रही है। मात्र तीन चीनी मिल ही चलने जा रही हैं। महोदय, इन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आयेगी तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरा बजट का किताब उठा लीजिये अगर इस बजट में कहीं भी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में एक भी पैसा कहीं दिया गया हो तो महोदय इस बात की चर्चा इस सदन में जरूर होनी चाहिये ।

महोदय, यही नहीं नौजवानों को लैपटाप और एक जी0बी0 इटंरनेट देने की घोषणा इस लोक संकल्प–पत्र में की गयी थी। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट की किताब के किसी भी पन्ने में नौजवानों को लैपटाप और एक जी0बी0 इण्टरनेट की सुविधा देने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक महोदय, सड़कों के संदर्भ में गड्ढामुक्ति से लेकर नई सड़कों के चौड़ीकरण के मामले में जिस सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ जनता से वायदा किया। मैं समझता हूं कि इसमें पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं और सारे लोग जनता के समक्ष चुनाव में जब जाते हैं तो बहुत बड़े–बड़े वायदे सड़कों और पुलों के संबंध में करते हैं। आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बताया, जिला मुख्यालयों को राजमार्गो से जोड़ने की बात। महोदय, मैंनें पहले ही दिन माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र दिया था और मेरे जिला मुख्यालय से तमकुही तहसील मुख्यालय तक जोड़ने की सड़क आधी बनी हुयी है और ऐसी सड़कें जो एन0एच0–28 बी की तमाम सड़कें जो काफी दिनों से लम्बित हैं, उन तमाम सड़कों के निर्माण के बारे में अधूरी सड़कों पर पैसा देकर उनके निर्माण कराये जाने के बारे में इस सरकार को सोचना चाहिये था, विचार करना चाहिये था, लेकिन इस बजट में सड़कों के लिये इतनी कम धनराशि दी गयी है मात्र 71 करोड़ रूपया, जिससे मुझे नहीं लगता कि चौड़ीकरण तो दूर, एक किमी0 सड़क बनने में 2 करोड़ रुपये के आस–पास का जो खर्च आता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस धनराशि से इस सरकार ने मात्र 31 से 32 किमी0 सड़क का प्रायोजन ही इस किताब के माध्यम से करने का काम किया है। महोदय, इन्होंने पूरा यह बजट चारों धाम की तरफ इंगित किया है, बहुत अच्छी बात है, चारों धाम हमें जाना भी चाहिए लेकिन धर्म में जाने के बाद कुछ प्राप्ति भी तो होनी चाहिए। महोदय, संकल्प–पत्र में इन्होंने कहा है कि हर ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जायेगी लेकिन जरा इस बजट को देख लें क्या कहीं भी गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की बात की है। इन्होंने इसी बजट के दौरान इस बात को कहा कि जब मेरी सरकार आयेगी तो इन्सेफ्लाइटिस और कालाधन जैसी बीमारियों से मजबूती से लड़ने का काम करेगी।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन्सेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों से लड़ने का आपका कौन सा तरीका है, एक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बस उसके लिए बना पड़ा है। आप जानते हैं कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा हिस्सा इन्सेफ्लाइटिस जापानी बुखार से पीड़ित है, ए0ई0एस0 और जे0ई0 से हर साल नौजवान बहुत तेजी के साथ मर रहा है। इस साल तो अब तक 70 बच्चे इन्सेफ्लाइटिस से काल के गाल में समा चुके हैं। अगर आपकी उनके प्रति लड़ने की इच्छा रहती तो जितने इन्सेफ्लाइटिस से सन्दर्भित क्षेत्र थे, जनपद थे, उन जगहों पर वेंटीलेटरयुक्त बेड की व्यवस्था की जाती, वार्ड की व्यवस्था की जाती और सारे सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में डॉक्टर की तैनाती जरूरी अनिवार्यता के साथ की जाती लेकिन इसके लिए केवल टीकाकरण की बात की गई है। इन्होंने इसी सदन में कहा कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंप लगा करके हम लोगों ने 88 लाख इन्सेफ्लाइटिस का टीका लगाया है। महोदय, मेरी जानकारी में तो यह है कि केवल एक दिन मा0 मुख्यमंत्री जी गये और

कुशीनगर में उद्घाटन किये लेकिन उसके बाद टीकाकरण की कोई योजना कैंप लगाकर तो नहीं की गई अगर की जाती तो शायद हम लोगों के भी संज्ञान में आता, उस इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते जानकारी दी जाती लेकिन केवल घोषणा कर देने से इन्सेफ्लाइटिस से लड़ाई नहीं हो जाती। अगर आप इन्सेफ्लाइटिस से लड़ना चाहते तो आपको जिस कारण से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयोजन बनाना चाहिए था। आज काला ज्वर भी बहुत तेजी के साथ फैला हुआ है जो बीमारी वर्षों से समाप्त हो गई थी वह बीमारी आज आपके सामने पुनः मुंह उठाये खड़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार प्रदेश में काला ज्वर बीमारी में पाये जाने वाले मरीजों के लिए आवास और पेन्शन की व्यवस्था की जाती थी ठीक वह व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इन्सेफ्लाइटिस बीमारी गन्दगी के नाते होती है जो मड़ई के घर में रहने वाले, फूस के घर में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं उनके घर के बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं अगर उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए समुचित पानी की व्यवस्था हो जाए तो इन्सेफ्लाइटिस जैसी बीमारी इतनी तेजी के साथ न फैले। जे0ई0 का तो कुछ इलाज हुआ लेकिन ए0ई0एस0 का आज तक इलाज खोज पाने में यह सरकार असमर्थ रही है और कोई भी इन्तजाम नहीं कर पाई है। मान्यवर, पशु अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं हैं और यह एक जगह का मामला नहीं हैं अगर आप देखें तो एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को कम से कम तीन जगहों पर सम्बद्ध कर दिया जाता है। एक दिन वह एक जगह जाता है, दूसरे दिन दूसरी जगह जाता है, कभी तीसरी जगह जाता है। मान्यवर, पशु चिकित्सकों की भारी कमी है, फार्मासिस्टों की भारी कमी है। मेरी आपसे मांग है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके पशु चिकित्सकों की नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा करे। अगर आप पशु चिकित्सालयों को देखेंगे तो किसी भी पशु चिकित्सालय में बाउन्ड्रीवाल का कोई प्रावधान नहीं है। महोदय, बाउण्ड्री वॉल का भी प्राविधान करने का काम आपके माध्यम से मैं सरकार से करना चाहता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस सदन में बैठे हुए हैं। इस पूरे बजट में कहीं भी पुराने खम्भे, तार, लकड़ी के पोल या तमाम चीजों के लिए जो बजट दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है। आजादी के इतने साल बाद भी बहुत सारे ऐसे पुरवे हैं जिनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। आदरणीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत 250, 500 की आबादी से लेकर तमाम योजनाओं के माध्यम से गांवों में विद्युतीकरण तो हुए लेकिन आज भी तमाम गांव हैं जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुए हैं। जिन गांवों में विद्युतीकरण है आप पता करा लीजिएगा, बहुत सारे गांवों में आज भी लोहे तार से बिजली की सप्लाई है, बांस के खम्भे से बिजली की सप्लाई है, उन जगहों को चिन्हित करके रिपोर्ट मंगाकर बदलने की जरूरत है और ट्रांसफार्मर जो आपने घोषणा किया है कि 24 घण्टे के अंदर जो अधिकारी नहीं पहुंचा पायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महोदय, पता करा लीजिएगा पडरौना डिवीजन में, गोरखपुर डिवीजन में, कुशीनगर डिवीजन में, सभी जगहों पर किसी भी स्टोर में, किसी भी वर्कशाप में 10 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर नहीं है। 25–25, 20–20 दिन पर 10 और 25 के0वी0ए0

के ट्रान्सफार्मर मिल पा रहे हैं और ऐसे ट्रान्सफार्मर जो आज ही आते हैं और दूसरे दिन जल जाते हैं, इस तरह की स्थिति है।

महोदय, जहां तक किसानों के कर्ज माफी का मामला है, यह सरकार इतनी बड़ी संख्या लेकर आयी थी और प्रदेश का सारा किसान इनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा था, वह यह सोच रहा था कि यह सरकार बनी है तो जरूर किसानों का कर्जा माफ होगा। लेकिन वह क्या जानती थी कि जिस सरकार पर हमने भरोसा किया है वही हमारे साथ धोखा करने का काम करेगी। सवा दो करोड़ किसान इस प्रदेश में है और सवा दो करोड़ किसानों ने कर्जा लिया है, किसान तो बहुत हैं लेकिन सवा दो करोड़ लोगों ने कर्जा लिया है और मात्र कुछ लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। महोदय, मात्र 36 हजार करोड़ रुपया माफ हुआ है जबकि केवल उन्हीं लोगों का जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया था। क्या साधन सहकारी बैंक से लेने वाला कर्जा, क्या कृषि यंत्र के लिए लेने वाला कर्जा, क्या ट्रैक्टर लेने वाले किसानो का कर्जा, क्या ये कर्ज के मायने में नहीं आता। अगर पूरे किसानों का माफ होता तो 93 हजार करोड़ रुपया होता और मात्र 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। यानी 57 हजार करोड़ रुपया का आप क्या करने वाले हैं ? अगर आपके अंदर थोड़ा भी किसानों के प्रति ममता होती, किसानों के प्रति दर्द होता, किसानों के शुभ–चिन्तक होते तो जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया और सरकार आने के बाद किसानों का दो–दो लाख रुपये का कर्ज माफ करने का काम किया। (कांग्रेस सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) इसी तरह से आपको भी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था। इनके वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश अपने संसाधन से माफ करे। मैं पूछना चाहता हूं, देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो सबको चुनने का काम इस देश की जनता ने किया है और अगर देश की जनता ने किया है तो वह उसके प्रति उसी तरह आशा भरी निगाहों से देखने का काम करती है। महोदय, आज भी किसानों पर आर0सी0 जारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी बड़े कड़े शब्दों में चिल्ला–चिल्लाकर कह रहे हैं कि जो बैंक किसानों पर नोटिस जारी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महोदय, यह नोटिस इस बात का गवाह है 17/4 की नोटिस जारी हुई है। 17.4. की नोटिस जारी हुई है और यह एक किसान है जिनका नाम है सन्नू यह ग्राम रामपुर दुधही ब्लाक के रहने वाले हैं। 1 लाख रुपये की नोटिस जारी हुई है और इस किसान के घर रोज पुलिस जा रही है। आज किसान कर्जा के नाते आत्महत्या कर रहा है महोदय। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि दो लोग हार्ट अटैक से मर गये। मेरे ही क्षेत्र में दुधही में किसान हरदेव कुशवाहा पुत्र गोपाल कुशवाहा एक लाख 60 हजार रुपया उन्होंने एस0बी0आई0 से किसी से लिया था और डेढ़ लाख रुपये में अपना खेत बंधक रखा था। वह किसान सोचते रहा कि कैसे हम इस पैसे को देकर अपने खेत को बंधक से छुड़ायें। जब वह खेती में काम करने गया बिया छींट रहा था महोदय, और बिया छींटने के दौरान उसको हार्ट अटैक हुआ और वहीं वह किसान मर गया। इतना ही नहीं उसी दुधही ब्लाक के जानकी प्रसाद पुत्र रामधारी जो रामपुर जमनिया के रहने वाले हैं कर्जा माफ न होने के कारण इनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो

गई। इन लोगों ने सोचा था कि किसान तो किसान है और माफ सबका होगा। वह क्या जानते थे कि 2017 में वोट देने वाले किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। केवल 2016 तक के किसानों का कर्जा माफ होगा। वह बेचारे गुमराह हुए, इस प्रदेश की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा कर लिये और भरोसा का इतना बड़ा घात हुआ कि आज किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। आगरा में किसान ने आत्महत्या की और बहुत जगह किसान ऐसे ही मरने की स्थिति में आ गये। इन लोगों ने इस प्रदेश के उन तमाम किसानों की भावनाओं के साथ घात किया है।

सदस्य–

आगरा में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। मैं वहीं से विधायक हूं।

श्री अजय कुमार लल्लू–

पेपरों में मैंने पढ़ा था मान्यवर। आगरा में किसान ने आत्महत्या की है, यह मैंने पेपरों में पढ़ा था और उसी को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। महोदय, आज साधन सहकारी समिति बैंक जो वर्षों से बहुत सारे बंद पड़े हुए थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर मेरी बात को सुन रहे होंगें बनारस की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर यह घोषणा किया कि सभी बन्द साधन सहकारी समिति बैंक चलेंगे और आज तो आपकी यू0पी0 में सरकार है, देश में सरकार है पिछले समय समाजवादी पार्टी के सरकार में इतने ढेर सारे कागज मांग लिये गये कि वह साधन सहकारी समिति बैंक नहीं चल पाये। और आज भी वह तमाम साधन सहकारी समिति बैंक जिनमें किसानों का गन्ने का पैसा, तमाम चीजों का पैसा वैसे ही बाकी के आधार पर पड़ा है और उनको आज तक वह पैसा इसलिये नहीं मिल पाया कि साधन सहकारी समिति बैंकों में ताला लटका हुआ है। महोदय, अब तो देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सरकार इसका संज्ञान ले और इन साधन सहकारी समिति बैंकों को चलवाने का काम करे। महोदय, गृह विभाग के क्षेत्र में मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस जो कानून–व्यवस्था को संचालित करने वाली है और सबसे मजबूत स्तम्भ है अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो लोग सबसे पहले पुलिस को याद करती है। लेकिन आज दरोगा और सिपाही की पूरे 24 घंटे की ड्यूटी है। और उस 24 घंटे की ड्यूटी के नाते वह भी अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा जिस तरह से दिल्ली में 12 घण्टे की सेवा एक पुलिसकर्मी से ली जाती है ठीक उसी तरह इतने बड़े प्रदेश को सम्भालना है तो कम से कम 12 घंटे के अलावा 14 घंटे उससे सेवा ले लीजिये लेकिन कम से कम 8 घंटा एक दरोगा को, एक सिपाही को व्यवस्था करिये ताकि कम से कम अगर दो शिफ्टों में वह नौकरी करेगा तो काम बड़ी आसानी के साथ करेगा। महोदय, निवेदन करना चाहूंगा लेखपाल। कहा जाता है गांव में हम लोगों के पता नहीं और जगह कहा जाता है कि नहीं। **नीचे लेखपाल ऊपर महामहिम राज्यपाल।** मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा और न मैं गवर्नर साहब के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। लेखपाल की स्थिति यह है कि मात्र कम पैसे में वह अपना जीवन चलाता है और सारे लोगों की जरूरत उसी लेखपाल से है। आज जरूरत है उसे लैप टॉप देने की, प्रशिक्षण देने की,

आज जरूरत है उनको ऐसा वेतन देने की, कि वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकें। उसके लिए एक प्रायोजक बनाना चाहिए और लेखपाल को उन तमाम सुविधाओं को देना चाहिए जिससे आज के इस भौतिक युग में वह आसानी के साथ किसानों का, आम लोगों का, ठीक ढंग से काम निस्तारित करने का काम करें। महोदय भ्रष्टाचार की चर्चा हुई, भ्रष्टाचार आज वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। मुझे याद है बिहार में आदरणीय नितीश कुमार जी ने इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक व्यवस्था संचालित की। उन्होंने टोल फ्री नम्बर लांच किया अगर कोई भी कर्मचारी किसी से भी एक पैसे का घूस मांगता था उस टोल फ्री नम्बर पर फोन कर देता था तो उसकी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती थी और उसके बाद उससे सम्पर्क किया जाता था और जब वह अधिकारी या कर्मचारी कहीं भी जाता था अगर किसी से घूस की स्थिति होती थी वह तुरन्त वहां रंगे हाथों पकड़ा जाता था लेकिन यहां इतनी बड़ी प्रक्रिया है जब तक डी0जी0 आदेश नहीं करेगा तब तक विजीलेंस का एक भी दरोगा, एस0पी0 कहीं नहीं जाएगा। अगर एक आम आदमी मिल रहा है किसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए कि यह आदमी हमसे इतना पैसा मांग रहा है तो उसे आना पड़ेगा डी0जी0पी0 से आदेश कराने के लिए। डी0जी0पी0 आदेश करेंगे तो विजिलेंस के एस0पी0 के पास जाएगा तब दरोगा नियुक्त होगा तब वह नोट देगा तब वह पकड़ा जाएगा मुझे लगता है यह प्रक्रिया करने में भ्रष्टाचार कहीं से खत्म होने वाला नहीं है। महोदय, इसको सरल बनाया जाए जो लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उन लोगों को जरूर इस तरह की व्यवस्था के अन्तर्गत पकड़ने की व्यवस्था शुरू की जाए।

महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में इन लोगों ने इतनी बड़ी चिन्ता व्यक्त की है कि सिंचाई के क्षेत्र में जो बजट संकल्प–पत्र में लिखा है बीस हजार करोड़, यह इतने बड़े किसान हितैषी हैं कि किसानों को सिंचाई देने के लिए बीस हजार करोड़ का प्राविधान करने का काम इस लोक कल्याण संकल्प–पत्र में अंकित है। लेकिन इसमें कितना पैसा दिया गया है नहरों में पानी के लिए कोई प्राविधान नहीं, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कहीं मुफ्त सिंचाई नहीं बुन्देलखंड में सूखे की मार झेल रहे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बुन्देलखण्ड के लिए कोई पैकेज नहीं, बुन्देलखण्ड का हर एक आदमी आज पानी के लिए तरस रहा है। इधर तो भगवान की कृपा से कुछ दिन से बारिश हुई है तो शायद कुछ सूखे से वह निजात पाने की स्थिति में होगा, लेकिन उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या दशा होगी जिस समय वह पानी के अभाव में वह दम तोड़ने की स्थिति में आया। श्रीमन् बुन्देलखण्ड अपने प्रदेश का सबसे अहम् प्रदेश है। जहां खनन के मामले में वह बहुत राजा है लेकिन पानी के मामले में वह बहुत गरीब है ऐसे प्रदेश के बारे में एक अलग इन लोगों को पैकेज देने का काम करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कर दें।

श्री अजय कुमार लल्लू–

पांच मिनट में खत्म करूंगा। महोदय पूर्वांचल में आज गम्भीर बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी का फेल होना, ब्रेन हेमरेज, हेपेटाइटिस भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसका कारण यह है कि पानी में कहीं आयरन की मात्रा ज्यादा कहीं गन्दे पानी की स्थिति और पानी ठीक न होने के नाते यह गम्भीर बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। आप उठाकर देख लें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष का पैसा जाता है या विधायक निधि का जाता है तो सबसे अधिक इन्हीं मदों में जाता है मेरे क्षेत्र में पूर्वांचल में तो इन बीमारियों का बाढ़ सा आ गया है, मैं निवेदन कराना चाहूंगा कि उस इलाके के पानी की जांच कराकर कैसे उस बीमारी पर नियंत्रण पा सकें इसकी समुचित व्यवस्था कराने का काम करें। आज कानून–व्यवस्था की हालत क्या है आज चारों ओर लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती चरम सीमा पर है कोई प्रदेश का हिस्सा ऐसा नहीं है जहां रोज हत्या न हो, रोज व्यापारी न लूटा जाए अब तो हालत यह है मैं एक जगह की घटना बता रहा हूं हमारे क्षेत्र में तमकुहीराज है वहां पर एक व्यापारी संदीप बर्मा उसने सबेरे–सबेरे दुकान खोला जैसे ही उसने दुकान खोला अपना बैग रख दिया कुछ बन्धक का सामान सोना और पैसा था मोबाइल था जैसे ही उसने सामान रखकर लोटिया में पानी लाने चला गया पूजा करने के लिए वह क्या जानता था कि पूजा उसको इतनी भारी पड़ेगी वह आया तब तक उसका बैग लेकर कोई भाग गया यह घटना केवल वहीं की नहीं है आज जिस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वह शहर दहला हुआ है आप देख लीजिए मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन जब वह जाते हैं उसके एक दिन पहले हत्या हो जाती है इस बार तो उनके आने के बाद भी हो गई अगर आप केवल गोरखपुर का आंकड़ा निकलवा लें वहां पर रोज हत्या, लूट, डकैती की भरमार है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें दो और दलीय नेता बोलने के लिए हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू–

अधिष्ठाता महोदय, अगर आपका आदेश हो तो दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आज पूरा प्रदेश अपने आप में डरा सहमा है। सीतापुर देवरिया में अभी जायसवाल परिवार के पिता को स्टूडियो चलाने वाले को और बेचारा एक आम जीवन बीमा एजेण्ट को गोली मार दी गई पांच सौ मीटर पर पचास मीटर दूरी पर वहां रेलवे पुलिस थी और पचास मीटर दूरी पर सामान्य पुलिस थी दोनों पुलिस की चौकी वहीं पर और दोनों पुलिस चौकी के बीच में एक आदमी को सरे आम गोली मार देने की घटना हुई। बहराइच में कुशीनगर में अन्य जगहों में आज लूट, हत्या, डकैती पूरी तरह से व्याप्त है अन्तिम बात के साथ इन लोगों ने नारा दिया था न गुण्डा राज न भ्रष्टाचार अबकी बार भाजपा सरकार महोदय इसी विषय पर अन्तिम बात के साथ चारों ओर लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, छिनैती से मचा है हाहाकार यही तो है भइया असली भाजपा की सरकार। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'**श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'**–

अधिष्ठाता महोदय सम्मानित सदन सबसे पहले सरदार बल्लबभाई पटेल जैसे डाक्टर सोनेलाल पटेल को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय साधारण बजट की चर्चा पर आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में एन0डी0ए0 की सरकार है और एन0डी0ए0 की सरकार 100 दिन में जो 15 साल का बीमारू उत्तर प्रदेश था 100 दिन में इस एन0डी0ए0 सरकार ने उसका इलाज करके उसको ठीक करने का काम किया है। पहले बिजली मात्र सैफई, मैनपुरी, इटावा, रामपुर में जाती थी लेकिन आज बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रही है। जब सैफई, मैनपुरी, इटावा, रामपुर में बिजली जाती थी तो उत्तर प्रदेश का पढ़ा–लिखा नौजवान अपने गांव में रोजगार की तलाश करने के लिए वह चाहता था कि गांव को भी बिजली मिले, लेकिन पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवानों को गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी जीविका चलाने के लिये, अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये उसने अपने गांव से 15 वर्षों में पलायन करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाने का काम किया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, वह घर से सपने लेकर जाता रहा कि बम्बई को जाऊंगा, दिल्ली को जाऊंगा, कलकत्ता को जाऊंगा और वहां पर पैसे कमा करके घर में आऊंगा तो बहन के हाथ पीले करूंगा, अपने पिता के पांव को एक बढ़िया जूता देने का काम करूंगा, मां को एक अच्छी साड़ी देने का काम करूंगा, अपनी घरवाली को सुहाग की चूड़ियां देने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान ऐसे सपने लेकर के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता को 15 वर्षों तक जाता रहा है, लेकिन वहां गन्दी नाली के किनारे रहने के लिये मजबूर होता रहा। लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हो करके उत्तर प्रदेश का नौजवान वहीं पर दम तोड़ने का काम कर देता था। मरने के बाद उसको कफन भी नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश के गांवों में यह चर्चा होती थी कि फलां का बेटा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने के लिये गया था, लापता हो गया और आज तक उसका कहीं अता–पता नहीं चला, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में 85 लाख बेरोजगार नौजवानों को प्रदेश और केन्द्र सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश के प्राईवेट सेक्टरों में योग्यता के अनुसार हर जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने काम किया गया है।

इस उत्तर प्रदेश में 15 सालों तक यूरिया का घोटाला जम करके होता था और यूरिया का घोटाला करने वाले वही थे जो दूध का धंधा करने का काम करते थे, यूरिया से नकली दूध बनाने का काम करते थे। यूरिया से नकली शराब बनाने का काम करते थे। उन लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर यूरिया का घोटाला किया जाता था, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इस केन्द्र की सरकार ने, इस एन0डी0ए0 की सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड करके यूरिया के घोटाले से इस देश और इस प्रदेश को बचाने का काम किया है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का किसान खुशहाल है, खुशहाली की जिन्दगी बसर कर रहा है। आज किसानों के होठों पर मुस्कान है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे जो मासूम बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिये जाते थे, मिडिल स्कूलों में पढ़ने के लिये जाते थे, 15 सालों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने उनको जो स्कूल की ड्रेस देने का काम किया है हमारे इन स्कूलों के बच्चे, भिखारियों के बच्चे नजर आते थे। हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में उन मासूम बच्चों को जो कल के उत्तर प्रदेश की तकदीर हैं, इस भारत की तकदीर हैं, कान्वेन्ट स्कूलों की तर्ज पर हमारी इस एन0डी0ए0 की सरकार ने उनको ड्रेस देने का काम किया है, उनको किताब–कापी देने का काम किया है। जयापुर गांव के प्राईमरी स्कूल, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जिस गांव को गोद लेने का काम किया है वह मेरी विधान सभा में पड़ता है, मैं उस गांव के विद्यालय में गया था। मैंने वहां पर ड्रेस बांटते हुये उन छोटे–छोटे मासूम बच्चों से जब यह पूछा कि बेटा यह ड्रेस तुम्हे कैसी लग रही है तो उन मासूम बच्चों ने चहक करके कहा कि हम लोगों को जो पिछली ड्रेस मिली थी वह अच्छी नहीं लग रही थी, यह ड्रेस हम लोगों को बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है। तो साथियों, ऐसी तमाम उपलब्धियां इस एन0डी0ए0 सरकार की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कई हजार वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का काम किया था, इस देश को लूला–लंगड़ा भारत बनाने का काम किया था, इस देश को आत्महत्या करने वाला भारत बनाने का काम किया था, इस देश को किसान आत्महत्या करने वाला भारत बनाने का काम किया था, उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश को लूला–लंगड़ा उत्तर प्रदेश 15 वर्षों में बनाने का काम किया गया है। इस उत्तर प्रदेश को 15 वर्षों में किसान आत्महत्या करने वाला उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया गया। पिछले पन्द्रह वर्षों में गरीब उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया गया, भूखा–नंगा उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया गया और इन सौ दिनों के अंदर उन सारी बीमारियों को माननीय योगी जी ने जो महावैद्य के रूप में इस उत्तर प्रदेश को मिले हैं, उन्होंने इस एक–एक रोग को पहचानने का काम किया है और जब उसका इलाज हो रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। प्राब्लम हो रही है और जब कलई खुलने वाली है तो इस सदन में तमाम लोग चिल्लाने का काम कर रहे हैं, अनाप–शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। अपना आपा खो करके तमाम फिजूल की बातें इस सदन में हो रही हैं, ऐसे–ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिनके अर्थ को यहां के तमाम हमारे माननीय सदस्य लोग हैं स्वयं आप भी उन शब्दों के अर्थ को समझने का काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे गंभीर विषय क्या हो सकता है, इससे खराब विषय क्या हो सकता है, इससे सदन की मर्यादा पर भी चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे शब्दों पर इस सदन के अन्दर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाये। मैं अपनी बातों को विराम करने से पहले इस देश के शहीदों के लिए कहना चाहूंगा कि–

''करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, मशाल फिर से जलाओ तो कोई बात बने। लहू
जो सूख गया है यहां शहीदों का, कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने।''

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता सुहेलदेव पार्टी यहां पर उपस्थित नहीं हैं और उनकी ओर से भी कोई बोलने के लिए उपस्थित नहीं है। एक सूची आई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो माननीय सदस्य यहां पर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी जी आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतनी विस्तार वाली बातों का संक्षेप में जवाब कैसे संभव होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप सत्ता पक्ष की तरफ से होकर इतना विस्तार में मत जाइये। आप कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिये।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे विपक्ष के माननीय विद्वान सदस्य बहुत देर से बजट का विश्लेषण कर रहे थे और उनके विश्लेषण को मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। वह मेरा दायित्व भी था क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिये मैं भी आज अपने माननीय सपा, बसपा और कांग्रेस के सदस्यों की ओर से नये तरीके से बजट का विश्लेषण कैसे होता है यह सीख रहा था क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में और पन्द्रह–सोलह वर्षों के अध्यापक जीवन में मैंने बजट का इस तरह का विश्लेषण पहले कभी देखा नहीं था। छांट–छांट कर उन बातों को कहा जा रहा था और उन आंकड़ों को यहां पर दिखाने की कोशिश हो रही थी जिससे लगे कि यह बजट खराब है। आधी–आधी बातें कही जा रही थीं। अगर हम अपने बेटे को मेला देखने के लिए सौ रुपया देते हों और यह कहते हों कि पचास रुपये का खिलौना खरीद लेना और पचास रुपये का खा लेना तो आधी बात कहना कि पिछली बार तो हमने नब्बे रुपये दिया था, लेकिन आपने मेला करने के लिए इस बार पचास रुपये ही दिया है, उस तरह का विश्लेषण आज मैं सुन रहा था। महोदय हमारे लोक कल्याण संकल्प–पत्र की भी बात हुई है। हम सबको पता है कि यह छह महीने का बजट है। इस छह महीने के बजट में पहली बार प्रदेश का विपक्ष यह चाह रहा है कि अगले पांच सालों में जो भी करने का हमने वायदा किया है वह इसी छह महीने में क्यों नहीं कर दिया। हम सब जानते हैं कि बजट पूरे पांच साल के कार्यक्रमों का पुलिन्दा नहीं होता है। हमको यह पता है कि बजट एक वर्ष का आय–व्ययक होता है और वह भी पिछला छह महीने का बजट तो आप प्रस्तुत करके गये थे। केवल छह महीने का बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, हमको विरासत में क्या मिला, हमको विरासत में मिला था प्रदेश की ध्वस्त कानून–व्यवस्था, हमको विरासत में मिला था आठ–नौ जिलों को छोड़कर धूप और अंधेरे में जी रहा उ0प्र0, हमको विरासत में मिले थे भू–माफिया, खनन माफिया, हमको विरासत

में मिला था हत्या, लूट तथा बलात्कार से कराहता हुआ उ0प्र0 और अध्यक्ष महोदय, हमको विरासत में मिला था लोकतंत्र की हत्या, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों पर लोगों को नामांकन पत्र तक नहीं भरने दिये गये थे। हमको विरासत में मिली थी, नकल आधारित शिक्षा व्यवस्था, हमको विरासत में मिला था लुंजपुंज औद्योगिक क्षेत्र हमको विरासत में मिला था, जो दोनों पार्टियां यहां बैठी हैं, एन0आर0एच0एम0 के घोटाले से पस्त हो गयी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमको विरासत में मिला था एक्सप्रेस–वे घोटाला, हमको विरासत में मिला था गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, हमको विरासत में मिला था ट्रांसफर–पोस्टिंग का धंधा। हम आपके प्रति आभारी हैं कि विपक्ष भी हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है कि वह मानकर चल रहा था कि इसी छः महीने के बजट में भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को ठीक कर देगी। शायद उनके मन में भी भाजपा के बारे में यह परसेप्सन है, यह विश्वास है इसलिए आपने हमसे यह उम्मीद की हमें इस बात की खुशी है।

श्रीमन्, रही बात इस बजट की छांट–छांट कर, मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 नेता बसपा के द्वारा उन आंकड़ों को दिखाने की कोशिश की गयी है, जिन आंकड़ों से यह लगे कि आपने तो कम कर दिया है। पूरा प्रदेश, पूरे पत्रकार, सारे विद्वान यह सब मान करके चल रहे हैं कि यह उ0प्र0 का सबसे बड़ा बजट है, 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह आप कौन सा नया आंकड़ा ले आये हैं जिसमें हर चीज में आप कमी दिखा रहे हैं। श्रीमन्, बजट के दो पक्ष होते हैं। एक पूंजीगत पक्ष होता है, एक राजस्व पक्ष होता है। जहां पूंजीगत पक्ष में कमी हुई हैं क्योंकि हमको उसने बढ़ोतरी की जरूरत नहीं थी। अरे, भाई थाने के लिए नई गाड़ियां जब आप खरीद लिये, 100 नंबर के लिए जब आप नयी गाड़ियां खरीद लिये, क्योंकि गाड़ियां खरीदने में बड़ा गोलमाल था तो क्या अब हम भी गाड़ियां खरीदें ? श्रीमन्, चूंकि हम अब गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं इसलिए पूंजीगत व्यय वहां कम नजर आ रहा है। श्रीमन्, कोई बिल्डिंग यदि आप बनाकर चले गये तो क्या हम भी बिल्डिंग बनाएं ? जब बिल्डिंग बनाने पर खर्च करते हैं तो पूंजीगत व्यय होता है, लेकिन जब कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं तो राजस्व का व्यय होता है तो जहां हमने खाली अस्पताल में ऑपरेटर्स देने की व्यवस्था की है या कर्मचारी देने की व्यवस्था की है तो जब हम यह राजस्व व्यय में दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब, यहां पूंजीगत व्यय नहीं हुआ है। श्रीमन्, मैं उदाहरण देता हूँ कहां–कहां वृद्धि हुई है ? आप लोक निर्माण कार्य की बात करेंगे, मैं पूरे आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूँ 228 आपके 2016–17 के बजट में हैं तथा हमारे बजट में 244 हैं आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। श्रीमन्, आज सामान्य शिक्षा में कमी हुई है यह दिखा रहे हैं और यह उलाहना भी दे रहे हैं कि आप रोजगार का इंतजाम कहां कर रहे हैं ? श्रीमन्, रोजगार का इंतजाम बी0ए0, बी0एस0सी0 करने से नहीं होगा। श्रीमन्, रोजगार का इंतजाम तब होगा जब तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमन्, जैसा हमने संकल्प लिया है, हर जिले में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाएंगे। श्रीमन्, प्रतापगढ़ के मित्रों से पूछ लीजिए कि इंजीनियरिंग कालेज की व्यवस्था हुई, उनको कितनी खुशी हुई है। श्रीमन्, हमने तकनीकी शिक्षा के बजट को जब बढ़ाया और उसको किया 34968 से 38772, इस पर

आपका ध्यान नहीं गया। आप क्या चाहते हैं कि हम भी वही बी0ए0 कराने वाले, जिसमें नकल करके केवल पास होकर बच्चे डिग्री लेकर बेरोजगार होकर घूमते हैं तो क्या हम भी वही करें ? श्रीमन्, मा0 वर्मा जी और चौधरी जी का ध्यान इन आंकड़ों पर क्यों नहीं जा रहा है ? हमारे ही बजट में जब हम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1545295 के मुकाबले 1631655 का खर्च कर रहे हैं तो आपको कौन पढ़ा रहा था कल रात को बजट, जो हम कल्याणकारी मुद्दों पर जिन पर हम खर्च बढ़ा रहे हैं वह आंकड़े आपको नहीं दिखा रहा था। मैं जान रहा था आपने अगर खुद यह किया होता तो यह बयान नहीं देते क्योंकि आप जानते हैं कि आप फंस जायेंगे। श्रीमन्, हम सबको स्वास्थ्य देना चाह रहे हैं, सबको स्वच्छ पेयजल देना चाह रहे हैं।

श्रीमन्, हमारे मित्र श्री अजय कुमार लल्लू जी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने यहां इंसेफ्लाइटिस की चिंता व्यक्त करी है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की जड़ खराब पानी है इसके लिए हम स्वच्छ पानी देना चाह रहे हैं इसलिए जलापूर्ति और सफाई पर 11975 के मुकाबले हम 140650 का जब व्यय कर रहे हैं तो आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है। श्रीमन्, आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारी केंद्र सरकार का संकल्प है कि 2022 तक हम सबको घर देंगे और जब हर झोपड़ी वाले को हम पक्का मकान देने की कोशिश करेंगे और शहरी तथा ग्रामीण दोनों आवासहीन लोगों को आवास देने के लिए जब हम 8578 के मुकाबले 17751 का खर्च कर रहे हैं तो आप कौन सा विश्लेषण कर रहे हैं आप बजट का जहां आपको यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से श्रीमन्, आज तो समाजवादी पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनसे बड़ा दलितों का मसीहा और कोई है ही नहीं और हमारे आदरणीय लालजी वर्मा भी मुस्कुरा रहे थे उन बातों पर। आप एक आंकड़ा लेकर बैठे हैं और यह टेक्निकली दिखा रहे हैं कि आपने इतना खर्चा कम कर दिया है। लेकिन हम सभी जानते हैं आज सबेरे चर्चा भी हो रही थी। वहीं दलित भाई हैं जिनके पास खेत नहीं होता है। कृषि से संबंधित जो सारी योजनायें लागू होती हैं वह उसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वह मजदूर हैं, भूमिहीन हैं। तो जब श्रम और रोजगार के क्षेत्र में हम अपना बजट बढ़ा रहे हैं। 107037 के मुकाबले 122772 कर रहे हैं। ताकि हमारे भूमिहीन दलित बंधुओं को रोजगार मिल सके तो यह आंकड़ा आपको दिखायी नहीं दे रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, यहां सदन को गुमराह किया जा रहा था कि यह कर्जा माफ नहीं हुआ वह कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प–पत्र में कहा था कि हम एक लाख रुपये तक का फसली ऋण जो 5 एकड़ से कम के किसान हैं, उनका किसी भी बैंक से लिया गया ऋण माफ करेंगे। इनके द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है। पिछली सरकार भी एक ऋणमाफी की योजना लायी थी। इन्होंने कहा था कि जिन्होंने को–आपरेटिव से ऋण लिया है केवल उन्हीं का ऋण माफ करेंगे। को–आपरेटिव पिछले 10 सालों से बन्द था। कोई लेन–देन नहीं हो रहा था। किसी किसान ने ऋण लिया ही नहीं था। बल्कि जो किसान को–आपरेटिव में पैसा जमा किये हुये हैं वह डूबा हुआ है। अभी हजार करोड़ रुपया हमारी केंद्र सरकार ने दिया है कि जो किसानों का पैसा को–आपरेटिव में जमा है उसका भुगतान करिये। जब किसान ने वहां से कोई लोन ही नहीं लिया था तो आपने माफ क्या किया। हमने जब 36

हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया। हम जब 86 लाख किसानों का हित करके बैठे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आंशिक ऋणमाफी हो रही है। दो करोड़ किसानों में सिर्फ 86 लाख का आपने माफ किया। अरे भाई, पहली साल में अगर हमने दो करोड़ कर्जदार किसानों में से 86 लाख किसानों का उद्धार किया है तो आप कल्पना करिये कि हम पांच साल में क्या करेंगे। पांच साल बाद किसानों के बीच आप जायेंगे तो वह आपको वोट मांगने नहीं देंगे। वह कहेंगे कि यहां से आप वापस जाइये हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं सारे आंकड़े नहीं पढ़ूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा कि चाहे आप मृदा तथा जल संरक्षण की बात करिये, चाहे पशुपालन की बात करिये, चाहे डेरी की बात करिये, मत्स्य पालन की बात करिये चाहे वानिकी की बात करिये, चाहे खाद्य भण्डारण करिये, चाहे कृषि अनुसंधान की बात करिये। यह सारे आंकड़े यह बता रहे हैं कि हमने पिछले बजट की तुलना में बजट बढ़ाया है। हम जब कह रहे हैं कि हम 25 मेडिकल कालेज खोलेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, वह इसी 6 महीने के बजट में नहीं खुल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां बैठे हुए विपक्ष के सदस्य यह कह दें कि क्या सारी खराब सड़कें चलने लायक हुयी हैं कि नहीं हुयी हैं पिछले दो महीनों में, अपने क्षेत्र में आप चल रहे होंगे तो आपको अन्तर महसूस हो रहा होगा। मान्यवर, बार–बार यहां कहा जा रहा है कि आप सबको बिजली देने की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें, अभी बहुत से मा0 सदस्य बोलने वाले हैं।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

अध्यक्ष महोदय, बार–बार दो तीन मुद्दों पर यहां कहा गया है कि आपने बिजली पर होने वाला खर्च घटा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। विपक्ष के कुछ सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको भी कुछ घण्टा देने को तैयार हूं। इस तरह से बजट का विश्लेषण नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं आपकी प्राथमिकता में जो–जो कार्यक्रम थे और आपने ठेकेदारी का बजट बढ़ा रखा था, कमीशन वाला हिस्सा आपने बढ़ा रखा था हम भी वही बढ़ा दें। हम वह करने नहीं आये हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको यह सब बन्द करने को कहा है और जब हमारी केंद्र सरकार देश के 18 हजार गांव जो विद्युत विहीन थे उनको अक्टूबर, 2018 तक बिजली पहुंचाने के लिए बहुत भारी मात्रा में धनराशि दे रही है, बिजली खम्भा वह लगा रही है, तार वह दे रही है तो हम उसे कौन सा बजट देंगे। हम लाइन लॉस कम करने वाले हैं। हम ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। हम जर्जर तारों को बदल रहे हैं। हम रोस्टर ठीक कर रहे हैं। हम बिजली विभाग की कार्य प्रणाली को ठीक कर रहे हैं और यह बहुत सारे काम जो हैं यह प्रशासनिक काम हैं। इसलिए आपको आंकड़ों में कहीं कमी नजर आती होगी। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के मा0 सदस्यों से कह रहा हूं कि वह बजट का ठीक से अध्ययन करें। जैसे एक्सपर्ट मा0 राम गोविन्द चौधरी जी को मिल गये थे वैसे एक्सपर्ट से थोड़ी दूरी बनाये रखें नहीं तो वह फजीहत करा देंगे। पूरे बजट को आप देखेंगे तो बजट सरकार की जो नीतियां होती हैं सरकार का जो संकल्प होता है उसका एक संकेत मात्र होता है।

मान्यवर, हम कहीं–कहीं बजट में एक रुपया एलॉट करते हैं, वह इसलिए एलॉट करते हैं कि हम बताते हैं कि यह कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। जरूरत पड़ती है तो हम व्यवस्था करते हैं। केवल समेकित निधि, समेकित निधि की चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने की, वह यह नहीं समझ पाये कि समेकित निधि में से हम एक रुपया भी किसी कार्यक्रम के लिए दे दें तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम हजारों करोड़ की व्यवस्था हम कर सकते हैं। वह हमारी प्राथमिकता बताता है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता से जितने वायदे किए थे, कह रहे हैं कि कानून–व्यवस्था की बात बजट में नहीं आयी। अरे, हम डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की बात 5 साल में कर रहे हैं, 30 हजार की बात इसी साल कर रहे हैं, क्या पुलिस कानून–व्यवस्था का हिस्सा नहीं होता है ? हमारे मित्र अजय जी कह रहे थे कि युवाओं के रोजगार की बात नहीं की गयी है, अरे, मा0 लालजी वर्मा जी तो इतनी बढ़िया गणित लगाकर आए थे कि 70 लाख रोजगार देने का आपने कहा है तो इस साल के लिए 3 लाख हुए, 6 महीने के लिए डेढ़ लाख हुआ। अरे, मा0 वर्मा जी, अगर कोई एक अध्यापक नियुक्त होता है तो वह 40 साल के लिए नियुक्त होता है, महीने–महीने में उसको बांटना मुश्किल होता है। इसलिए रोजगार का विवरण इस रूप में नहीं देखा जाता है कि हर महीने आपने कितना दिया ? सपा की सरकार ने तो 72 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 29 हजार शिक्षक भर्ती, 12 हजार शिक्षक भर्ती, 01 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था, आज वह सारे के सारे कोर्ट में पड़े हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, वह बेचारे जिस सत्रांस में हैं, हम इस तरह का रोजगार देने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार की ओर से आप सब को आश्वासन देता हूं, आप निश्चिन्त रहिए, हम उस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी की सरकार है, जो जितना कहती है, उतना तो करती ही है, जो नहीं कहती है, वह भी करती है, 05 साल बीतते–बीतते 70 लाख के मुकाबले हम 01 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले हैं और सपना मत देखिए, अगले 05 साल भी आप उधर नहीं जाने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, अभी मुझे मौका नहीं मिल पाया है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बजट ठीक से पढ़ूंगा तो और भी बातें कर पाऊंगा, इसी आश्वासन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 अरूण कुमार–

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार द्वारा जो भारी–भरकम बजट प्रस्तुत किया गया है, 3 लाख 85 हजार करोड़ का, जो गांव, गरीबों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों के कल्याण का बजट है, हमारे लोक कल्याण पत्र के हिसाब से है और मैं आपको सबसे खास बात बता दूं, हमारा विपक्ष क्या घबराया हुआ है ? उसकी खास वजह यह है कि हमने 36 हजार करोड़ रुपया किसानों का माफ किया, 33 हजार करोड़ रुपया सेवेंथ पे कमीशन का भुगतान करना है, 55 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाएं लाए हैं, फिर भी कोई नया टैक्स नहीं है। इनका तो सोचना यह था कि जब 36 हजार करोड़ रुपया माफ किया है, 33 हजार करोड़ सेवेंथ पे कमीशन का है तो नयी योजनाएं कहां से लायेंगे और नए टैक्स लगायेंगे तो हम इन्हें उधेड़ देंगे। लेकिन असलियत यह है कि इतनी होशियारी से बजट बनाया गया, योजनाओं को इतने अच्छे से

बनाया गया कि नयी योजनाएं लाये, अच्छी योजनाएं लाये, फिजूलखर्ची जो इनकी थी, वह कम की गयी, एपीजमेंट की जो पालिसीज थीं, उन पर जो खर्चा था, वह कम किया गया और एक अच्छा बजट लाया गया। किसानों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में तय किया कि हम 01 लाख रुपये तक किसानों का ऋण माफ करेंगे और 86 लाख किसानों का 01 लाख रुपया माफ करके 36 हजार करोड़ का बजट पर जो भार पड़ा लेकिन उसके बाद भी किसी पर टैक्स नहीं लगाया, किसान खुश हुआ। इसके पहले क्या किसी सरकार ने 01 लाख रुपया माफ किया ? बातें करना बहुत आसान है लेकिन एक काम करके दिखाओ, मैं कहूंगा कि यह हमारी ही सरकार है, जिसने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया। इससे पहले किसान का एक्सप्लायटेशन होता था, गेहूं खरीद हो, आलू खरीद हो, गन्ना के किसानों की सप्लाई हो, इन तीनों में किसी तरह का कोई एक्सप्लायटेशन नहीं हुआ और किसान की हर सम्भव मदद की जा रही है। किसान की आमदनी दोगुनी करने का हमारी सरकार का जो निश्चय है, वह शीघ्र पूरा होगा। स्वायल टेस्टिंग के लिए किसान को मुफ्त सुविधा है, गांव–गांव स्वायल टेस्ट हो रही है, किसान की फ्री टेस्ट हो रही है। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कार्य किया जा रहा है, सिंचाई में, ट्यूबवेल्स में और सभी तरीके में उनमें सब में बजट बढ़ाया गया है, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई और वो नहीं, किसान के लिए हर मुमकिन खर्च किया जा रहा है ताकि उसकी आमदनी बढ़े। सड़क का सवाल यह है जो लोग कहते हैं सड़क ऐसी–वैसी, मैं उनसे पूछता हूं कि पिछले सालों में हालत यह थी कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है यही नहीं मालूम पड़ता था, सड़कों की हालत इतनी खराब थी। आज हमारे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, नई सड़कें बनायी जा रही हैं, एक जिले से दूसरे जिले को फोर लेन से जोड़ा जा रहा है, जहां पर जरूरत है वहां पर पुल भी बनाये जा रहे हैं। साथियों लॉ एण्ड आर्डर की हालत तो इतनी खराब थी कि कोई इण्डस्ट्रीलयस्ट इण्डस्ट्री लगाने को यू0पी0 में तैयार नहीं था, लगभग ढाई साल पहले तब के मा0 मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी से पूछा कि आपने आगरा समिट किया, आपने बाम्बे समिट किया, आपने दिल्ली समिट किया, बहुत से उद्योगपतियों ने आपके साथ एम0ओ0यू0 किया कि वह उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्री लगायेंगे, 48 लोगों ने एम0ओ0यू0 किया, फिर 14 आये यू0पी0 में लगाने, लेकिन लगी सिर्फ 03 इण्डस्ट्री और बाकी सब पतली गली से निकल लिये, बोले यू0पी0 में नहीं लगायेंगे, हालत यह हो गई कि यू0पी0 में कोई इण्डस्ट्रिलियस्ट इण्डस्ट्री लगाने को तैयार नहीं था, यहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी खराब थी, जिसको अब हमारी सरकार सुधार रही है। नई उद्योग नीति ला रही है, रोजगार नीति ला रही है और हालत सुधर रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं पिछली सरकार में इण्डस्ट्री कोई लगी नहीं बल्कि जाने कितनी इण्डस्ट्री बन्द हो गईं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, हमारी सरकार नई उद्योग नीति और नई रोजगार नीति ला रही है। लॉ एण्ड आर्डर के लिए 30 हजार सिपाही और 32 सौ दरोगा इसी वर्ष में इन छः महीनों में नियुक्त किये जायेंगे, ताकि लॉ एण्ड आर्डर सम्भाला जाय। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार नौजवानों में भी रोजगार के लिए कौशल विकास को बहुत ज्यादा

प्रोत्साहन दे रही है, इस पर खर्चा बढ़ाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं नौजवानों को रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आज उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या मैं समझता हूं नौजवानों में बेरोजगारी, जो कौशल विकास और स्वरोजगार से ही दूर होगी, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत से लोग हथकरघा उद्योग में जुड़े हुए हैं और उनको रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही साथ बेटियों की पढ़ाई के लिए डिग्री कालेज तक उनकी पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था की गई है, इसमें पैसा बढ़ाया गया है और इसके साथ ही साथ माध्यमिक और बेसिक में भी पैसा बढ़ाया गया है। बेसिक शिक्षा के अन्दर बच्चों को अच्छी पढ़ाई, जहां स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोले जायेंगे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ–साथ उनकी भोजन व्यवस्था और साथ–साथ उनको ड्रेस दी जा रही है, जैसा कि अभी मेरे सभी साथियों ने बताया कि ड्रेस की हालत यह है, पहले तो बिल्कुल होमगार्ड बना दिया था खाकी कमीज खाकी नेकर, अब यह है कि बच्चों को अच्छी ड्रेस दी जा रही है, वह कान्वेण्ट स्कूल के बच्चों से अपना मुकाबला करते हैं, मैंने स्वयं कई स्कूलों में जाकर ड्रेस बांटी, बच्चों के चेहरे देख कर जो दिल को खुशी होती है, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। साथियों आप लोग जरा देखिये एक बार इन स्कूलों में जाकर जहां जिन बच्चों को नई ड्रेस, अच्छी ड्रेस, कलरफुल ड्रेसें दी जा रही हैं, उनके चेहरे की खुशी देखिये और इसके साथ ही साथ उनको किताबें अभी से ही दी जा रही हैं, इस पर भी खर्च पहले से बढ़ाया गया है। पिछले साल किताबें दिसम्बर के महीने में बंटी हैं, इस बार किताबें जुलाई से ही बंटना शुरू हो गई हैं, इसके लिए मैं यही कहूंगा हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ यह चीज प्रदेश के लिए अच्छी है वह कहें और दूसरे की अच्छी चीज को तो अच्छा मान लो, हर चीज को गलत कहना मैं अपोजीसन की इस बात से सहमत नहीं हूं। स्वास्थ्य के मामले में मैं यह कहूंगा कि 108 एम्बुलेन्स का नम्बर बढ़ाया जा रहा है जो पहले डेढ़ लाख जनसंख्या पर एक एम्बुलेन्स होती थी, अब एक लाख जनसंख्या पर एम्बुलेन्स बढ़ाई जा रही है, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो आ गये हैं, उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में बेहतर इलाज और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीनेशन में बहुत इम्प्रूवमेण्ट है, आज नौ रोगों के खिलाफ वैक्सीनेशन फ्री दिया जा रहा है। आज सुबह ही एक सवाल के जवाब में बताया गया। आज सुबह ही एक सवाल के जवाब में बताया गया कि जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस जो कि मच्छरों के काटने और गन्दगी से होता है। 88 लाख बच्चों के बजाए एक करोड़ से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। मैटरनिटी ऐण्ड चाइल्ड वेलफेयर पर हमारी सरकार ने बजट बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य में बजट घटा लेकिन मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं। मैटरनिटी ऐण्ड चाइल्ड वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है। कुपोषण के लिए अलग से प्रोजेक्ट है। कुपोषण, मैटरनिटी ऐण्ड चाइल्ड वेलफेयर तीनों का स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा असर है और मैं समझता हूं कि इन तीनों से हमारे प्रदेश के आने वाले नौजवानों का, हमारे प्रदेश के सभी लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तरक्की होगी। उद्योगों के बारे में मैं

कह रहा था कि पहले तो कोई आता ही नहीं था। आज हालत यह है कि सिंगल विण्डो सिस्टम हमारी नई नीति में आ गया है। सिंगल विण्डो सिस्टम से नये रोजगार लगाने में लोगों को आसानी होगी। पहले 18, 20 जगह से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती थी और एन0ओ0सी0 कैसे मिलती थी, यह अगर किसी इण्डस्ट्रलिस्ट से पूछो तो वह बताएगा। दो जोड़ी जूते घिस जाएंगे, एन0ओ0सी0 नहीं मिलेगी। हालत इतनी बदतर थी कि हर आदमी जहां जाओ वहां दुहने की कोशिश करता था। यही वजह थी कि इण्डस्ट्रलिस्ट भाग जाता था, भाग गया और अब जो नई नीति है उसमें मैं समझता हूं कि हमारे इण्डस्ट्रलिस्ट आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। साथियों, इसके साथ ही साथ वृद्धावस्था, विकलांग, महिलाओं की पेंशन 300 रु0 से 500 रु0 कर दी गई और इसमें भी हमारी सरकार ने बजट काफी बढ़ाया है। इस तरह से वृद्ध, गरीब, विकलांग, महिलाएं इनका जो ख्याल रखा गया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। बिजली की तो हालत यह है, मैं हमारे अपोजीशन के दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि दिल पर हाथ रखकर बताओ, पहले से ज्यादा बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। कोई यह कहने वाला नहीं मिलेगा कि बिजली कम आ रही है। पहले से बिजली बहुत ज्यादा आ रही है। ट्रांसफार्मर शहरों के अन्दर 24 घण्टे के अन्दर बदले जा रहे हैं, देहात के अन्दर भी ट्रांसफार्मर 48 घण्टे के अन्दर बदले जा रहे हैं। लोगों को बिजली में बहुत सुधार दिख रहा है और बिजली में सुधार से हमारे यहां इण्डस्ट्रीज़ आएंगी, हमारे यहां लोगों को रोजगार मिलेगा और साथियों पहले हालत यह थी बिजली के बारे में कि मेरे एक मिलने वाले साहब गए इंग्लैण्ड। उनके बच्चों की उनके 25वें बर्थ डे पर लन्दन से करीब 200 माइल्स दूर पर एक प्रोग्राम रखा और उसमें उन्होंने डिनर किया और उन्होंने वहां पर कुछ हल्की–हल्की लाइटें लगाईं और कम लाइट में बोले कि यह कैण्डिल लाइट डिनर है तो हमारे यहां से जो साहब गए थे उनका बच्चा बोला कि हमारे यहां तो रोज कैण्डिल लाइट डिनर होता है। हमारे यहां बिजली आती ही नहीं और तो और कैण्डिल लाइट डिनर क्या चाहो तो सुबह–सुबह कैण्डिल लाइट ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। यह हालत थी उस समय बिजली की और आज हालत यह है कि बिजली में बहुत सुधार है। बिजली पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आ रही है। मैं इसके लिए अपने ऊर्जा मंत्री को बधाई देता हूं। आज आप आम आदमी से पूछकर देखो कि बिजली अब पहले से कितनी बेहतर आ रही है। ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। लोकल फॉल्ट नहीं हो रहे हैं और उन गांवों में जहां बिजली नहीं थी वहां भी बिजली पहुंच रही है और अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचेगी और 24 घण्टे बिजली मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 डा0 साहब, समाप्त करें।

डा0 अरुण कुमार–

सर, एक मिनट और लूंगा। जो लोग पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली आती ही नहीं। वे अब ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली जाती ही नहीं। **(मेजों की थपथपाहट)** साथियों, अवस्थापना और नगर विकास में भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। खासतौर से अल्पविकसित क्षेत्रों में सड़क, नाली, सीवर, स्वच्छ

जल इसके लिए जो कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने अल्पविकसित के नाम से सिर्फ एक वर्ग विशेष के यहां सड़कें बनवाईं और मलिन बस्तियों में कहीं नहीं बनवाईं। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्दर 3000 करोड़ रुपया दिया गया है। हमारी सरकार का कहना है रोटी, कपड़ा, मकान। हर एक को मकान दिलाने के लिए हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, इसको काफी बढ़ाया जा रहा है और समझता हूं कि सभी को मकान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि सदन में तमाम सम्मानति नये सदस्य चुनकर आए हैं और ज्यादा–ज्यादा कोशिश हो की सभी माननीय सदस्यगण चाहे सत्तापक्ष के हो या विपक्ष के अपनी बात थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे तो सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिल जायेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि समय की पाबन्दी रखें पांच मिनट में ही अपनी बात रख दें।

श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी के वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर बजट भाषण में नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं आपके कृपापूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, कहां से शुरू करूं यही नहीं समझ में आता है माननीय सदस्यगण आए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से आए हैं और क्या जनता के बाहर से जीतकर आ गए। कोई कहता है कि बिजली बहुत मिल रही थी कोई कहता है कि कैन्डिल लाइट में खाना खा रहे थे। मान्यवर, अच्छी बात है लेकिन यह वह सदन है जहां प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने हम सब पर भरोसा और विश्वास देकर अपनी समस्याओं को उठाने के लिए यहां भेजने का काम किया है। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं तो आपके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे की बुराइयों को बताने के लिए विधायक नहीं हुये। कैसे जनता की समस्याओं का निराकरण हो, कैसे प्रदेश की जनता सुखी रहे, कैसे गरीब की थाली में रोटी पहुंचे, कैसे हमारा नौनिहाल बच्चा पढ़े, कैसे तमाम आवाम के बीच में जो दिक्कते हैं उनको दूर किये जाने के लिए हम आपस में विचार–विमर्श करें। मुझे तो लगता है कि लोग पैसा देकर जांच कराने जाते हैं। बहुत बड़ी–बड़ी रकम देकर लोग अपना एक्स–रे तथा तमाम जांचें करवाते हैं। हम विपक्ष के जरूर सही लेकिन आपके बीच में अगर समस्याओं को उठाने का काम करते हैं तो हम लोग हंसी के पात्र नहीं हैं। हम भी वहां थे, आप आज वहां हो, जो पुराने माननीय सदस्य यहां थे आज उधर बैठे हैं, तमाम साथी मंत्रीगण बन गए हैं, तमाम साथी विधायक हैं। पहले हमारे लोग भी ऐसे ही उछल–कूद मचाते थे, बहुत उछलते थे, समझते थे कि उधर ही रहेंगे इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लगता था, सत्ता में हैं अच्छी बात है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन तमाम

साथियों को जिन्होंने कहा कि कोई साथी अपने कलेजे पर हाथ रख ले कह दे बिजली कम आती थी कि ज्यादा।

(एक सदस्य द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

हम खुद पूछना चाहते हैं मैं आपसे जिरह नहीं करना चाहता आप ही बोल लें आप सदस्य हैं, बोल लीजिएगा, जनता ने चुनकर भेजा है। मैं बाराबंकी से आता हूं अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मैं अपना परिचय भी दे दूं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

टोका–टाकी न करें, कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री धर्मराज उर्फ सुरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां से मेरी विधान सभा केवल 12 से 15 किलोमीटर दूर है जो साथी सदस्य कह रहे हों कि बिजली नहीं आती हम चाहेंगे कि वह मेहमान के रूप में आज रात्रि को मेरे साथ निवास कर लें और मेरे यहां जाकर पुरानी सरकार का रिकार्ड निकाल लें और अपने तीन–साढ़े तीन महीने का शिड्यूल निकालने का काम कर लें। मैं बिजली पर नहीं जाना चाहता, मैं आपकी कमियां उजागर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर अगर प्रदेश की जनता को आगे ले जाने का काम करने में आपस में बैठकर विचार–विमर्श और अपनी योजनाओं को बताने का और अपने विचार आपके बीच में रखने का और सुझाव देने का काम करूं तो मुझे लगता है कि यह कोई गुरेज या हंसने की बात नहीं है। तमाम साथियों से मैं कह रहा था कि पैसा देकर हम लोग जाते हैं अपनी जांच कराने के लिए विपक्ष के साथी अगर जनता की समस्याओं को आपके बीच बताते हैं, तो सदन की एक गरिमा होती है। गरिमा में यह निहित है कि कोई भी माननीय सदस्य तीन–साढ़े तीन लाख, 4 लाख की जनता के बीच से चुनकर आता है, क्या वह ख ग ग ग , बोलने के लिए यहां आते हैं, क्या हम सभी ख ग ग ग , बोलते हैं, आप लोग उपहास करते हो। अपने–अपने सीने पर हाथ रखो कितने दरोगा सिपाही आपका कहना आज मान रहे हैं। मैं यकीन करके कहना चाहता हूं यहां से जाने के बाद सोच लेना आपका एक साथी क्या बोल रहा है। अभी लॉ एण्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, जिस जनता ने आप पर भरोसा और अपना यकीन सौंपा है, क्या वह जनता आज पूरे प्रदेश में सुरक्षित है, क्या जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। थानों में जाति विशेष के लोगों को 151 जैसी धाराओं में चालान होने लायक होता है। दो–दो, तीन–तीन दिन तक बैठा लिया जाता है केवल ज्यादा पैसा वसूलने के लिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो माननीय सदस्य बोल दें। माननीय सदस्यों को लगता है कि हम लोग आपकी निंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। बड़े भाग्य, बड़ी मेहनत, बड़ी किस्मत से आप सब जीत कर सत्ता में आएं हैं और बड़ी संख्या के साथ आएं हैं। आज अगर प्रदेश की हालत पर बात करें तो हम एक–दूसरे की निंदा नहीं करना चाहते हैं। यह क्राइम

नोट :–[गग ग , यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कैसे रुके, यह क्राइम कैसे कंट्रोल हो यह विचार की बात है, यह सोचने की बात है। हम यह बता दें कि कल के दिन में कितना हुआ, परसों कितना हुआ, इसके पहले कितना हुआ। अगर हम रक्षा कर पाते तो हमारी सत्ता न जाती। आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सत्ता में हो, आपकी जिम्मेवारी है कि आप पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए उन तमाम योजनाओं को बनाने का काम करें जिसमें जनता का हित है और जनता की सुरक्षा निहित है। वास्तव में कई सदस्यों ने कहा और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि बलिया तक जाते हैं तो रास्ते में लिखा रहता है कि 'न गुण्डई, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार'। आपको जनता ने यही भरोसा तो कर के भेजा है लेकिन क्या हो रहा है यह विचार करने की जरूरत है। यह विचार करने की जरूरत नहीं है कि कौन कह रहा है। आप सब लोग देवलोक से नहीं आएं हैं, जनता में रहते हैं और आप सब जरूर जानते होंगे। जो पहले हमने किया उसका चिंतन करने की अब जरूरत नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं या हम लोग जो बता रहे हैं अगर गलत बता रहे हैं तो उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बार विचार करने की जरूरत है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में आपके क्षेत्र की जनता भी आपसे पूछती होगी। कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप स्वयं जनता को जवाब नहीं दे पाते होंगे। मैं बाराबंकी जनपद से अकेला हूं, पांच साथी बाराबंकी से जीतकर आपकी पार्टी से आएं हैं। पूछिए क्या चल रहा है ? यहां दूसरे सदन की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर कहा जाए तो लॉ एण्ड आर्डर पर हमारे जनपद के सदस्यों से कह दीजिए वह अपना वक्तव्य दे लेंगे। वह सत्तापक्ष में हैं, सच्चाई तो नहीं बताएंगे लेकिन कमरे में पूछ लीजिएगा। एक अकेला बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे प्रदेश की हालत आप देख लें। किसानों के लिए वह किसान, वह गरीब, वह मजदूर जिसके लिए जब चुनाव आते हैं तो हम तमाम दलों के लोगों को उनकी याद आती है। किसानों के लिए करेंगे, मजदूरों के लिए यह करेंगे, छात्रों के लिए यह करेंगे, नौजवानों के लिए यह करेंगे, किसानों को क्या मिल रहा है ? कोई कहता है यूरिया वह खा गए जो दूध बेचते हैं। मैं यादव समाज से हूं और दूध वाले सब चोर नहीं होते, सब दूध में यूरिया नहीं मिलाते। माननीय सदस्य ने कहा कि यूरिया तो दूध वाले सब खत्म कर देते हैं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा हूं दूध का काम ज्यादातर यादव समाज के लोग करते हैं। अब आपकी सरकार है, मंशा साफ कर लीजिए और दूधवालों की जांच करा लीजिए। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार बनने से नहीं, नीम कोटेड तो बहुत पहले हो गयी थी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपस में संवाद न करिए। वह बोल रहे है तो उनको बोलने दीजिए तमाम मौका मिलेगा प्रतिवाद करने के लिए। अब दूध ही नहीं और काम करिए, चलिए बैठ जाइए।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जात–धर्म से, संप्रदायवाद से यह सदन नहीं चलने वाला है। हम सुझाव देते हैं, उस सुझाव को न मानिए। आप

हमारी जगह आ जाएंगे उसमें कोई जल्दी–देरी नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा पांच साल का समय पांच हजार साल नहीं हो रहा है। साथियों यह जरूरी नहीं कि हम आपकी निन्दा करें, आप हमारी निंदा करें, आप हमारा उपहास उड़ाओ लेकिन यह जरूरी है कि 22 करोड़, 25 करोड़ जनता ने जो भरोसा किया है अच्छे दिन के लिए, अच्छी तरक्की के लिए, अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल दो मिनट का समय चाहिए।

(टोका–टाकी से व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में ऐसे कौन से किसानों के लिए प्राविधान किया गया है। किसानों के लिए अगर देखा जाय तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं ने एक भरोसा दिया था कि हम लघु सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ करने का काम करेंगे। बजट में प्राविधान है लेकिन कितना है, कितने किसानों का है यह मैं पूछना चाहता हूं। अगर हम देखें गो सेवा आयोग बना है गो–शालाओं के लिए, कांजी हाउस पशु शेल्टर होम के लिए 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है हम सदन के माध्यम से जानना चाहते हैं कि गऊ हमारी माता है, सबकी माता है लेकिन वह बछड़ों और पड़वों के लिए कौन सा इंतजाम करने का काम किया है। जो किसान बड़ी मेहनत के साथ फसल पैदा करता है हमारे क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, बछड़ों, पड़वों और साड़ो से कितनी दिक्कत हुई। हमारे क्षेत्र में धनौली गांव है वहां हिन्दू मुसलमान के लिए पीएसी लगानी पड़ी यह मैं कहना चाहता हूं। गौ–माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ–रक्षा आयोग और गौ–सेवा आयोग बनना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार से अगर देखा जाय तो एक हौसला पोषण योजना पूर्व मुख्य मंत्री जी ने चलाने का काम किया था 1900 रुपया एक गर्भवती को मिलता था। इस योजना को बन्द करने का मकसद इस बजट में नहीं दिया गया इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से निन्दा करता हूं। मान्यवर, अगर देखा जाय तो ला एण्ड आर्डर के मामले में हण्ड्रेड डायल में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा और उसको चलाने में सरकार पूरी तरह से अक्षम है। आज अगर देखा जाय तो बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा बजट है लेकिन माननीय सदस्य हमारे बीच में है बता दें कि इनके जनपद के शहरी क्षेत्र के किनारे कितने टीचर हैं। बच्चे 8 टीचर 6, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे डेढ़ सौ टीचर एक भी नहीं शिक्षा मित्र हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ साथियों ने कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गयी चुनावी समय में और कहा गया कि कब्रिस्तान और श्मशान बनाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों में किया गया। आखिरी समय में हमको जाना वहीं पड़ता है चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत से साथियों ने कहा कि एक भी श्मशान नहीं बना है चलिये दिखा देते है 8 तो हमारे यहां ही है।

श्री अधिष्ठाता–

श्मशान पर मत ले जाइये।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

मान्यवर, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले नेवालों की बात हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने को नेता प्रतिपक्ष की बातों से सम्बद्ध करते हुए कटौती पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय उमा शंकर जी, आपकी कोई सूची है कि कल बुलवा दें ।

श्री उमा शंकर सिंह–

मान्यवर, आज कोई है नहीं, कल बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

टाइम हो गया है अब कोई बोल कर क्या करेगा, जब तक आप नियम–51 लेंगे तब तक खत्म हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

5 मिनट में कोई एक माननीय सदस्य बोल लें। ज्ञानेन्द्र सिंह जी बोलें।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कल बोलने का अवसर दीजिएगा तो 15 मिनट दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों को अगर अवसर मिलना है तो समय की पाबन्दी 5–5 मिनट में सब लोग अपनी अपनी बात रख लें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध किया हूं।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन में वर्ष 2017–2018 का बजट वित्त मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह भारी भरकम 3,84,659.71 करोड़ रूपया इस प्रदेश में बजट के रूप में विकास के लिये रखा गया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिनकी सोच है, जिनकी परिकल्पना है सम्पूर्ण प्रदेश का विकास, सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, मूल मंत्र था उस मूल मंत्र को लेकर हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी चल रहे हैं। इस सरकार में सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय से प्रदेश में विकास का काम हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सरकार जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग के आधार पर काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी मान्यवर, किसी भी रूप में चाहे केन्द्र की सरकार का कार्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास के कार्य हो रहे हैं चाहे जो भी कार्य हो रहे हों, गांव में विद्युतीकरण के कार्य हो रहे हैं, जिस मोहल्ले में मुस्लिम आबादी है, जिस मोहल्ले में यादव आबादी है क्या उस मोहल्ले में विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी भी कार्य में जाति–पांति, धर्म सम्प्रदाय, वर्ग कोई विषय नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है इस आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। बजट

की बात आई, किसानों के लिये कहा गया कि किसानों के लिये यह बजट उपयोगी नहीं है और गांव–गांव में बिजली की बात अभी हो रही है। हम सभी लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में बैठे है, याद नहीं होगा करीब 20–25–30 साल पहले पीछे जायें आप। शाम को घर पर पहुंचने पर घरवाली का मुंह कोई बिजली की रोशनी में नहीं देख पाता था। सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, मुझे भी कई बार इस सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, आज जो ऊर्जा मंत्री जी बिजली की व्यवस्था किये हैं, उन्हें भी बिजली नहीं मिलती थी। वी0आई0पी0 जिले हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में देखा जाता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी वी0आई0पी0 जिले देखे जाते थे, वहां 24 घन्टे बिजली दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, श्रीकान्त शर्मा जी की सरकार है, यहां कोई वी0आई0पी0 जिला नहीं है सब समान रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घन्टा, तहसील मुख्यालय पर 20 घन्टा और जिला मुख्यालयों पर 24 घन्टा बिजली दी जा रही है।

(इस समय 05 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इस सरकार में न कोई वी0आई0पी0 जिला, न कोई वी0आई0पी0 तहसील, न कोई वी0आई0पी0 मुख्यालय है। समान रूप से सबका साथ सबका विकास की मंशा से सरकार काम कर रही है। अभी किसानों की कर्ज माफी की बात हो रही थी, 36 हजार करोड़ 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने माफ की थी मात्र 50 हजार। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय चौधरी साहब बोल रहे थे, जिस समय अखिलेश जी का चुनाव के पहले रथयात्रा चल रही थी, उस समय इन्होंने घोषणा किया था कर्ज माफी के लिये, लेकिन जब इनकी सरकार बन गयी और जनता ने विश्वास किया। सरकार बनने के बाद इन्होंने घोषणा की कि एल0डी0बी0 बैंक का केवल कर्ज माफ होगा। एल0डी0बी0 बैंक मान्यवर, लखनऊ से पश्चिम में है। हमारे महाराजगंज में केवल एक एल0डी0बी0 बैंक है। कोई लोनर इस बैंक का है ही नहीं। अगर कोई लोनर नहीं, तो इन्होंने माफ किसका किया। मान्यवर, इसमें भी भेदभाव किया गया पूरब और पश्चिम का। अपने ही सैफई, इटावा, मुजफ्फरनगर, रामपुर ऐसे जिलों का कर्ज माफ किया गया। किसानों की बात हो रही है यह पहली सरकार है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हमने देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी हमने देखा है, जब धान का सीजन आता है, गेहूं का सीजन आता है अभी गेहूं का खरीद हो रहा था पूर्ववर्ती सरकारों के समय में गेहूं या धान का खरीद केवल कागज में होता था, बिचौलियों से लिया जाता था। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी जी की सरकार है इस सरकार में 36.99 लाख मीट्रिक टन 1625 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का भुगतान हुआ है। कहीं किसी प्रकार का कोई बारगेनिंग नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं और उस समय बिचौलियों से लेकर भुगतान किया जाता था। पारदर्शिता बनी रहे सरकार की यह सोच है, योगी जी की सोच है स्वच्छ प्रशासन। सारे कामों के लिये ई–टेन्डरिंग की व्यवस्था की गयी है। पहले लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर ठेका दे दिया जाता था। इसको भी मान्यवर, सुधार करने के लिये ई–टेन्डरिंग की व्यवस्था की गयी है। ताकि हर काम में पारदर्शिता बनी

रहे। अवैध बूचड़खानों पर बड़ी चर्चा चल रही थी, इस सरकार ने केवल अवैध बूचड़खानों को बन्द कराने की बात नहीं की है वह तो बन्द होंगे ही, हर अवैध कार्य को बन्द कराने की सरकार की सोच है और यह परिकल्पना है मा0 योगी जी की। कोई भी अवैध काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पायेगा इस सोच से हमारी सरकार काम कर रही है। एण्टी भू–माफिया टास्कफोर्स का गठन किया गया है जिसने अवैध कब्जा किया है उसी को दुःख हो रहा है, उसी दल के लोगों ने ज्यादा अवैध कब्जे किये हैं, जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, सब पर्दे पर आयेगा, सामने आ जायेगा। महिलाओं की बात हो रही थी, चौधरी साहब कह रहे थे कि कोई महिला जेवर नहीं पहन रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रही है। एण्टी रोमियो स्क्वायड का जब गठन हुआ, हम लोग स्कूल चलाते हैं वहां सभी परिवारों के बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ये जो कुछ मनचले, कुछ शोहदे लड़के स्कूल के गेट पर जा करके 10 बजे के पहले खड़े हो जाते थे, फब्तियां कसते थे लेकिन एण्टी रोमियो का गठन होने के बाद आज अभिभावकों की कोई शिकायत प्रबन्धकों के पास नहीं आ रही है कि लड़कों के द्वारा फब्तियां कसी जा रही हैं। किसानों की बात हो तो मृदा स्वायल टेस्ट, मैं भी किसान हूं 7 लाख किसानों का निःशुल्क मृदा टेस्ट हुआ है, किसान जान नहीं पाता है। किसान कम्पटीशन करता है, अगर हम अपने खेत में एक बोरी यूरिया डालते हैं तो किसान देखता है कि इनकी फसल अच्छी है तो वह सवा बोरी यूरिया डाल देता है, वह जान नहीं पाता है कि हमारी खेती नुकसान की तरफ बढ़ रही है तो मृदा स्वायल टेस्ट से यह हो जायेगा कि किसान को जानकारी दी जायेगी कि आपके खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, कौन सी फसल आप बोयेंगे और कितनी यूरिया आप डालेंगे, इस प्रकार से मान्यवर यह किसानों के हित में काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आप ज्यादा समय देंगे नहीं इसलिए मैं अन्तिम बात कह लेना चाहता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, पूर्वांचल पिछड़ा क्षेत्र है और उसमें से सबसे पिछड़ा जिला महाराजगंज है, पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोहगीबरवा जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, वहां जब किसी अधिकारी कर्मचारी को पनिश करना होता है, किसी पुलिस वाले को दण्डित करना होता है तो उसे सोहगीबरवा भेजा जाता है। सोहगीबरवा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जो इसमें प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं पर्यटन मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पिपराइच चीनी मिल को चालू करने की बात हो रही है, ये चीनी मिलें तो इन्हीं लोगों के समय में बन्द हुईं, इन लोगों ने चीनी मिलों को औने–पौने दामों में बेचा, और अपने लोगों को दिया, जितने में इन लोगों ने मिल को बेचा उससे ज्यादा तो स्क्रैप वहां लोगों ने बेचा है। अरबों रुपए की जमीन एक–एक चीनी मिल के स्थान पर पड़ी हुई है, पिपराइच चीनी मिल चला करके हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है, तीन चीनी मिलें चलनी हैं और पिपराइच चीनी मिल चलने से हमारे पूर्वांचल के किसानों के गन्ने की बुवाई बढ़ जायेगी इसके लिए भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से और मा0 वित्त मंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आगे जब मेट्रो का काम शुरू हो तो उसे

आगे भटहट तक बढ़ाया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को सस्ता साधन उपलब्ध हो जाएगा। अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि प्रदेश में कोई ऐसी विधान सभा क्षेत्र नहीं होगी, हो सकता है कि एक–दो विधान सभा क्षेत्र हों, कि जिस विधान सभा में एक–दो टाउन एरिया न हो, एक–आध तहसील न हो। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र पनियरा है, पनियरा विधान सभा में एक भी टाउन एरिया नहीं है, एक भी तहसील नहीं है, जनपद महाराजगंज में 5 विधान सभा क्षेत्र हैं चारों विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय, नगर पालिका, नगर पंचायत है लेकिन पनियरा एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां दो–दो मार्केट परतावल बाजार और पनियरा बाजार दोनों बाजार टाउन एरिया घोषित करने के लिए मानक को पूरा करते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि परतावल बाजार को और पनियरा बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की आप कृपा करेंगे। चूंकि उस विधान सभा क्षेत्र में कोई टाउन एरिया नहीं है। एक अन्तिम बात हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक नदी है। 2007–2008 में बंधा टूटा था, 27 आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान कृषि कार्य के लिए जा रहे थे वे सब डूब करके मर गये। जरदी–डीमरा बांध है, माननीय मुख्य मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है और आपके माध्यम से चाहूंगा कि जरदी–डीमरा बांध के निर्माण कराने की योजना हमारी सरकार के द्वारा हो ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 राजेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं भरपूर समर्थन करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख5.10, सदन की कार्यवाही कम से कम 6 बजे तक चलाये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आपने कहा था कि सदन थोड़ा ज्यादा देर तक चलायेंगे। कई माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

अध्यक्ष जी, कोई बोलना वाला है ही नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग बोलने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 7.00 बजे तक न चलायें तो 6.00 बजे तक तो चलायें ही।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, 7.00 बजे तक चलाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अब नियम–51 ले लीजिए, परसों से चलाइयेगा सात बजे, आठ बजे तक।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हाउस कम से कम 6.00 बजे तक तो चले।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों लोग अलग पंचायत कर लीजिए, हम चलाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री कब से गये हैं, मुंह–हाथ धोकर, खाना–नाश्ता करके तब आये हैं, फ्रेश हो करके आये हैं। तमाम माननीय सदस्य सवेरे से बैठे हैं और बहुत कम लोग खाना वगैरह खा करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी हमको–आपको कार्य–मंत्रणा में भी बैठना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी कार्य–मंत्रणा समिति की भी बैठक है। हम 10.00 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, रातभर बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इनकी बात मानकर बोलना शुरू कर दिये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि काफी माननीय सदस्य सत्तापक्ष और विपक्ष के बोलना चाहते हैं और हमारे पास जैसा कि सुबह बात हुई थी, पहले भी कार्य–मंत्रणा में बात हुई थी और आपने कहा भी था तो कम से कम आज 6.00 बजे तक हाउस चले।

श्री अध्यक्ष–

मैं सहमत हूं। माननीय श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी, नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

'संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, एक अनुरोध यह था कि इधर के लोगों की संख्या ज्यादा है तो ऐसा अनुपात निश्चित करें, कम से कम तीन और एक का हो जाए, तीन एक का न हो, तो दो एक का हो जाए। (प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज आयी कि दो–एक का कर लिया जाए।) यह मा0 अध्यक्ष जी के विवेक पर छोड़ दीजिए।

'श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, परसों 2017–2018 का बजट पेश किया गया, उस सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। लोकतंत्र की अजब विडम्बना है। दोपहर से बजट पर चर्चा चल रही है, हमारे विपक्ष के मित्रगण, प्रतिपक्ष के नेता, आप सभी ने जब कल अखबारों में आपको जगह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिली, इस प्रदेश की जनता ने बजट को सराहा और अखबारों में भी आपको जगह नहीं मिली तो आज उस बजट को दिशाहीन और औचित्यहीन बताने का प्रयास आप लोगों ने सदन में किया। मैं समझता था मेरा बोलने का समय कल आयेगा, 5 बजे तक ही सदन चलेगा। लेकिन आपने आज ही मुझे अवसर दिया तो मैं अपनी बात सदन में रख रहा हूं। मैं 2017–2018 के बजट की सराहना करता हूं और विपक्ष के लोग हमारे बजट में जो कमियां निकाल रहे हैं ऐसे सभी विपक्ष के नेताओं की मैं निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बजट पर बोलिये निन्दा प्रस्ताव नहीं।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

बजट पर मैं भी आ रहा हूं।

'श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रबोधन का कार्यक्रम भी कराया गया है। गजब–गजब शब्द आ रहे हैं। गजब–गजब चीज आ रही है, हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

आपकी समझ में आयेगा लेकिन आपने सदन का समय खाया है। दो घंटे आप बोले हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को 5 मिनट बोलने का समय नहीं मिलता है। जब मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नेता प्रतिपक्ष आपको रोकने के लिये नहीं। आप निन्दा की बात कर रहे थे उसके लिये भी वह कह रहे थे।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

अगर मेरे वक्तव्य में कोई कमी है तो मैं छोटा हूं, पहली बार सदन में आया हूं आप उस विषय को बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सही है। आप बोलिये।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

आज उत्तर प्रदेश का जो बजट है। कृषि में सबसे ज्यादा ध्यान हमारी सरकार ने दिया है। सड़क पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। बिजली की व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। कानून–व्यवस्था पर ऐसी चर्चा, जबसे सदन चल रहा है, ऐसी चर्चा की जा रही है जिससे लगता है उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है। मैं नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बात का स्पष्ट आदेश दिया है कि थानों में 100 प्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय तो आप रिकार्ड के आधार पर हमारी सरकार पर कानून–व्यवस्था खराब होने का आरोप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाते हैं यह कतई उचित नहीं है। अभी हमारे एक विपक्ष के नेता बोल रहे थे, सलाह दे रहे थे सत्ता पक्ष के लोगों को कि आप की थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे तो कमरे में इनसे बैठकर बात कर लीजिये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता थानों में दलाली नहीं करता है। और इन्स्पेक्टर और दरोगा भी दलाली नहीं करना चाहता है। हम विकास के लिये सत्ता में आये। विकास हमारा एजेन्डा है। बार–बार कहा जाता है कि दीवारों में लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुन्डाराज मुक्त सरकार हम देंगें। अभी तीन महीने हुआ है, जो ख्वाब हमारे विपक्ष के लोग देखना चाह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि कभी मैं यहां था आप इधर आ जायेंगे, एक समय वह भी आयेगा, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना विपक्ष के लोग बंद कर दें मैं इनसे यह कहना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में मैं बजट के ऊपर आ रहा हूं। हमारी सरकार ने कृषि के ऊपर काफी ध्यान दिया है। सड़कों के मामले में जो नगर के क्षेत्र हैं, मैं ग्रमीण क्षेत्र से विधायक चुनकर आता हूं रायबरेली से। नगर क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है। लेकिन जो सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आये हैं वहां के मुख्य–मुख्य मार्ग आजादी के बाद से जैसे संकरे थे वैसे ही आज तक संकरे बने हुए हैं। यह हमारी सरकार ने इस बजट में सड़कों के चौड़ीकरण के लिये बड़ा लम्बा चौड़ा बजट दिया है और इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सरनी विधान सभा क्षेत्र में लालगंज से जो भोजपुर का रोड जाता है यातायात के साधन बहुत बढ़ गये हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है, सड़कें वैसी ही पतली छोटी हैं। उसके चौड़ीकरण में ज्यादा से ज्यादा बजट हमारी विधान सभा में दिया जाना चाहिए। लालगंज से भोजपुर होते हुए दौलतपुर गांव जहां से पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिन्दी युग की स्थापना की जिनके नाम से हिन्दी युग जाना जाता है ऐसे युग पुरुष के जन्म स्थान में जरूर चौड़ीकरण होना चाहिए मैंने प्रस्ताव दिया है मैं चाहूंगा प्रस्ताव में इसको नोट किया जाए।अभी हमारी सरकार ने जो पी0एच0सी0 बनी हुई हैं, अस्पताल बने हुए हैं वहां के लिए भी एक लम्बा चौड़ा बजट दिया है। लालगंज कस्बा है हमारी विधान सभा क्षेत्र में, तीन लाख की आबादी उस पी0एच0सी0 में अपना इलाज कराती है और मात्र 30 बैड हैं उस अस्पताल में, मैं चिकित्सा मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि उसको 100 बैड का करा दिया जाए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत गम्भीरता से विचार किया है अभी जो थानों में पुलिस है जो बिजली के थाने खोलने का सरकार ने हमारी निश्चय किया है उसमें 75 थाने खोले जाएंगे और उसका टोल फ्री नम्बर भी दिया है 1912, मैं समझता हूं इससे आम जनमानस को काफी फायदा मिलेगा। पुलिस के ऊपर जो बिजली विभाग का भी लोड रहता था तमाम ऐसी घटनायें होती हैं गांव में, बिजली का तार गिर जाता है खेत में पेड़ जल जाते हैं और उसके मुआवजे के लिए थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ती है फिर लेखपाल के पास कार्यवाही जाती है लेखपाल एस0डी0एम0 के पास भेजता है एस0डी0एम0 डी0एम0 के पास भेजता है फिर बिजली विभाग से उसको कहीं मुआवजा मिल पाता है। ऐसे सराहनीय कदम उठाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और अपने ऊर्जा मंत्री का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है।

सिंचाई के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, नहरों में पानी हमारी विधान सभा क्षेत्र में सरैनी क्षेत्र की विधान सभा में पानी पन्द्रह से बीस वर्षों से नहीं है। वहां कम से कम चार लाख किसान उस नहर से प्रभावित होते हैं विधान सभा क्षेत्र में सरैनी ब्लाक डार्क जोन घोषित है। लखनऊ कमिश्नरी में अध्यक्ष जी, मात्र दो ब्लाक हैं जो डार्क जोन की स्थिति में हैं एक लखनऊ का चिनहट ब्लाक है एक रायबरेली का सरैनी ब्लाक है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि तमाम परियोजनायें जो पानी के संबंध में हैं वह अधूरी पड़ी हुई हैं। उनमें हमारी सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा बजट दे देगी तो वहां के लोगों को पानी की सुविधा मिल जाएगी जैसे हमारे बेहटा कलां गांव दुधवन गांव और खजुर गांव इन तीन गांव में पानी की टंकियां अधूरी पड़ी हुई हैं पिछली सरकारों में इतना विभाग के लोगों ने पैसे की डिमाण्ड किया कि टंकियां आधी अधूरी वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैं अपने मा0 नगर विकास मंत्री जी से ग्राम्य विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो परियोजनायें पैसे के अभाव में वहां लम्बित पड़ी हुई हैं वहां पर भी बजट चला जाएगा तो डार्क जोन क्योंकि सरैनी ब्लाक घोषित है तो वहां की जनता को पानी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह ग्राम्य विकास विभाग में, प्रधानमंत्री आवास योजना में चार हजार करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया है जो बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रतिपक्ष के नेता बड़े भाई आदरणीय चौधरी जी अगर आपको मेरी किसी बात पर लगा हो कि मैंने कोई अपमानजनक शब्द कोई आपके बारे में कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन मैं भी छात्र राजनीति से निकलकर आया हूं और मैं समझता हूं यह सदन...

श्री अध्यक्ष–

वह प्रशंसा कर रहे थे।

वह आपकी प्रसंशा कर रहे थे। आप भी प्रसंशा कर रहे हैं।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

बजट की मैंने सराहना की है बजट तो हमारा ऐसा है कि यह बजट में कोई कमी निकाल नहीं सकते हैं। बजट में जब चर्चा करने के लिए समाचार–पत्रों में जब विपक्ष को जगह नहीं मिली तो आज सदन में नेता प्रतिपक्ष दो घंटा बोले उसके बाद एक घंटा दूसरे नेताओं ने बोला हम लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

खूब तो मिल रहा है।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

मुझे मालूम है कि अभी अध्यक्ष जी टोक देंगे इस नाते मैं विस्तार में उतनी बात नहीं कर सकता हूं इसलिए मैं अपने वक्तव्य को समेटते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो बजट हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित किया है इस बजट की मैं सराहना करता हूं और आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सत्ता पक्ष के दो सदस्य बोल चुके हैं प्रतिपक्ष का शायद कोई बोलना नहीं चाहता।

'श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं हमारी सरकार ने 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तुत किया है जो पिछले सरकार के बजट से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। इसमें प्रदेश के लघु सीमान्त किसानों के फसली ऋण की अदायगी सरकार द्वारा की जाएगी इसके लिए 36 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूं । गत 13 वर्षों में 9 सालों तक बुन्देलखण्ड में सूखा रहा है 9 वर्षों के सूखे में सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वह भी मुआवजे की राशि शेष है मेरा अनुरोध है कि यह जो मुआवजे की राशि शेष है वह किसानों के लिए जिले को भेज दी जाए जिलाधिकारी को राशि भेजकर मुआवजे की राशि बंटवाई जाए। बुन्देलखण्ड में 13 साल में 9 साल सूखा रहा है दूसरा पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 10 करोड़ रुपया रखा गया है जिससे बीहड़ बंजर तथा जल भराव वाली भूमि तथा छोटे किसानों को आवंटित भूमि का सुधार किया जाएगा यह भी सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है मैं चूंकि बुन्देलखण्ड से आता हूं और बुन्देलखण्ड के लिए सरकार ने चार–पांच योजनाएं दी हैं इसलिए मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं एक बुन्देलखण्ड को दिल्ली से हाई–वे से जोड़ने की योजना है जबकि बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ है वहां हाई–वे मार्ग नहीं हैं दूसरा 110 नलकूप बुन्देलखण्ड को दिए गए हैं निश्चित रूप से हमारे चित्रकूट को भी उसका लाभ मिलेगा। बुन्देलखण्ड को जैविक खेती में लिया गया है। इससे भी हमारे बुन्देलखण्ड को लाभ होगा और 200 करोड़ रुपया विशेष क्षेत्र निधि में दिया गया है इससे भी हमारे बुन्देलखण्ड को विशेष लाभ होगा। चित्रकूट में परिक्रमा पुनर्निमाण तथा भजन सन्ध्या स्थल निर्माण के लिए धनराशि सरकार ने दी है इसके लिए भी मैं सरकार की प्रसंशा करता हूं। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं हमारे विपक्ष के जो वरिष्ठ सदस्य हैं मैं नेता प्रतिपक्ष का बड़ा सम्मान करता हूं उन्होंने दो तीन बातें कहीं थीं उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं बुन्देलखण्ड में जो खनिज निकलता है बालू है, गिट्टी है, मौरंग है, इसमें पिछली सरकारें गुण्डा टैक्स लेती रही हैं यह बात मेरी हो सकता है कि थोड़ी बुरी लगे मैं बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन सच्चाई है जैसे ही योगी जी की सरकार आई यह गुण्डा टैक्स बन्द हो गया यह एक बहुत बड़ी बात है और उसके अलावा बात हो रही थी कि लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है मैं चित्रकूट जिले से आता हूं हमारे यहां पिछली सरकारों में जब भी भर्तियां हुई हैं लड़कों को नौकरी नहीं मिली और उस विषय पर मैं न भी जाऊं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का क्या हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम चाहे वह परगनाधिकारी के पद रहे हों। चाहे वह पुलिस के सिपाहियों के पद रहे हों, वह कुछ विशेष लोगों के लिये अघोषित रूप से आरक्षित थे और मुझे पूरी आशा है कि अब जो नई भर्तियां होंगी उसमें सबको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय वृद्धि हेतु संकर शाक–भाजी उत्पादन हेतु सरकार ने 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न फसलों में अनुसंधान हेतु सेन्टर आफ एक्सिलेंस की भी व्यवस्था की गयी है, यह भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के लिये जहां लोग डीजल या बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाते थे इसलिये सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पम्प की व्यवस्था की गयी है और इससे लोगों के ट्यूबवेल सस्ते दाम पर चल रहे हैं। इसमें एक बार ही पैसा लगता है फिर पैसा नहीं लगता, क्योंकि वह सौर ऊर्जा से चलते हैं। यह भी हमारी सरकार ने किया है। दूसरा अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल जो विकास खण्ड हैं उनमें सिंचाई के लिये स्प्रिंकलर की व्यवस्था के लिये सरकार ने 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है इससे हमारा बुन्देलखण्ड निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होगा।

मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 598 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, इससे निश्चित रूप से सड़कों का चौड़ीकरण होगा। गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु एवं सेतु, लघु सेतु बनाने हेतु 451 करोड़ 58 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, इससे निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत भला होगा। जिला मुख्यालय को फोर लेन से जोड़ने हेतु 71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे हमारे सभी जिले फोर लेन से जुड़ जायेंगे। प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं गड्ढा मुक्ति हेतु 3,932 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे 70 प्रतिशत तक सड़कें गड्ढामुक्त हो गयी हैं और शेष सड़कें भी गड्ढामुक्त हो जायेंगी। इसी प्रकार विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल हेतु 300 करोड़ और बुन्देलखण्ड हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, इससे हमारे बुन्देलखण्ड को बहुत लाभ होगा। पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हेतु 300 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है, इससे नगरों में जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं उनको लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नगर हैं उसके लिये 3000 करोड़ और देहातों के लिये 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यदि किसी व्यक्ति का मकान कच्चा है, झोपड़ी है या वह भवनहीन है तो इस संबंध में सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमारी केन्द्र सरकार ने की है। उसी का जो अंश है राज्यांश, उसको रखा गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पहले 2011 की एक सूची होती थी उसको गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की सूची कहते थे, उस सूची में बहुत कम नाम होते थे और तमाम लोग जो गरीब हैं वह छूट जाते थे। प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है कि यदि वह गरीब है तो वह चाहे सूची के अन्दर है या सूची के बाहर है अधिकारियों के द्वारा उसका परीक्षण किया जायेगा और उसको भी सम्मिलित किया जायेगा। सरकार का यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है, इससे वह

तमाम लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की सूची में आने से छूट गये थे वह भी इसमें सम्मिलित कर लिये जायेंगे।

इसी प्रकार से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहां अन्ना पशुओं की बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने बताया कि 13 साल में 09 साल सूखा रहा है, तमाम लोगों के पास खिलाने के लिये भूसा नहीं था इसलिये तमाम जानवर अन्ना छोड़ दिये गये हैं जिसमें गोवंश अधिक है। अभी सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिये आश्रय स्थल बनाने की घोषणा की है, यद्यपि उसमें धनराशि तो बहुत ज्यादा घोषित नहीं की गयी है, लेकिन जब उसकी शुरुआत हो जायेगी तो बुन्देलखण्ड को इस समस्या से बड़ा निदान मिलेगा और जानवरों द्वारा किसानों की जो फसलें चर ली जाती थीं वह बचेंगी। बेसहारा पशुओं के लिये आश्रय स्थल बनाने का सरकार ने जो एक नया निर्णय लिया है उसके लिये मैं सरकार की सराहना करता हूं। एक नई फेरी नीति के तहत जो बहुत गरीब हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, सब्जी बेचते हैं, सिर पर रख कर बेचते हैं और सड़कों पर बैठे रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उनकी भलाई के लिये भी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इसी प्रकार से झील संरक्षण के लिये भी, तालाब और पोखरों के संरक्षण के लिये सरकार ने 70 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त 'पर ड्राप मोर क्राप' के तहत 113 करोड़ 67 लाख रुपये का प्राविधान सरकार ने किया है, इसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इससे हमारे बुन्देलखण्ड में स्प्रिंकलर की व्यवस्था होगी और पानी भी बचेगा, क्योंकि पानी की वहां बहुत कमी है। एक सबसे बड़ी बात कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर, 2018 तक प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त कर देंगे उसके लिए 3253 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने बजट की जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं बजट की सराहना करता हूं। धन्यवाद।

'हाजी इकराम कुरैशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी विधान सभा और मुरादाबाद जिले से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरे रमजान भर मलिन बस्तियों में बिजली वाले और पुलिस वाले रात में तीन और साढ़े तीन बजे चेकिंग करने के लिए मकानों में घुसते रहे। इस तरह की जब से सरकार बनी है यह चल रहा है मुरादाबाद जिले में। दूसरी बात, घर में अगर कोई हांडी पका रहा है तो जो डायल–100 बहुत अच्छे से काम करती थी, सरकार बदलने के बाद उस डायल–100 का काम अब यह रह गया है कि सिर्फ किसके मकान में क्या पक रहा है वह देखा जाये। हांडी समेत उसको उठाकर ले जाया जाता है और जब किसी थानाध्यक्ष से बात की जाती है तो थानाध्यक्ष कहते हैं कि डायल–100 का ताल्लुक लखनऊ से है। डायल–100 वालों ने बिल्कुल लूट मचा रखी है। गरीबों को क्या खाना खाने की भी इजाजत नहीं है। यह देखा जा रहा है कि उनके घर में क्या बन रहा है। डायल–100 बहुत से मकानों में जाती है जहां सादी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब्जी पकी भी होती है लेकिन अपमान तो उसका भी होता है। बिल्कुल गरीब की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिजली वाले रात को साढ़े तीन बजे मलिन बस्तियों में चेकिंग के नाम पर घुस जाते हैं और उसके बाद वहां वसूली होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक अपनी शिकायत है। मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हूं और पहली बार मैं चुनाव जीत कर विधान सभा में आया हूं। पिछली बार मुझे आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष बनाकर दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था और मैं गोमती नगर विभूति खण्ड आवास में मकान नम्बर–18 में रहता था।

(सत्तापक्ष के विधायकों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह पहली बार के विधायक हैं इन्हें अपनी बात रख लेने दीजिये। वैसे यह हमसे अलग से मिलकर भी बता सकते हैं।

हाजी इकराम कुरैशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी भी एक पीड़ा रख लेने दीजिये। उसी कालोनी में अभी भी और सारे विधायक रह रहे हैं लेकिन मुझे वहां से हटा दिया गया। मुझे जो मकान दिया गया है उसमें जो दो लैट्रीन हैं उसका मेरे कमरे में से होकर रास्ता है। मेरे यहां मेहमानदारी रहती है और मैं रात भर जागता हूं। जो मकान मुझे दिया गया है वह ऐसा है। हम भी अगर उसी कोठी में रह लेते तो हमें भी एहसास होता कि हम भी विधायक हैं। हमसे जबरन वह मकान खाली कराया गया और सारे विधायक और एम0एल0सी0 उसी कालोनी में हैं। एक तरफ तो सरकार नारा दे रही है कि सबका साथ, सबका विकास। मैं एक पिछड़ी बिरादरी से जीतकर आया हूं, पिछड़ी जाति से जीत कर आया हूं। मुझे एहसास होता है कि मुझसे वह मकान सिर्फ इसलिये खाली करा लिया गया क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से जीतकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष–

राम गोविन्द चौधरी जी के पास बढ़िया मकान है, यह भी सपा से जीतकर आये हैं, कभी आप इनके घर गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, वह हमारा मकान नहीं है, मैं भी उधारी में हूं।

हाजी इकराम कुरैशी–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारें बनती रहती हैं, लेकिन इतना पक्षपात नहीं होना चाहिये जो मेरे साथ हुआ है। मैं उस मकान को बिल्कुल खाली करके कहीं सड़क पर चला जाऊंगा क्योंकि उसमें मैं सो ही नहीं पा रहा हूं। नींद की गोली तो दे दी आप लोगों ने भई, कोई बात नहीं लेकिन पांच साल ज्यादा नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह जो बजट सरकार लाई है इसका आप विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे है।

श्री इकराम कुरैशी–

मान्यवर, बजट का जहां तक सवाल है जितना हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं यह बजट जनहित में नहीं है, यह जनता के विरोध में है। जहां पिछली सरकारें बहुत लंबे–लम्बे बजट पेश कर चुकी हैं। अब उसके बाद आपने जो अद्धा–पौना बजट पेश किया है, उससे न हम खुश हैं और न ही जनता खुश है।

'**श्री ज्ञान तिवारी**–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वित्त मंत्री जी के बजट में बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जनपद सीतापुर से पहली बार एक विधायक के रूप में इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। सबका ध्यान दिया गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, अन्त्योदय गांव, गरीब किसान, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दबे–कुचलों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध जिसमें त्रेता युग और द्वापर युग का भी विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ जनपद सीतापुर वहां सतयुग का तीर्थ नैमिषारण है, अट्ठासी हजार ऋषि मुनियों की तपस्थली है, महार्षि दधीचि की माटी है। श्रीमन्, आपसे आग्रह है जिस तरह से मथुरा, अयोध्या को रखा गया है बजट में जिसको अलग से निर्धारित किया गया है उसी तरह से नैमिषारण्य के लिए भी रखा जाए आपकी महान कृपा होगी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन से इस पर समर्थन चाहूँगा चूंकि सतयुग से युगों की शुरुआत हुई है और आप भी वेद पुराण लिखते रहते हैं और सारे वेद पुराण नैमिषारण्य के लिखे हुए हैं व्यास गद्दी भी है उसके लिए भी अलग से कुछ व्यवस्था रहे और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे ऐसा पूरे सदन से आग्रह है, मेरा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं जिस विधान सभा से विधायक चुना गया हूँ वह विधान सभा तीन नदियों के बीच में है और उस विधान सभा में आज तक आजादी के सत्तर साल हो चुके हैं लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। उन तीन नदियों में आज भी बाढ़ की स्थिति है और इस बाढ़ की स्थिति में मा0 अध्यक्ष जी, गांव के बीच में जो पुल बने थे वह टूट गये हैं। मैंने जिलाधिकारी से और अपने सिंचाई मंत्री से बात किया है और नाव की व्यवस्था हो गयी है जिससे लोग आ रहे हैं। उसमें पुलों की भी व्यवस्था हो जाए। श्रीमन्, हमने पांच पुलों की व्यवस्था को लिखकर दिया है अगर वह बन जाएंगे तो हर गांव को मुख्यालय से या जो हमारे मुख्य ब्लॉक क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा सके। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अन्दर एक भी टाऊन एरिया नहीं है और एक भी नगरपालिका नहीं है। मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि एक आपके यहां जरूर बनेगी इसका भी मान्यवर ध्यान रखा जाए क्योंकि मेरे यहां जो तीन नदियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जाल है वहां भीषण बाढ़ चल रही है। इस बाढ़ की स्थिति में नब्बे किलोमीटर में जो मेरी विधान सभा है वहां घाघरा और सरयू नदी के किनारे–किनारे नब्बे किलोमीटर सीमा है। इस नब्बे किलोमीटर सीमा के अंतर्गत तेरह गांव जो नदी के अन्दर समाहित हो चुके हैं और जिन गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है वह सिर्फ कागजों पर रह गये हैं। बहराइच जिले की सीमा को छोड़कर सात किलोमीटर सीतापुर सीमा के अंदर नदी आ गयी है और कटान भी है। इसको हमारे मुख्य मंत्री जी ने तत्काल बचाने की व्यवस्था की है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि यह किया होता तो सात किलोमीटर नदी वह नहीं आती। श्रीमन्, मेरा यह भी इस सदन से आग्रह है कि इसको भी प्राथमिकता के आधार पर स्थाई रूप से बोल्डर द्वारा तटबंध बनाया जाए ताकि हमारे जनपद के और बच सकें। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई अग्निशमन केंद्र नहीं है। अगर आग लगती है तो या तो बिसवां या महमूदाबाद या लहरपुर से गाड़ी आग बुझाने के लिए जाती है। वहां पहुंचने में लगभग एक घण्टा लग जाता है और एक घण्टे के अंदर सारा का सारा गांव जलकर राख हो जाता है। यह घटनायें निरंतर होती हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि मैंने उनसे आग्रह किया था उन्होंने स्वीकृति तो दे दी लेकिन उसका धन भी स्वीकृत होकर यह काम भी जल्दी चालू हो जाएगा तो मैं इस सदन का आभारी रहूंगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में लगभग पांच हजार ऐसे लोग हैं जो गांव नदी में समाहित हो गये हैं और उस नदी में समाहित होने के बाद आज भी वह सड़कों के किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। अगर उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबको मकान मिल रहे हैं लेकिन जो मकान मिल रहे हैं हर गांव के हिसाब से मिल रहे हैं। लेकिन बाढ़ की कटान में जो गांव गये हैं समाहित हो चुके हैं जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं उनके लिए अगर अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी उनको अगर प्राथमिकता के आधार पर पहले अगर पुनर्वास मिल जायेगा तो मैं इस सदन का आभारी रहूंगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में इतनी दिक्कते हैं। मेरा आग्रह है कि जो वहां गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं वह लोग भी मुख्य धारा से जुड़ जायें। जो तीन–तीन नदियां हैं, बाढ़ आती है तो जो थोड़ा–बहुत सड़कें हैं वह भी कट जाती हैं इस कारण से सुचारु रूप से आवागमन बाधित रहता है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार अगर हमारी विधान सभा क्षेत्र में थोड़ा और ध्यान दे देगी तो और अच्छा होगा। इस आग्रह के साथ मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा श्री तेजपाल सिंह, श्री नन्द किशोर गुर्जर, श्री राजीव तरारा एवं श्री बजरंग बहादुर जी का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे।)

'**श्री मोहम्मद रिजवान–**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और यह बजट जैसा हमारे नेता मा0 श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने सब कुछ बजट के बारे में कहा है कि जिस तरह से सारे विभागों में बजट में कटौती की गयी है इस कटौती के चलते किस तरह वह योजनायें पूरी होंगी। किस तरह से प्रदेश का विकास होगा। हर विभाग में आपने कटौती की है। बजट में जो 36 हजार करोड़ रुपये किसानों के कर्ज माफी की बात की गयी है यह सारे विभागों के बजट की कांट–छांट करके यह छलावे का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में न तो कहीं किसी पेंशन का कोई नाम है न कोई नये उद्योगों का प्राविधान है। जहां तक बिजली के ऊपर उधर से हमारे बहुत से साथी बोल रहे थे। जितनी हालत बिजली की खराब है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में रतनपुरकला में एक विद्युत उपकेंद्र है वहां पर पांच एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। 20–25 गांवों में न धान लग पा रहा है न गन्ने के लिए किसी तरह की पानी की व्यवस्था हो पा रही है। जब तक वहां दस एम्पियर का ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक वह फीडर नहीं चल पायेगा। जिस तरह से जो सरकार है उसने यह नारे दिये कि यहां कब्रिस्तान की चहारदीवारी हुयी, अन्त्येष्टि स्थल नहीं बने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 करोड़ रुपये के हमारे पंचायत विभाग की तरफ से अन्त्येष्टि स्थल बनाये गए और 200 करोड़ रुपया नगर विकास मंत्री, मा0 आजम खां साहब ने देने का काम किया, जिसका प्रमाण है, आप जांच करा लीजिए, मेरे क्षेत्र की। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक नगर पंचायत है, कुंदरकी, उसके अन्दर 05 अन्त्येष्टि स्थल बने हैं, उनकी लागत 85–85 लाख रुपया है, एक–एक अन्त्येष्टि स्थल की है, साढ़े चार करोड़ के अन्त्येष्टि स्थल बने हुए हैं और 27 अन्त्येष्टि स्थल मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बने हैं। मैं एक–एक गांव का प्रमाण दे सकता हूं जिस तरह से यह लोग गुमराह करने की बात करते हैं, जब 100 करोड़ का बजट अन्त्येष्टि स्थल के लिए दिया गया है और 200 करोड़ रूपये का बजट नगर विकास मंत्रालय की तरफ से अन्त्येष्टि स्थल के लिए दिया गया है तो यह जो गुमराह करने की बात करते हैं, यह बजट फिर कहां चला गया ? यह सारा काम हुआ है, क्षेत्र के अन्दर, अन्त्येष्टि स्थल बने हैं, अगर कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनी है तो अन्त्येष्टि स्थल बनाने का भी काम हुआ है। जहां तक इन्होंने खनन में पाबंदी लगायी है। खनन की पाबन्दी के कारण न तो कोई सरकारी काम हो पा रहा है, न मिट्टी किसान डाल पा रहा है, अपना भवन बनाने के लिए भी, अपना छोटा मकान बनाने के लिए भी न उसको गिट्टी मिल रही है, न उसको बालू मिल रही है, न उसको बजरी मिल रही है और दोगुने, तीन गुने दाम पर उस छोटे से मकान को बनाने में लागत आ रही है और जहां तक हमारी सरकार में जो लोहिया आवास 3 लाख 20 हजार का था, उसको घटाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाने का इन्होंने ठेका लिया है कि वह 01 लाख 20 हजार रुपये में बन जायेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 01 लाख 20 हजार रुपये में उसका पटान भी नहीं हो पायेगा, कहां से उसका मकान बन जायेगा ? उस मकान में न तो कोई बिजली की व्यवस्था की जा रही है, केवल गुमराह किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जहां तक गुण्डे–माफियाओं की बात चल रही है, मैं

आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, इस बात का नोट कर लें, सरकार यहां पर बैठी है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

यह बुजुर्ग कहने में नाराज होते हैं।

श्री मोहम्मद रिजवान–

अध्यक्ष जी, सप्लाई में जितनी बड़ी धांधली है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को जरूर नोट कर लें और मेरे क्षेत्र की जांच करा लें। 62 राशन की दुकानें निलम्बित की गयी हैं और केवल गुण्डई के बल पर उनका अटैचमेंट बराबर की दुकानों से कराया गया है, अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा और अभी सदन से चला जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 62 दुकानें निलम्बित की गयी हैं और उन दुकानों से अटैचमेंट लगाकर पूरी वसूली की जा रही है, क्षेत्र में त्राहि–त्राहि मची हुई है और कोई राशन बंटने का नाम नहीं ले रहा है। जो पट्टाधारी मुझसे चुनाव हारा है, उसने पूरी तरह गुण्डई कर रखी है और पूरे क्षेत्र के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसी तरह से ग्राम प्रधानों को उनकी जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। तो यह तो क्षेत्र की बात रही और मान्यवर, एक और बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मेरे खिलाफ शिकायत है कि मैं भूमाफिया हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, एक गुमनाम एप्लीकेशन दी गयी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को और उसमें कोई नाम नहीं लिखा है। उसमें लिखा गया है कि 50 साल पहले विधायक ने, मान्यवर, 50 साल पहले मेरी कितनी उम्र होगी, जब मैं जमीनों पर कब्जा कर रहा था, 10–12 साल का रहा होऊंगा। जिलाधिकारी की जांच का यह लेटर मैं आपको दूंगा। 50 साल पहले की बात लिखी है कि विधायक और विधायक के परिवार वालों ने एक जमीन का बैनामा कराया था, जबकि मैंने कोई बैनामा नहीं कराया है, मेरे बुजुर्गों ने कोई बैनामा नहीं कराया। यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का लेटर है, यह मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप उसे संसदीय कार्य मंत्री जी को दे देना, कार्रवाई हो जायेगी।

श्री मोहम्मद रिजवान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो पी0एच0सी0 बनी है, सी0एच0सी0 बनी है पिछली सरकार में, मेरे क्षेत्र के अन्दर 04 सी0एच0सी0 बनी, 02 पी0एच0सी0 बनी, 03 इण्टर कालेज बने, 01 आई0टी0आई0 बनी उसमें मैं स्टाफ की मांग करता हूं कि वहां पर स्टाफ को भेजा जाय और इसको मैंने लिख कर भी दिया है। तीसरी बात यह है कि 01 आई0टी0आई0 बनी है, उसमें भी स्टाफ की व्यवस्था की जाय। जहां तक बजट की बात है, यह बजट बिल्कुल छलावे का बजट है, बजट में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यह सच्चाई है और मा0 नेता जी ने बहुत कुछ कह दिया, तमाम योजनाओं को काट–छांट कर के और उसके बाद में ऐसा बजट पेश किया गया है

कि ये तमाम हमारे प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से कितना विकास यह करायेंगे। जिस तरह गड्ढे मुक्त करने की बात इन्होंने कही थी और मा0 हमारे सिंचाई मंत्री जी वहां पर कल बोल रहे थे कि हमने ग्यारह सौ तालाब भरने का काम किया है, जिस तरह से इन्होंने गड्ढे भरने का काम किया है, उसी तरह से इन्होंने तालाब भरने का काम किया है, सब फर्जी मामला, यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इतना झूठ यह बोलते हैं कि किसी दिन यह बिल्डिंग नीचे न आ जाय, सच्चाई यह है, कौन सा तालाब उन्होंने भर दिया, अभी पूर्वान्चल में थोड़ी बारिश हो गई है तो तालाब शायद भर गये हों, लेकिन गड्ढा कहीं पूरे प्रदेश में कहीं नही भरा गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जब ठेकेदार ठेका ही नहीं ले रहे हैं, जब उन्हें गिट्टी और बजरी नहीं मिल रही है, तारकोल नहीं मिल रहा है तो गड्ढे कहां से भरे जा रहे हैं, इसलिए यह सब छलावा है, झूठ है और गुमराह करने का काम किया गया है और बजट कोई लोकप्रिय बजट नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, मा0 आध्यक्ष जी, आपने बजट के विरोध में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आज मैं उधर बैठा था जहां लाबी है और हमारे कुछ मा0 सदस्य वहां धूम्रपान करते हैं और सिगरेट का धुंआ और गन्ध भीतर तक आती है, तो वहां पर बैठने में काफी परेशानी होती है, जिससे मुझे वहां से उठ कर यहां आना पड़ा, तो इसको दिखवा लें इसको रोका जाय और इसकी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रीमती नीलम करवरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी को उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वाले बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, बाढ़ नियंत्रण हेतु 647 करोड़, माध्यमिक शिक्षा हेतु 551 करोड़, सोलर पम्प योजना हेतु 128 करोड़, विद्यार्थियों को यूनिफार्म हेतु 123 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजना हेतु 2800 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान हेतु 19444 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना हेतु 1800 करोड़, मेट्रो रेलवे हेतु 280 करोड़ की व्यवस्था कर प्रदेश को सर्वांगीण विकास बनाने में पहला कदम बढ़ाया गया है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मेट्रो रेल योजना में सम्भवतः मिस प्रिन्ट के कारण इलाहाबाद का नाम छूट गया है, इसे जोड़ करके प्रयाग का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और विश्वास कर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कार्य किया है। शासन की नीति, सबका साथ सबका विकास के पथ पर मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यों का क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए संकल्पित होकर हमने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है, किन्तु पूर्ववर्ती सरकारों ने झूठा आश्वासन देकर जनता का वोट प्राप्त कर सरकारें तो बनाई थीं, लेकिन जनहित के कार्य करने में असफल रहे और समाज को जातिवाद की दिशा में

ढकेलने का कार्य किया। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस पर रोक लगाने तथा समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का दृढ़संकल्प लिया है, जो इस वर्ष के बजट से स्पष्ट हो जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले, समाज की कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक योजनायें पहुंचें इस संकल्प के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, वह अनुसूचित वर्ग में जन्मा हुआ व्यक्ति हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का हो सकता है तथा सामान्य जातियों में उसका जन्म हो सकता है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग की तरह सामान्य जाति के गरीब व्यक्ति को भी जीने का अधिकार, उसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, आवास तथा समान अधिकार प्राप्त हों, इसकी आज आवश्यकता है तथा हमारी सरकार इसके लिए संकल्पित है। मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं इसके लिए बधाई देती हूं। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था हमें विरासत में पूर्व की सरकारों से मिली है किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी के अथक प्रयास से सुधार हुआ है। किन्तु अभी भी जिले और प्रदेश में बैठे कुछ अधिकारी अपनी सोच और मानसिकता को नहीं बदल पाए हैं।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर बोलिए और समाप्त करिए।

श्रीमती नीलम करवरिया–

इस दिशा में अभी और ठोस कदम उठाने तथा जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के कार्य–कलापों के विषय में रिपोर्टिंग पर कार्यवाही हो तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते हैं क्योंकि प्रदेश में या जिले में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी की गलत–सही रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों की बात को तो जैसे न मानने की आदत सी पड़ गई है। इस दिशा में सरकार को और विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे महसूस होता है शायद मा0 सदस्यों को भी महसूस होता होगा। भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारियों पर अंकुश, किसानों की कर्जमाफी, एण्टी रोमियो टास्क फोर्स का गठन, अवैध बूचड़खानों को बन्द करना, विद्युत की व्यवस्था को ठीक करना, गड्ढा मुक्त सड़क योजना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की योजना, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु उठाए गए कदमों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा किए जा रहे प्रयास, उनकी जनता के प्रति संवेदनशीलता को जाहिर करती है। मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई तथा ह्रदय से धन्यवाद देती हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के, नहरों के, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर निवास करने के कड़े निर्देश जारी करें और उन्हें वहां उपस्थित रहने के लिए अगर कहा जाए तो शायद जन समस्याओं के निस्तारण को और गति प्राप्त होगी और हम जन अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस दिशा में भी मा0 मुख्य मंत्री जी तथा सभी विभागीय मंत्रीगण ध्यान देंगे तथा जनता की शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा। जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार वादे नहीं, इरादे लेकर प्रदेश में बनी है और इस दिशा में शुरुआत इस बजट में प्रारम्भ हो गई है। नहरों की टेल तक पानी, घर को बिजली, सभी को पक्की छत, बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में आज यह

पहला कदम हमने बढ़ाया है और मा0 मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा इसके लिए हम कृतसंकल्पित हैं। मैं हर प्रकार से सभी क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2017–2018 में किए जाने वाले कार्यों को विस्तृत रूप से रखने के लिए बधाई देती हूं और अपनी बात यह कहकर समाप्त करती हूं कि सरकार के इरादे नेक हैं किन्तु सहयोग सभी का आवश्यक है। एक नई रोशनी, एक नई दिशा और मजबूत इरादा मा0 मुख्य मंत्री जी का है। हम सब इसमें सहयोग करें और अपने–अपने योगदान का स्वतः आंकलन करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

[6.01, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा 01 अरब 16 करोड़ के घोटाले की जांच सी0ए0जी0/टी0ए0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्याऊ के ग्राम चितरी एवं सिमरिया देदूखाम में बाढ़ के खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में गजरौला में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर में किसान गंगा सहकारी चीनी मिल, मोरना की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास की सई नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तथा तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत भेलसर रुदौली उमापुर मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती में बाढ़ की भीषण समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है, तथा दूसरी सूचना श्री रामअचल राजभर की लोक सेवा आयोग द्वारा उ0 प्र0 सचिवालय के अपर निजी सचिव के पद का परिणाम घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :–

श्रीमती कृष्णा पासवान,

श्री सोवरन सिंह यादव,

श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस,
श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
श्री प्रमोद उटवाल,
श्री जगन प्रसाद गर्ग,
श्री संजय गर्ग,
श्री आजाद अरिमर्दन,
श्री उज्जवल रमण सिंह,
श्री रितेश पाण्डेय,
श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू,
इंजी0 बृजेश कठेरिया,
श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव,
श्री वीरेन्द्र कुमार यादव,
श्री रत्नाकर मिश्र,
श्री ओंकार सिंह,
श्रीमती साधना सिंह,
श्री अमिताभ बाजपेई,
श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
श्री अमन मणि त्रिपाठी,
श्री असलम अली,
श्री संजय प्रताप जायसवाल,
श्री तसलीम अहमद,
श्रीमती लीना तिवारी,
श्री उमाशंकर सिंह,
श्री नरेश सैनी,
डा0 आर0 के0 वर्मा,
श्री अजय कुमार लल्लू,
श्री महेश कुमार गोयल,
श्री बाबा गोरखनाथ,
श्रीमती जय देवी,
श्री प्रभुनारायण सिंह यादव,
श्री अनिल सिंह,
श्री कैलाश नाथ शुक्ल तथा

श्री सुखदेव राजभर।

जनपद उन्नाव सदर में नगर निगम का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

हमारे विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका परिषद्, उन्नाव व नगर पालिका.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्के अन्तर्गत दिनांक 17–05–2017 को निम्नवत् सूचना दी गयी है :–

''हमारे विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका परिषद्, उन्नाव व नगर पालिका परिषद्, गंगा घाट है, यह दोनों नगर पालिका परिषद् उन्नाव–कानपुर रोड पर स्थित हैं, लगातार क्षेत्रीय जनता द्वारा इन दोनों नगर पालिका परिषदों व इस रोड के समीपस्थ गांवों को मिलाकर नगर निगम गठन किये जाने की मांग की जाती रही है। इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा मुख्य मंत्री जी से भी 21 अप्रैल, 2017 को अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम का गठन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन को ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।''

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु मानकों के निर्धारण सम्बन्धी नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–2212/नौ–6–14–181मिस/2014, दिनांक 10–11–2014 द्वारा तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की जनसंख्या 1 से 1.50 लाख, द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका की जनसंख्या 2 लाख तक तथा प्रथम श्रेणी की नगर पालिका की जनसंख्या 5 लाख तक निर्धारित की गयी है।

प्रकरण में नगर पालिका परिषद् उन्नाव की जनसंख्या 1 लाख 77 हजार 658 तथा नगर पालिका परिषद् गंगा घाट की जनसंख्या 84 हजार 72 अर्थात् दोनों नगर पालिका परिषदों को मिलाकर कुल जनसंख्या 2 लाख 61 हजार 730 है। इस प्रकार दोनों नगर पालिका परिषदों की जनसंख्या सम्मिलित करने के पश्चात् भी प्रथम श्रेणी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका परिषद् हेतु निर्धारित अधिकतम जनसंख्या 5 लाख से काफी कम है। अतः वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नगर निगम, उन्नाव का गठन औचित्यपूर्ण नहीं है।,

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय लालगंज अझारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत 50 बेड के मैटरनिटी विंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना 'मिश्रा' मोना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्में मेटरनिटी विंग के निर्माण की स्वीकृति एन0एच0एम0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/निर्माण–34/2016–17, दिनांक 16–09–2016 द्वारा राजकीय निर्माण निगम को आवंटित किया गया तथा राजकीय निर्माण निगम द्वारा तैयार किये गये आगणन पर पी0एफ0ए0डी0 के अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ निर्माण/75(वित्तीय स्वीकृति)/2016–17/1058–10, दिनांक 22–02–2017 द्वारा लागत रु0 603.73 लाख सर्विस चार्ज रु0 29.75 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा दिनांक 24–02–2017 को अनुबन्ध चिकित्सा विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के माध्यम से सम्पादित किया गया। पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/निर्माण–47/2017–18/17, दिनांक 04–04–2017 द्वारा धनराशि रु0 300.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा निविदा की कार्यवाही नहीं की जा सकी। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा निविदा का प्रकाशन दिनांक 25–03–2017 को किया गया था, परन्तु सभी निर्माण कार्यों की निविदा ई–निविदा के माध्यम से कराये जाने के निर्देशों के क्रम में उक्त निविदा दिनांक 26–04–2017 को निरस्त कर दी गयी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/निर्माण–121/ 2017–18/ 23272, दिनांक 16–06–2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जिन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां निर्माण कार्य अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाये। तद्नुसार निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जा रही है।,

जनपद अम्बेडकरनगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जनपद अम्बेडकरनगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर मार्ग.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्के अन्तर्गत दिनांक–17–05–2017 को दी गयी सूचना में निम्न तथ्य शासन के संज्ञान में लाते हुए सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है :–

''जनपद अम्बेडकरनगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर मार्ग अति महत्वपूर्ण मार्ग हैं। उक्त मार्ग मया टाण्डा मार्ग को अकबरपुर–फैजाबाद मार्ग को जोड़ता है। आवागमन अत्यधिक है। परन्तु उक्त मार्ग केवल 03 मी0 चौड़ाई का बना है जिसके कारण आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन दुर्घटना होती रहती है जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हैं। स्थिति विस्फोटक है।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर, उक्त मार्ग को 07 मी0 चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स से बनाये जाने की मांग करते हुए शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री लालजी वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक–17–05–2017 के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी–405/अड़तीस–9–17–07(नियम)/2017, दिनांक–21–06–2017 द्वारा मा0 सदस्य को यह अवगत कराया जा चुका है कि जनपद अम्बेडकरनगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर तक के मार्ग की कुल लम्बाई 18.05 कि0मी0 है। मार्ग की कुल लम्बाई पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन फेज–10, विश्व बैंक पोषित (आर0आर0पी0–2) के अन्तर्गत उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) का कार्य कराया गया है। मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.30 मीटर है। मार्ग का पूर्ण संरेखण अवधि के अन्तर्गत है, जो दिनांक–11–06–2017 को समाप्त होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण संरेखण का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुबन्धित अवधि से आच्छादित होने के कारण पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन के अनुसार इसका चौड़ीकरण 7.00 मीटर तक किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इल्तिफातगंज से अबकरपुर मार्ग वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है एवं पूरी तरह से गड्ढामुक्त है। यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–1 के अन्तर्गत बनाया गया था। तत्पश्चात् अगस्त, 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 की गाइडलाइन्स जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत मार्गों के उच्चीकरण के कार्य अनुमन्य हैं। पीएमजीएसवाई–2 की गाइडलाइन्स के प्रस्तर–5.8 के अनुसार नियमानुसार थ्रू रूट्स/मेजर रूरल लिंक रूट्स पर केवल 5.5 मीटर तक चौड़ाई में उच्चीकरण का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति से किये जाने की व्यवस्था है।

अतः वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रश्नगत मार्ग इल्तिफातगंज से अबकरपुर का निर्माण 07 मीटर चौड़ाई में कराया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद सीतापुर में राशन कार्ड बनाने में हुई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह मद स्थगित है।

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद उटवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

श्री प्रमोद उटवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्के अन्तर्गत दिनांक 17–05–2017 को यह सूचना दी गयी थी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र पुरकाजी की आबादी लगभग 40 हजार है। जहां के छात्र 12वीं की कक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

पास करने के बाद डिग्री कालेज में प्रवेश लेने हेतु लगभग 25 किमी0 दूर मुजफ्फरनगर या 30 किमी0 दूर उत्तराखण्ड के रूड़की जाना पड़ता है या 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिससे वह गलत संगत में पड़ कर अपराधी भी बन जाते हैं। अतः शिक्षा के प्रसार एवं छात्रों के भविष्य हेतु मा0 सदस्य द्वारा कस्बा पुरकाजी में एक सरकारी डिग्री कालेज खोले जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मुजफ्फरनगर में 05 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 47 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। विकास खण्ड पुरकाजी के निकटस्थ लगभग 13 किमी0 की दूरी पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 01 वीतराग स्वामी कल्याण देव डिग्री कालेज बरला, मुजफ्फरनगर संचालित है।

नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना पर वृहद् वित्तीय भार एवं उपर्युक्त के दृष्टिगत वर्तमान में मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना विचाराधीन नहीं है।,

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं सुश्री अदिति सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

सर्वश्री अजय कुमार लल्लू, मसूद अख्तर, नरेश सैनी आदि मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 19–05–2017.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि ''प्रदेश में ज्वैलर्स व्यवसायियों पर बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ लगातार हो रहे हमले, उनसे हो रही लूट से कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है। हाल ही में वाराणसी, गोरखपुर एवं मथुरा में हुए लूट से ज्वैलर्स व्यवसायियों में सरकार के प्रति रोष व आक्रोश व्याप्त है। पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर तनिष्क लूट काण्ड, नोएडा में हुए काण्ड तथा लखनऊ समेत पूर्वांचल में बार–बार हो रही घटना से तंग आकर उन्होंने आज प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान करते हुए लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा सर्राफा कारोबारी दुकान एवं शोरूम बन्द रखने का एलान किये हैं। इसी के साथ ही उन्होंने दिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में सत्ताधारी पार्टी कार्यालय का घेराव करने तथा जी0पी0ओ0 पर प्रदर्शन करने का एलान किया है। मथुरा के होलीगेट पर कोयला वाली गली में 4 सर्राफा व्यापारियों को गोली मारने तथा करोड़ों की ज्वैलरी लूट में अभी तक पुलिस द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका है। इस घटना में मारे गये सर्राफा मेघ अग्रवाल के परिवारीजन मथुरा में धरने पर बैठे हैं। डी0जी0पी0 एवं सरकार के मंत्री के सामने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है। कल ही राजधानी लखनऊ के विभूति खण्ड में एक स्टैण्ड संचालक भानु प्रताप सिंह को बदमाशों ने फ्लाई ओवर पर दौड़ाकर गोली मार दी किन्तु सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को निलम्बित कर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रदेश की जनता में सरकार से प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। वह कभी भी सरकार विरोधी कदम उठाने को विवश हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार उल्लिखित घटनाओं के सम्बन्ध में संक्षेप में स्थिति निम्नवत् हैः–

1. वाराणसी

दिनांक 08–04–2017 समय 04 बजे अपराह्न थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत सीताराम सर्राफ की दुकान में 07 अपराधियों द्वारा घुसकर पिस्तौल व चाकू से कवर करके तथा सीसीटीवी व टेलीफोन तोड़कर तिजोरी से लगभग 12 किलो सोने के जेवरात (कीमत लगभग 03.06 करोड़ रु0) व 03 अदद मोबाइल फोन लूट लिया गया। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल द्वारा समय 05.35 बजे सायंकाल थाना चौक, वाराणसी में दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0–97/17 अन्तर्गत धारा–395/397/412/120बी भादवि पंजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचना के दौरान 12 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिसमें से 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 03 अभियुक्त हाजिर अदालत हुए। गिरफ्तार एवं हाजिर अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके कब्जे से रु0 34.00 लाख मूल्य के जेवरात बरामद किए गये।

2. गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में वर्तमान में ज्वैलर्स/सर्राफा व्यवसायी से कोई लूट की घटना घटित नहीं हुई है। दिनांक 11–05–2017 को थाना कोतवाली अन्तर्गत दीवान बाजार में चन्द्र प्रकाश टिवरेवाल पुत्र बाबूलाल टिवरेवाल निवासी हेमन्त अपार्टमेंट, दीवान बाजार को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार दी गयी थी तथा चन्द्र प्रकाश टिवरेवाल के पास से बैग छीन कर भाग गये। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली गोरखपुर में दिनांक 11–05–2017 को मु0अ0सं0–102/2017 धारा–394/302 भादवि विरुद्ध अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से 04 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिसमें अभियुक्त जीशान उर्फ ईशान पुत्र इरसाद को दिनांक 20–05–2017 को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास

से लूटी गयी रकम से 3.75 लाख रु0 एवं घटना में प्रयुक्त पिस्टल मय कारतूस व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त रियाज हुसैन को दिनांक 03–06–2017 को गिरफ्तार करके लूट की रकम के 01 लाख रु0 व एक तमंचा, कारतूस सहित बरामद करके जेल भेजा गया। शेष 02 अभियुक्तों के विरुद्ध 82,83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अभियोग की विवेचना की जा रही है।

3.मथुरा

दिनांक 15–05–2017 को समय करीब 08.00 बजे सायं थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कोयला वाली गली होली गेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा क्षेत्रान्तर्गत मयंक चैंस नाम सर्राफा की दुकान पर मयंक गोयल विकास गोयल पुत्रगण श्री मोहन लाल अग्रवाल नि0 सिविल लाइन थाना सदरबाजार जनपद मथुरा, मेघ अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल नि0 डैम्पीयर नगर थाना कोतवाली मथुरा कारीगर अशोक साहू पुत्र चरन साहू नि0 घंटाघर देहली गेट जनपद मेरठ एवं मोहम्मद अली पुत्र जमालुद्दीन नि0 पूर्वाह देहली गेट जनपद मेरठ उपस्थित थे, तभी 6–8 अज्ञात युवक जिनमें से कुछ के मुंह पर कपड़ा बंधा था तथा कुछ हेलमेट लगाये थे, और हथियारों के बल पर लूटपाट प्रारम्भ कर दी। दुकान पर उपस्थित उपरोक्त पांचों व्यक्तियों के विरोध करने पर अज्ञात युवकों द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गयी तथा दुकान से सोने एवं चांदी के आभूषण एवं नगदी लूट कर ले गये। जिला अस्पताल में मेघ अग्रवाल उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया, तथा घायलों को नयति हास्पिटल रेफर कर दिया गया। नयति हास्पिटल में दौराने उपचार विकास गोयल की मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में डा0 अशोक अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल नि0 53 सदर बाजार द्वारा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–513/2017 धारा–395,397 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। मृतकों के मीमो प्राप्त होने पर अभियोग में धारा–396, 307 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया।

सी0सी0टी0वी0 फुटेज एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर अभियुक्तों की पहचान सम्भव हो सकी जिसके क्रम में घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान 1. राकेश उर्फ रंगा, 2. नीरज उर्फ आशीष एवं 3. कामेश उर्फ चीनी पुत्रगण स्व0 बालस्वरूप चतुर्वेदी निवासीगण रतनकुण्ड, चैबिया पाडा, थाना कोतवाली, जनपद मथुरा के रूप में हो गयी, जिनके द्वारा अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की जानकारी हुई। इस घटना में अब तक 11 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिनमें से 09 अभियुक्त गिरफ्तार हुए 01 अभियुक्त द्वारा आत्म हत्या कर ली गयी तथा 01 अभियुक्त ने आत्म समर्पण कर दिया। घटना में लगभग 1.50 करोड़ रु0 के जेवरात लूटे गये थे, जिसमें से करीब 1.00 करोड़ रु0 की सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है। मेघ अग्रवाल के पिता श्री महेश अग्रवाल निवासी डैम्पीयर नगर थाना कोतवाली मथुरा के लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर क्लेम करने पर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। विवेचना प्रचलित है। वर्तमान में मेघ अग्रवाल के परिवारीजन धरने पर नहीं बैठे हैं।

4. सहारनपुर

दिनांक 15–02–2015 को थाना क्षेत्र सदर बाजार में तनिष्क ज्वैलर्स के शोरूम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0–68/15 धारा–395,171,120बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्त मुकीम उर्फ काला सहित 15 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिनमें से 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर लूट का माल बरामद किया गया तथा 01 अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की वारण्ट तामील कराया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया, वर्तमान में अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

5. नोएडा

दिनांक 21–09–2015 को श्री अमन वर्मा पुत्र अजय कुमार वर्मा निवासी यमुनापुर थाना कोतवाली, बुलन्दशहर की कार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ओवर टेक कर गाड़ी रुकवाकर करीब 80 किलोग्राम चांदी के जेवरात (कीमत करीब 26.00 लाख रु0) लूट लिये, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0–644/15 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना से 08 अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से 56.300 किलोग्राम चांदी व घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15–11–2015 को आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

6. लखनऊ

दिनांक 29–12–2016 को हनुमान सेतु मन्दिर के पास 03 किलोग्राम सोना लूटकर भागने की घटना पर थाना महानगर पर मु0अ0सं0–13/17 धारा–392 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 12–01–2017 को 05 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके कब्जे से 02 किलोग्राम सोना बरामद किया गया।

दिनांक 05–03–2017 को वादी की सूचना के आधार पर थाना चौक पर मु0अ0सं0–108/17 धारा–395/397 भादवि बनाम 08 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से घटना में संलिप्त 11 अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आये, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनसे 09.160 किलोग्राम ज्वैलरी व एक मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

दिनांक 18–05–2017 को वादी श्री भानुप्रताप सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी सूर्या सिटी तकरोही, इन्दिरानगर द्वारा थाना विभूति खण्ड पर सूचना दी गयी कि पुरानी रंजिश के चलते राजा, अफजल खान, पवन सिंह आदि करीब 10 अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोकते हुए उनसे गाली गलौज करते हुए लाठी डन्डों से हमला कर दिया तथा जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–298/17 धारा–147/148/149/341/307 भादवि बनाम राजा, अफजल व अन्य 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 हाजिर अदालत हुए तथा 01 अभियुक्त के विरुद्ध धारा–82 सीआरपीसी के

अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त परितोष त्रिपाठी की 82 सीआरपीसी की कार्यवाही होने के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र दाखिल किया गया है कि अभियुक्त परितोष त्रिपाठी उक्त घटना में शामिल नहीं था। विवेचना प्रचलित है। लखनऊ की कानून–व्यवस्था पूर्ण रूप से चुस्त एवं दुरुस्त है तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण है।,

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाई व मुफ्त इलाज न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्यगण की सूचना में उल्लिखित है कि जब से उ0प्र0 में भारतीय जनता की सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य सेवा.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्चरमरा सी गयी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रदेश में 7300 डाक्टरों की उ0प्र0 में कमी का जिक्र किया है। हमारी प्रदेश सरकार में उ0प्र0 में गरीबों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाई दी जा रही थी जब से नई सरकार बनी है तब से मरीजों को दवाई व मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। हलात यह है कि सरकारी अस्पतालों में यहां तक की पी0जी0आई0, सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल आदि में भी सरकारी डाक्टरों की मिली–भगत से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है जिस कारण गरीब जनता प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज व महंगी दवाई खरीदने को मजबूर है। सरकार की कोई इच्छा शक्ति गरीब आम जनमानस को लाभ देने की नहीं है।

2– मा0 सदस्यगण द्वारा दी गयी सूचना में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 में पूर्व की भांति ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को निःशुल्क औषधि वितरित की जा रही है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकारी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को निःशुल्क औषधि वितरित किया जा रहा है। पूर्व में लगभग 290 आइटम्स का दर अनुबन्ध था तथा 15–06–2017 के उपरान्त लगभग 200 आइटम्स का और दर अनुबन्ध जारी कर दिया गया तथा वर्तमान समय में मरीजों के उपचार हेतु कुल 487 आइटम्स दर अनुबन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

में उपलब्ध हैं, जिसमें 300 से अधिक औषधियां हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों के इलाज के प्रति सरकार कटिबद्ध है तथा स्वास्थ्य सेवायें बेहतर हुई हैं और जनता निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त कर रही है।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्गया है कि जनपद–फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सरकार के आदेशानुसार जारी विद्युत आपूर्ति रोस्टर तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश है परन्तु पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 10 से 12 घण्टे मात्र हो पा रही है। नगर क्षेत्र रूदौली में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त है विगत दिनों फैजाबाद के दौरे पर पधारे मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा एम0डी0 पावर कारपोरेशन को रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया था। उक्त निर्देश का अनुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण बाबा बाजार बिजली घर, पटरंगा विद्युत केन्द्र व रूदौली विद्युत केन्द्र से चलने वाली राजकीय नलकूप व प्राइवेट नलकूप लघुडाल नहरें सुचारु रूप से नहीं चल पा रही हैं परिणामस्वरूप किसानों की जायद की फसलें सूख रही हैं। ऐहार फीडर व पूरे डलई फीडर की लगभग 80 ग्राम पंचायतों में विद्युत कटौती लगातार की जा रही है। दोनों फीडरों के गांव को सब डिवीजन सोहावल से सम्बद्ध कर दिया गया है, मेरे द्वारा दोनों फीडरों की ग्राम पंचायतों को रूदौली से सम्बद्ध करने के प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी अभी तक विभाग के अधिकारियों द्वारा रूदौली से सम्बद्ध नहीं किया गया है। जिसके कारण किसानों/उपभोक्ताओं को रूदौली व सोहावल का चक्कर लगाना पड़ता है। विभाग के इस व्यवहार के कारण किसानों/उपभोक्ताओं में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

आख्याः–अवगत कराना है कि जनपद–फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 20.00 घण्टे तथा 18.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शेड्यूल है। दिनांक 15–05–2017 से 30–06–2017 तक फीडरवार औसत विद्युत आपूर्ति निम्नवत् है :–

(1)	ऐहार फीडर	–	16.32 घण्टे
(2)	पूरे डलई–1	–	15.52 घण्टे
(3)	पूरे डलई–2	–	16.18 घण्टे

पूरे डलई एवं ऐहार फीडरों को दिनांक 10–05–2017 को ही विद्युत वितरण उपखण्ड–रूदौली के कार्यक्षेत्र के अधीन किया जा चुका है।,

जनपद पीलीभीत में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत 5000 के लगभग.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्अभियोग धारा–138 ई0सी0 एक्ट पंजीकृत करवाये हैं, जिनका उद्देश्य मात्र यह है कि श्रेष्ठ वसूली दर्शाकर प्रशंसा का पात्र बना जा सके। गम्भीरता से विचारण का विषय यह है कि विद्युत विभाग पीलीभीत के अन्तर्गत कर्मचारियों के अभाव में न ही मीटर रीडिंग का निरीक्षण होता है और न ही समय से विलिंग हो पा रही है। बिल जमा करने की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामतः अनुमानित बिल काफी–काफी समय के उपरान्त भारी–भारी धनराशि के निर्गत किये जाते हैं, जिनका कनेक्शन काटा जाना दर्शाकर उपभोक्ता द्वारा जोड़ा जाना उल्लिखित कर कथित अभियोग पंजीकृत कराकर सरचार्ज सहित बकाया विद्युत बिल की भारी धनराशि एवं अभियोजन का शमन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि कर्मचारी का अभाव है। इस प्रकार विद्युत विभाग एवं पुलिस द्वारा उपभोक्ता का शोषण, उत्पीड़न एवं दमन किया जा रहा है।

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की कृपा की जाये।

आख्या–

अवगत कराना है कि बिलिंग से सम्बन्धित स्टाफ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बिलिंग का कार्य कार्यदायी संस्थानों से कराया जा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–पीलीभीत के आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों में एच0सी0एल0 बिलिंग सिस्टम पर आधारित एस0बी0एम0 मशीनों द्वारा एवं ग्रामीण ऑन लाइन व्यवस्था के तहत मौके पर ही फ्लयून्ट ग्रिड बिलिंग सिस्टम के माध्यम से एनड्रायड मोबाइल द्वारा बिल निकाल कर दिये जा रहे हैं, जिनका भुगतान भी अधिकांशतः उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

बकायेदार उपभोक्ताओं का संयोजन शासन की मंशा एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन में राजस्व वसूली हेतु विच्छेदित किये जा रहे हैं। कुछ समय के उपरान्त चेकिंग किये जाने पर बकाया पर विच्छेदित कनेक्शन, बिना अदायगी किये मौके पर जुड़े पाये जाने पर विद्युत अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के आधार पर अधिनियम की धारा–138 बी के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत कराये जाते हैं, क्योंकि विच्छेदित कनेक्शन जोड़कर उपभोक्ता ने आपराधिक कृत्य किया है।

अभियोग पंजीकृत कराना प्रशंसा का पात्र बनने जैसा कोई कृत्य नहीं है, बल्कि विभागीय प्रक्रिया पर आधारित है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासन के नीति के अन्तर्गत बकायेदारों को सरचार्ज में छूट दिये जाने की व्यवस्था भी चलायी गयी, ताकि अधिकांश उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।,

जनपद बदायूं के ग्राम नाधा, दफतोरी और बिनावर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

श्री ओमकार सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958.....

गन्ना विकास, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 17–05–2017 को निम्न सूचना दी गयी है :–

''आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बदायूं में पिछली सरकार में ग्राम नाधा, दफतोरी और बिनावर को ब्लाक बनाने की स्वीकृति हुई थी। परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह जनहित का विषय है उपरोक्त तीनों ब्लाकों को बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त तीन ब्लाक बनाये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समुचित भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण जनपद–बदायूं में नाधा, दबतोरी और बिनावर ब्लाकों को बनाया जाना सम्भव नहीं हो पर रहा है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बज कर 03 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 13 जुलाई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0–एल0 192 विधान सभा (369)–06–12–2017–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।